The House met at eleven of the Clock,
MR. CHAIRMAN in the Chair.

MEMBER SWORN

Shri Khekiho Zhimomi (Nagaland)

(Ends)

श्री एस.एस. अहलुवालिया : सर, आज पॉवर मिनिस्ट्री पर चर्चा होनी है और सुबह का क्वैश्चन भी पॉवर पर है, लेकिन चारों तरफ अँधेरा हो रहा है।

MR. CHAIRMAN: All right. ...(Interruptions)...

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: Sir, sometimes I have to prove that I am the Power Minister. That is the reason... ...(Interruptions)...

SHRI BALBIR PUNJ: You appear to be powerless today. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Ahluwalia Saheb, let us take the Questions. ...(Interruptions)...

SHRI S.S. AHLUWALIA: You must prove it through the magic wand. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Question No. 321.

DR. K. MALAISAMY: Sir, it is conceded from the reply of the hon. Minister for Power on earlier occasions that the country is in dearth of power. Despite several sources of power generation, the country is in shortage of power. That is conceded. If that be the case, I think, the alternative sources have to be found out. That is a must. In such a situation, as a student of Management, any single problem will have more than one solution. If a solution is to be found out, I mean, one must have various alternatives. In such a situation, my first supplementary is...

MR. CHAIRMAN: Please adhere to the question.

DR. K. MALAISAMY: In such a situation, I would like to know from the hon. Minister whether the Government is serious about renewable energy or wind mill energy or other alternative sources of power generation. If that be the case, what are all the measures taken and whether they are adequate and effective?

DR. FAROOQ ABDULLAH: Sir, first of all, I would like to congratulate his State of Tamil Nadu for being one of the top most States in the wind generation. At the same time, I would also like to inform this House that the total plan was, 11,000 MW of power to be generated by the Eleventh Plan. But, because of the global slowdown, it had to be brought down to 9,000 MW. But, we assure that we will be able to make up this deficit. What we have done is, we had earlier one type of subsidy that we used to give, which is now changed to generation based. We find that will bring new players. The hon. Member's first part of the question is on Gujarat State. Now, I would like to inform you that Gujarat is one of the States that

is going at a rapid rate in developing this wind energy. They had an international meeting in which 13 top players of the world came, who are now already signing MoUs with them. We hope that their target of 4,000 MW to be generated will be completed by the end of the Eleventh Plan.

(Contd. by 1b-kgg)

Kgg-sch/1b/11.05

DR. FAROOQ ABDULLAH (**contd.**): In other States also we have done a lot of studies through CMET which is also headquartered in Chennai. They have had a large study done. In 650 locations in the country they did their study. Out of which, 216 locations they found suitable and 38 are in Gujarat. When we gave generation-based incentive, I would like to place facts before hon. Members here, as far as how to get on rapidly with this is concerned, the Centre gave 80 per cent depreciation---10 years' tax holiday on income generated from power projects, concessional customs duties on import of specified components, and excise duty exemption on manufacture of wind electricity generators and parts thereof. This was the thing that was given as depreciation. Then we added what is called generation-based incentive to get more people to come into. We found that this is doing very well. Many of these people who are generating wind mills here wanted that the earlier incentive should continue till the Eleventh Plan was over. So, we gave them the options---whether they want to stay with the earlier benefit of depreciation or they would like to go into the new generation-based incentive. We hope, we will be able to achieve the results that the country wants to see from

wind. We hope, we will be able to do a lot more. I am sure, we will be able to achieve that.

MR. CHAIRMAN: Now, the second supplementary. Please stick to the question.

DR. K. MALAISAMY: The Minister has mentioned about Tamil Nadu. I am provoked to ask about Tamil Nadu. As far as the people coming from Tamil Nadu is concerned, they are undergoing the greatest strain on account of power cuts. 2-3 hours power cut is in existence in Tamil Nadu.

Coming to the question, in Tamil Nadu, the potentiality of wind power generation is about 645 MWs a year, as told by the Minister in his reply.

DR. FAROOQ ABDULLAH: 265 MW is the target for 2011. Otherwise, the potential in Tamil Nadu is 5,530 MW and installed capacity is 4,907 MW.

DR. K. MALAISAMY: Out of the total potentiality available in Tamil Nadu, how much has been exploited?

DR. FAROOQ ABDULLAH: I have told you already that already the installed capacity which is there is 4,907 MW and the target for this year, 2010-11, is 645 MW.

श्री रामदास अग्रवाल: सभापति महोदय, गैर पारम्परिक विद्युत उत्पादन में जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, वे सराहनीय हैं। मैं मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं, गुजरात गवर्नमैंट ने इन स्त्रोतों से 4000 मैगावाट पावर उत्पन्न करना तय किया है, लेकिन मुझे यह भी जानकारी मिली है कि इसके लिए गुजरात सरकार प्रति यूनिट 16 रुपये देगी। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब 16 रुपये प्रति यूनिट पर पावर परचेज़ की जाएगी, उसके बाद कंज्यूमर चाहे इंडस्ट्री हो या होम एप्लीकेशंस हों, उनसे हम क्या रेट चार्ज करेंगे? यदि सैंट्रल गवर्नमैंट

अथवा स्टेट गवर्नमैंट इसमें कुछ सब्सिडी दे रही है, तो आगे के लिए उन्होंने क्या प्रावधान किए हैं, ताकि पावर की यह जो इंडस्ट्री लगने वाली है, इसको बाद में जाकर रास्ते में कहीं टूटना, भटकना या बर्बाद होना न पड़े?

1c/psv-kls पर आगे

-SCH/PSV-KLS/1C/11.10

डा0 फारूख अब्दुल्ला: सर, इनका सवाल है कि गुजरात गवर्नमेंट ने इसका रेट 16 रुपए रखा है और यह रेट बहुत ज्यादा है। आपके कहने का मकसद यही है कि यह लोगों पर भारी पड़ेगा, लेकिन रेट क्या होना चाहिए, यह फैसला स्टेट गवर्नमेंट, electricity board के साथ बैठ कर करती है। इस बारे में बात करने के लिए अब हम स्टेट गवर्नमेंट के पास जाने वाले हैं और हमारी यही कोशिश रहेगी कि power generation में हम लोगों को इस तरीके से काम करना चाहिए कि लोगों पर बोझ न पड़े। इसके लिए हमें कोई-न-कोई तरीका ढूँढ़ना पड़ेगा कि हम उनको इस मुद्दे पर लाएँ ताकि आज जो बिजली पैदा की जाती है उसका ज्यादा-से-ज्यादा लोग इस्तेमाल कर सकें। इस प्रकार, हम उनसे बात करेंगे और इसके लिए कोई रास्ता निकालेंगे कि हमें ऐसी क्या सुविधाएँ करनी पड़ेंगी कि इसका रेट कॉमन आदमी पर कम पड़े।

श्री रामदास अग्रवाल: सर, ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: नहीं, सिर्फ एक सवाल। प्लीज़ ...(व्यवधान)...

श्री रामदास अग्रवाल: महोदय, उन्होंने मेरे जिस सवाल का जवाब दिया, उसमें मैंने यह पूछा है कि ऐसे power stations जो आज तक लग चुके हैं, उनकी cost 16-17 रुपए आती है ...(व्यवधान)... उन्होंने अब तक क्या प्रावधान किया है ...(व्यवधान)... या नहीं किया है और आगे यह क्या करेंगे, मैं यह जानना चाहता हूँ। ...(व्यवधान)...

डा0 फारूख अब्दुल्ला: यह wind energy का नहीं है। ...(व्यवधान)... यह wind energy का नहीं है। ...(व्यवधान)... Wind energy पर ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: We cannot have a discussion on it. ...(Interruptions)...

डा0 फारूख अब्दुल्ला: सर, wind energy पर रेट 3.56 रुपए है। Solar energy पर करीब 16 रुपए तय किया गया है, मगर solar energy का सवाल अलग है। Wind energy पर 3 रुपए 56 पैसे का रेट रखा गया है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि देश में हवा से बिजली पैदा करने की जितनी क्षमता उपलब्ध है उसको देखते हुए और यहाँ के मौसम को देखते हुए बहुत से private entrepreneurs ने इस मामले में पहले प्रोजेक्ट्स बनाए। इसमें यह हुआ है कि उन्होंने जो बिजली उत्पादन की, उसे उन्हें राज्य के electricity board को बेचनी पड़ती है। एक जानकारी के अनुसार, private entrepreneurs द्वारा राज्य electricity boards को जितनी बिजली बेची गई, उसकी पेमेंट उनको कई वर्षों तक नहीं मिली जिसके कारण बहुत से प्रोजेक्ट्स फेल हो गए और जो नए प्रोजेक्ट्स लगने वाले थे, उनमें entrepreneurs इसी कारण discouraged हुए।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या आपने इस बात की जाँच कराकर देखा है कि private entrepreneurs द्वारा लगाए गए ऐसे कितने प्रोजेक्ट्स हैं, जो इस कारण से फेल हुए कि राज्य बिजली बोर्ड्स ने उनको समय पर पैसे की पेमेंट नहीं की? इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या आपने राज्य बिजली बोर्ड्स के साथ या राज्यों के बिजली मंत्रियों के साथ मिल कर कोई पहल की है? यदि हाँ, तो उस सम्बन्ध में क्या निर्णय हुए हैं, कृपया बताने का कष्ट करें।

डा0 फारूख अब्दुल्ला: सर, ये जो प्रोजेक्ट्स लगते हैं, उन्हें basically स्टेट्स लगाती हैं और उन्हें ही यह बिजली खरीदनी पड़ती है। हमारे पास कोई भी ऐसी बात नहीं आई है कि कहीं

पर non payment हुई हो। अगर माननीय सदस्य के पास ऐसी कोई बात आई हो तो उसे हमारे सामने लाएँ, हम उसका हल निकालने की कोशिश करेंगे।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: सभापति महोदय, मैंने केवल इतना ही कहा कि क्या आपने इस बात की कोई जांच-पड़ताल की है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स कितने हैं ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: इन्होंने आपको जवाब दे दिया है।

डा0 फारूख अब्दुल्ला: मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई है तो हम जाँच-पड़ताल किसकी करें? पहले यह हमारे पास आए तब तो हम उसकी जाँच-पड़ताल करें। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि जिन्होंने इनके पास यह बात रखी है, अगर यह उसे हमारी मिनिस्ट्री में भेजेंगे तो हम उसी वक्त यह देखेंगे कि उसकी पेमेंट नहीं हो पाने की क्या वजह है।

SHRI Y.P. TRIVEDI: Sir, the hon. Minister is talking about alternative sources of energy. Wind power is one source of energy, solar power is another source of energy and some people are trying to get energy from tidal waves. Will the hon. Minister tell us whether wind power is cheaper or solar power is cheaper?

DR. FAROOQ ABDULLAH: Sir, according to the figures that we have, solar power is definitely expensive whereas wind power is cheaper because solar power costs Rs.17 to Rs.18 per unit whereas wind energy costs Rs.3.56 per unit. So, solar power is expensive. At the same time, as far as the other question regarding tidal wave is concerned, up to this time no study has been done.

(Contd. by 1D/SSS)

Q. No. 321(Contd.)

DR. FAROOQ ABDULLAH (CONTD.): But now, the C-MET is looking into one of the projects to see whether this tidal wave can be also be utilized in our country and that is being studied. We are also looking into that tidal wave that you have mentioned.

(Ends)

श्री ईश्वर सिंह: सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से मेरा यह प्रश्न है कि क्या सरकार ने सेन्ट्रल पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा ऐसा कोई सर्वे कराया है कि देश में हर साल कितना इलेक्ट्रोनिक वेस्ट पैदा हो रहा है और उससे पर्यावरण और स्वास्थ्य पर कितना असर हो रहा है? इसके साथ ही मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या यूनाइटेड नेशंस एन्वायरनमेंट प्रोग्राम ने भारत में होने वाले इलेक्ट्रोनिक वेस्ट पर कोई रिपोर्ट दी है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, there are a number of questions in the hon. Member's opening remarks. It is true that surveys have been done on the generation of electronic waves. The Central Pollution Control Board has carried out a survey and the results of that survey are detailed in the statement that I have laid on the Table of the House. There has been another survey that was done by the Manufacturer's Association of Information Technology which is an industry body and they have made some estimates on the amount of e-waste that is generated. While the precise numbers may vary I think, the general conclusion that has been reached is that e-waste is becoming an increasingly important challenge for the country to deal with because we are becoming more and more of an IT literate society. We use computers, mobile phones and other such electronic devices. Therefore, we have to take much more precautionary measures in so far as the use of e-waste is concerned. On the health point, that the hon. Member has raised, electronic waste has both toxic waste as well as useful materials. We can extract gold, silver, plastic, glass, steel from electronic waste. At the same time, electronic waste also has lead, cadmium, arsenal,

mercury which is hazardous for human health. So, the real challenge for us is to put in place systems that will re-cycle the electronic waste, that would remove the toxic wastes that are harmful for the human environment and the human body and enable the re-cycling of useful materials so that employment is generated and country earns foreign exchange as well.

श्री ईश्वर सिंह: सर, माननीय मंत्री महोदय ने इलेक्ट्रोनिक वेस्ट से क्या लाभ और क्या हानि है, ये दोनों चीजें बतायी हैं। मैं जो पूछना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोनिक वेस्ट का proper disposal करने के लिए क्या नीति बनायी गयी है, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। मैं आपके नोट में यह भी लाना चाहता हूँ कि वर्ष 2020 तक जैसा कि यू.एन.ई.पी. की रिपोर्ट आयी है, उसमें जो चेतावनी दी गयी है कि 2020 तक कम्प्यूटर से होने वाला इलेक्ट्रोनिक वेस्ट 500 प्रतिशत बढ़ जाएगा, टेलीविजन और रेफ्रिजरेटर से होने वाला इलेक्ट्रोनिक वेस्ट triple हो जाएगा और मोबाइल फोन से होने वाला इलेक्ट्रोनिक वेस्ट 18 गुना बढ़ जाएगा। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि इसके बारे में राज्य सरकारों से क्या विचार-विमर्श किया गया है? क्योंकि इलेक्ट्रोनिक वेस्ट से पर्यावरण और स्वास्थ्य की क्या हानि हो रही है, इसके बारे में राज्य सरकारों को तो पता ही नहीं लगता और न ही यह किसी कमेटी और आम आदमी की जानकारी में है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि सरकार इसके बारे में क्या कर रही है?

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, I would like to make three specific responses to the hon. Member's questions. Number one, for the first time, the Government is coming out with a separate set of rules for managing e-wastes. Our Ministry has finalized these rules. These are being vetted by the Law Ministry and by the 15th of May I expect to make public for the first time a set of regulations for the management of e-waste. So far, we have not had a separate set of regulations.

They are part of the hazardous waste management rules of 2008 and this is going to be a major step forward. The second important step that we are taking is to put in place a financing mechanism to set up separate facilities for treating storage and disposal of electronic wastes. Twenty-five per cent of the funds will be provided by the Central Government.

(Contd. By NBR/1E)

-SSS/NBR-AKA/1E/11.20.

SHRI JAIRAM RAMESH (CONTD.): Sir, 25 per cent of the funds will be provided by the Central Government, 25 per cent of the funds will be provided by the State Government and the remaining 50 per cent funds will come from the entrepreneur. So, this is on PPP mode as far as setting up of treatment, storage and disposal facilities for e-waste is concerned. There are already 14 such facilities in the country. But, for the first time, the Government of India is taking a step to, actually, finance these facilities.

Sir, my third and the most important point which the hon. Member has raised is this. Today, over 85 per cent to 90 per cent recycling facilities are in the information/unorganized sector over which the Central Government or the State Government have virtually no control. These are illegal facilities in more often than not. I can give you examples of Moradabad and Seelampur which is very close to Delhi. These are all facilities which are entirely in the informal sector over which the Government have no control. The CPCB has virtually no control. The SPCP, if at all, has to take the primary initiative. We will take this up, considering the seriousness of the situation. We will take this up with the State Governments.

But the real answer lies in making sure that the unorganized sector becomes a much more organized sector in terms of reuse and recycling. As along as it remains in informal, I am afraid, there is very little we can do, given the fact that this is generating huge amounts of potential and no Government would like to stop this activity from continuing.

DR. (SHRIMATI) NAJMA A. HEPTULLA: Sir, the hon. Minister touched very lightly the point of waste disposal. We have examined it in great detail. The new hazardous waste disposal, as the hon. Minister said, rules are going to come. But, Sir, the whole problem is that the waste disposal is not under the Environment Ministry either at the Centre or at the State level. It is the local Municipality which takes care of the waste disposal. In Municipality or the Corporation there is no specialized authority which can differentiate between hazardous waste and normal waste. Sir, even the biomedical waste is being thrown out in Delhi. And, we have read it in the newspaper even today about the nuclear waste. So, these are very serious matters. Mr. Minister, rules are now going to effect. Since we have the federal system, the State Governments have to be empowered and educated in disposal of hazardous waste.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, I would like to make a small correction to what the hon. Member has just said. The Ministry of Environment and Forests is fully empowered, by law, to deal with hazardous wastes. Hazardous Waste Rules have been notified in the year 2008 and hazardous waste covers biomedical waste as well. It is not true to say that the Ministry has no power.

DR. (SHRIMATI) NAJMA A. HEPTULLA: But, it is not doing anything.

SHRI JAIRAM RAMESH: Madam, I am trying to explain the facts of the case. Municipal solid waste is the responsibility of the Municipalities. But, hazardous wastes which is very clearly defined by law is the responsibility of the Ministry of Environment and Forests for which we have a detailed set of rules and regulations which are being implemented. The hon. Member mentioned about Cobalt-60 incident that has taken place in New Delhi just a couple of days ago. This is not covered by Hazardous Waste Management Rules. This is a radioactive waste and radioactive waste is covered by the Atomic Energy Act.

श्री बृजभूषण तिवारी : सभापति महोदय, मंत्री जी ने अभी जो जवाब दिया है, उसमें उन्होंने यह बात स्वीकार की कि जो रिसाइकलिंग यूनिट्स हैं, वे ज्यादातर अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर में हैं और दूसरी तरफ ये जो वैस्ट हैं, ये इतने खतरनाक हैं कि इनके बहुत दुष्परिणाम लोगों के ऊपर पड़ रहे हैं। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि आपने जो यह कानून बनाया है, इस कानून के तहत आपने अब तक कितने यूनिट्स पर कार्रवाई की है और उसमें कितने लोगों को सजा मिली है?

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, I can answer this question straight. No action has been taken either by the Centre or by the State against any unit in the informal sector. By law, only registered units can come up for reuse and recycling. But, we all know the reality of this country. The reality of this country is, because of the enormous pressure to generate employment you have a mushrooming of units in the informal sector. I have personally seen, for example, in Dharavi, in Mumbai, a flourishing recycling industry against which no Government has had the courage

to take action, because you would be destroying lakhs and lakhs of livelihood opportunities.

(CONTD. BY USY "1F")

NB/USY/1F/11.25

SHRI JAIRAM RAMESH (CONTD.): So, Sir, the answer lies in expanding the proportion of organized sector re-cycling and re-use facilities, the answer lies in creating incentives for the unorganized sector to come under organized sector. I agree with the hon. Member if we can take solitary deterrent action against a couple of illegal units in the informal sector, I think, the message will go. I have already instructed the Central Pollution Control Board to take such action. And, I would like to request the hon. Members to support me when there could be a backlash when the Central Pollution Control Board actually begins to take such actions, particularly in places, like, Moradabad.

SHRI P. RAJEEVE: Sir, there are so many reports regarding the dumping of e-wastes, outdated electronic equipments and cheaper electronic equipments which have many hazardous components. So, I would like to know whether the Ministry of Environment is aware of that or not; and whether the Ministry has allowed the dumping of e-wastes and outdated electronic equipments in our country.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, we allow import of e-wastes under strict regulations. I would like to inform the hon. Member that we not only import the e-wastes, but we also export the e-wastes. We are not just an importer of e-

wastes, we also export e-wastes to European countries which, then, extract gold, silver and other useful materials. So, India is both, like many countries, an importer of e-wastes and an exporter of e-wastes under strict regulated conditions. There have been some estimates which show that about 50,000 tonnes of e-wastes have come, which you may classify as illegal or dumped wastes. No precise estimates are there, but I would like to assure the hon. Member that when the new rules are going to be notified very soon, he will find that the Ministry of Environment and Forests has taken a very clear and tough stand against the import of electronic equipments. There is always a tendency in our country to import second hand equipments, which has already been used, and that opens the doors for more and more e-wastes to come into this country. The rules, in this regard, are going to be very clear. Personally, Sir, I am against the import of computers and electronic equipments in the name of charity, which had already been used for a long time in the developed countries. It, then, becomes e-wastes in our country. I think, as a country, we must be very clear as to what we will allow to be imported and what we will ban for import.

(Ends)

श्री मोहम्मद अली खान : सभापति जी, मंत्री जी ने काफी डिटेल में फूड पार्क और फूड इंडस्ट्री के बारे में बताया है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि NIFTEM का जो इंस्टीट्यूट है, क्या मरकज़ी सरकार की ऐसी कोई स्कीम है कि आंध्र प्रदेश में, खासकर तेलंगाना और रायलसीमा में इसकी ब्रांच खोली जाए?

جناب محمد علی خان : سبھا پتی، منتری جی نے کافی ڈٹیل میں فوڈ پارک اور فوڈ انڈسٹری کے بارے میں بتایا ہے۔ میں منتری جی سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ NIFTEM کا جو انسٹی ٹیوشن ہے، کیا مرکزی سرکار کی ایسی کوئی اسکیم ہے کہ آندھرا پردیش میں، خاص کر تلنگانہ اور رائل سیما میں اس کی برانچ کھولی جائے؟

श्री सुबोध कांत सहाय : सभापति जी, यह NIFTEM का जो इंस्टीट्यूट है, State of Art point of view से देश में ऐसा केवल एक इंस्टीट्यूट बनने जा रहा है, जो अगले सितंबर से चालू होने वाला है। दक्षिण भारत में तंजावूर में हमारा एक दूसरा इंस्टीट्यूट है, उसकी branches वगैरह हम खोलते हैं, लेकिन चूंकि NIFTEM का इंस्टीट्यूट अभी खुलने वाला है, इसलिए तात्कालिक रूप से इसकी ब्रांच खोलने का कोई विचार नहीं है, लेकिन वहां पर PPRC का जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट है, यदि रायलसीमा की तरफ उसकी ब्रांच खोलने की मांग आएगी, तो हम इसकी ब्रांच अवश्य वहां खोल सकते हैं।

श्री मोहम्मद अली खान : सभापति जी, मेरा दूसरा सवाल यह है कि मरकज़ी सरकार का फूड इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का जो मकसद है, वह यह है कि इसका डॉयरेक्ट फायदा किसानों को हो और दूसरा, अवाम को इसका फायदा पहुंचे।

1G/VNK पर क्रमश:

-NB/VNK-PK/1g/11:30

श्री मोहम्मद अली खान (क्रमागत): क्योंकि तीन महीने से मुसलस्ल एग्रीकल्चर की कमिटी में डिसकस हो रहा है, लेकिन तमाम मेम्बरों और अराकीन की राय है कि मरकज़ी सरकार की जो प्लानिंग थी कि किसानों को और आवाम को इससे फायदा पहुंचना चाहिए, लेकिन इसके

बजाए जो बीच के आदमी हैं, उनको इसका फायदा पहुंच रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इन तमाम बातों को सामने रखने के बाद और स्टेंडिंग कमिटी के नजरिए को सामने रखने के बाद क्या मंत्री जी किसी मुकाम पर पहुंचे हैं या किसी पॉलिसी के ऊपर खड़े हैं कि इन दो बातों को मद्देनजर रखते हुए बीच में जो लोगों की साझेदारी है, उनको खत्म करेंगे और डायरेक्ट किसानों को और आवाम को फायदा पहुंचाएंगे?

جناب محمد علی خان : سبھا پتی جی، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ مرکزی سرکار کا فوڈ انڈسٹری کو بڑھاوا دینے کا جو مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا ڈائریکٹ فائدہ کسانوں کو ہو اور دوسرا، عوام کو اس کا فائدہ پہنچے۔ کیوں کہ تین مہینوں سے مسلسل ایگریکلچر کی کمیٹی میں ڈسکس ہو رہا ہے، لیکن تمام ممبروں اور اراکین کی رائے ہے کہ مرکزی سرکار کی جو پلاننگ تھی کہ کسانوں کو اور عوام کو اس سے فائدہ پہنچنا چاہئے، لیکن اس کے بجائے جو بیچ کے آدمی ہیں، ان کو اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ میں مانّئے منتری جی سے جاننا چاہتا ہوں کہ ان تمام باتوں کو سامنے رکھنے کے بعد اور اسٹینڈنگ کمیٹی کے نظریے کو سامنے رکھنے کے بعد کیا منتری جی کسی مقام پر پہنچے ہیں یا کسی پالیسی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں کہ ان دو باتوں کو مدّنظر رکھتے ہوئے بیچ میں جو لوگوں کی ساجھیداری ہے، ان کو ختم کریں گے اور ڈائریکٹ کسانوں کو اور عوام کو فائدہ پہنچائیں گے؟

श्री सुबोध कांत सहाय: निश्चित तौर पर हमारी भी यही कोशिश है और इस मंत्रालय की जो पूरी सोच है, वह भी इसी दृष्टिकोण पर है कि कैसे हम market driven farming के लिए किसानों को मौका दें। यह तभी संभव है, जब Agriculture Produce Marketing Act जो राज्य सरकार के नियम हैं और दूसरे नियम भी हैं, जो किसानों के खेत में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए थर्ड पार्टी को अवसर देगा, अभी जो विधि है, उसके तहत किसाना पैदा करता है और एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में ले जाकर उसको बेचना पड़ता है और कोई भी थर्ड पार्टी किसानों के खेत में निवेश नहीं कर सकती है। अगर राज्य सरकारें अपनी नीति बदले, जिसके लिए केन्द्र सरकार लगातार pursue कर रही है कि एपीएमसी एक्ट खत्म कीजिए और Co-operative Farming शुरू कराइए या Contract Farming शुरू कराइए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसमें बिचौलिया अपना काम करते हैं और अगर ऐसा हो जाएगा तो इंडस्ट्री

डायरेक्ट किसान के पास जाएगा। उसको अच्छा बीज देगा, अच्छी technology देगा, long term water management देगा ..(व्यवधान)..

श्री विक्रम वर्माः National Development Council में ..(व्यवधान).. आपने किसानों को बचाने के लिए ...(व्यवधान)..

MR. CHAIRMAN: Please, Please ..(Interruptions).. Please do not interrupt. ..(Interruptions)..

श्री विक्रम वर्माः महोदय ..(व्यवधान)..

श्री सभापतिः कृपया आप बैठ जाइए। अभी आपकी बारी नहीं आई है ..(व्यवधान)..

श्री विक्रम वर्माः महोदय ..(व्यवधान)..

MR. CHAIRMAN: This is not fair. ..(Interruptions).. Please, please.

श्री सुबोध कांत सहायः सभापति महोदय, मैं जो कह रहा हूँ, यह ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना जब पास हो रही थी, तब National Development Council के फैसले में यह बात जोड़ी गई थी कि किसानों को बाजारोन्मुखी खेती करने का जब तक अवसर नहीं दिया जाएगा, तब तक किसान आर्थिक रूप से इस लायक नहीं होगा और यह राज्य सरकार के नियम के ऊपर आधारित है। कोई नया निवेश किसानों के खेत में नहीं हो रहा है। किसान इतना कमा नहीं रहा है कि वह फिर से अपने खेत में re-invest करे, इसीलिए जब एपीएमसी एक्ट को खत्म किया जाएगा, तभी बिचौलिए से जान बचायी जा सकती है और इस इंडस्ट्री का भविष्य तभी बन सकता है, जो value addition of processing level को बढ़ाएगी। जिस दिन किसान की उपज raw material की तरह ट्रीट होने लगेगी, उस दिन किसान का आर्थिक स्वरूप बदलेगा और उसकी bargaining capacity बढ़ेगी।

श्री रवि शंकर प्रसादः सभापति महोदय, मैंने माननीय मंत्री के विस्तृत उत्तर को बहुत ध्यान से पढ़ा है, इस प्रश्न में उनके विभाग के उत्पादकों के भूमंडलीय प्रतिस्पर्द्धा के स्वरूप कितने

आगे बढ़ा रहे हैं, उसकी चिंता की है। उत्तर के दूसरे पेज के पहले पैराग्राफ में देखें, तो आप भी समझते होंगे कि सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि किसानों का उत्पाद सुरक्षित रहे। आज गेहूं सड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं और गेहूं की किल्लत हो रही है। आपने जो कोल चेन की बात कही है, मुझे देखकर बहुत चिंता हुई कि आपका यह एक अच्छा प्रयोग है, लेकिन 2008-09 में बड़े-बड़े प्रदेश, जैसे बिहार, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, में सिर्फ दस कोल चेन बनाए गए हैं। मेरा मंत्री महोदय से सीधा सवाल है कि यह जो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का एक अच्छा प्रयोजन है, इसमें गति इतनी धीमी क्यों है, इसका कारण क्या है और यह तेजी से हो, इसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं?

(1h/MP पर आगे)

MP-PB/1H/11.35

श्री सुबोध कांत सहाय : महोदय, मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं कि cold chain supply chain का बहुत बड़ा missing part है, जिससे किसानों की उपज की self-life कम हो जाती है। रहा सवाल कि हमारे मंत्रालय की जो क्षमता है, उस क्षमता के मुताबिक कैसे integrated cold chain हैं, तो पहले जो cold chain होते थे, वे प्याज-आलू के होते थे, लेकिन integrated cold chain के लिए हम दस करोड़ रुपए दे रहे हैं, जो from farm gate to market या processing hub तक उसको ले जाए, उसकी self-life बची रहे और किसानों की उपज को दुनिया के बाज़ार से जोड़ने का काम भी यही करेगा। जो विभिन्न मंत्रालयों की योजनाएं हैं, एग्रीकल्चर की भी कुछ योजना है, APEDA की कोई योजना है, इसलिए cold chain की हमारी कोशिश है, लेकिन हमारे मंत्रालय की जो क्षमता है, जो हमें दिया गया था, वह हमने पूरा किया है। ...(व्यवधान)...

श्री रवि शंकर प्रसाद : आपकी सीमित क्षमता है, स्वीकार कर लिया?

श्री सुबोध कांत सहाय : मैं मंत्रालय की बात कह रहा हूं। जो फैक्ट है, हर मंत्रालय बजट से ....(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Please.

श्री रवि शंकर प्रसाद : मंत्री जी, आलू सड़ रहा है, किसानों का गेहूं सड़ रहा है !

श्री सुबोध कांत सहाय : किसानों के गेहूं को कोल्ड स्टोरेज में रखने की जरूरत नहीं है। उसके लिए FCI का godown चाहिए।

श्री रवि शंकर प्रसाद : उसमें आलू, टमाटर सब रखा जाता है।

श्री तारिक अनवर : सभापति जी, मंत्री जी के उत्तर में यह बताया गया है कि Number of projects approved and financial assistance provided during the years 2007-08, 2008-09 and 2009-10, State-wise under the scheme of Setting up/Technology Upgradation/Establishment/Modernization of FPIs - इसमें मंत्री जी ने विस्तार से जो जवाब दिया है और जो statewise data दिया है, उसमें खास तौर पर मेरा ध्यान बिहार की ओर गया है कि दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार की क्या स्थिति है? महोदय, बिहार के बंटवारे के बाद जो बिहार राज्य बचा है, वह मूल रूप से कृषि पर आधारित है, लेकिन जो data यहां दिया गया है, उसके अनुसार.. यहां तक कि जो हमारा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश है, वहां भी 2007-08 में 11 लाख 23 हज़ार रुपए दिए गए थे और 63 प्रोजेक्ट्स approve किए गए, लेकिन बिहार में मात्र 5 approve किए गए, 2008 के मात्र 2 और 2009-10 के 2, यानी मात्र 44 लाख दिए गए। महोदय, दूसरे राज्यों की जो फिगर्स मैंने देखी हैं, उनकी तुलना में बिहार बहुत ही पीछे है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर इसके क्या मापदंड हैं? क्या बिहार सरकार की उदासीनता है और वहां से कोई स्कीम नहीं आ रही है या और कोई वजह है, वह मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री सुबोध कांत सहाय : सभापति महोदय, basically हमारा यह लगातार प्रयास है कि राज्य सरकारें एक separate Food Process Industrial Policy बनाएं। यह perishable industry है और perishable industry में investor की last choice होती है। कैसे इसको बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए हमने सारी राज्य सरकारों के लोगों को बुलाया और कोशिश की कि उनको aware किया जाए। उसके लिए हम बहुत awareness campaigns करते हैं, लेकिन बहुत राज्यों में Food Process Industrial Policy नहीं बनी है, जबकि केंद्र सरकार ने इसको पूरी तक tax free कर दिया है, इस पर zero taxation कर दिया है - Central Excise, Import Duty, Export Facility - यह सारा हमने किया है। महोदय, मैं कह सकता हूं कि जिन-जिन राज्य सरकारों ने, जैसे दक्षिण भारत की राज्य सरकारों ने इस पर काफी ध्यान दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान - ये सारे राज्य हैं, जिनको इसके लिए जागरूक होना होगा। अगर राज्य सरकारें हमारे पास आती हैं, तो जो proposal आते हैं, उनको हम क्लीयर कर रहे हैं। केंद्र सरकार कुछ नहीं करती है, हमारा रोल एक promoter, facilitator का है, जो हम कर रहे हैं।

(1J/SKC पर आगे)

SKC-SC/1J/11.40

SHRI MOINUL HASSAN: Sir, it was reported that the Government would establish food processing industries through PPP mode in different parts of the country. If that be so, may I know from the hon. Minister, what is the experience at present? What type of response did the Government receive? How many food processing industries under PPP mode are proposed to be established in different parts of the country in this financial year?

SHRI SUBODH KANT SAHAY: We have given details as to how many such industries have been established; it is very much there in our detailed reply. As I told you, there has been a lot of growth in this sector. Even during the period of recession, there has been a growth rate of 14 plus. So, you could say that this is a very lucrative sector for investment. Even our FDI has come to 200 per cent as compared to last year.

SHRI MOINUL HASSAN: The question is: how many units have been set up under PPP mode?

SHRI SUBODH KANT SAHAY: We do not have the PPP mode in such areas. We only have mega food parks in the SPV mode, the Special Purpose Vehicle mode. If three or four companies come together, we provide them with a backward and forward integration project called the mega food park and we provide Rs. 50 crores as grant from our side.

SHRI SUBODH KANT SAHAY: How many are there in PPP mode? (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please, do not interrupt.

SHRI SUBODH KANT SAHAY: Here, there is no PPP mode. We have initiated ten food parks and out of the ten, six are already being developed while four are under process.

(Ends)

SHRI N.K. SINGH: Sir, the hon. Minister has, in the annexure, given details of the coal-based power plants which are to be progressively retired. In retrofitting these plants, what special steps is the Ministry contemplating to ensure that the future power stations are really environment-friendly, that technologies are adopted for Carbon sequestering and that the Carbon-di-oxide emissions from future coal-based power plants are minimized?

SHRI BHARATSINH SOLANKI: Sir, hon. Member thinks what he desires. Almost 35 plants are going to be retired in the 11th Five Year Plan. He is concerned about the future power plants and Carbon emission. That is why Government of India has come up with a policy of super critical plants. It is a new technology with five collaborations with indigenous products. Also, there is our innovation and modernization programme through which we are trying to reduce Carbon emissions.

श्रीमती माया सिंह : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहती हूं कि जो कोयला आधारित विद्युत इकाइयां हैं, जिन प्रदेशों में वे इकाइयां पूर्व से चल रही हैं, उन प्रदेशों में कोयले का उत्पादन होता है। इसके बावजूद भी उन प्रदेशों को कोयला अन्य प्रदेशों से आयात करना पड़ता है और उन्हें उनकी मांग के अनुसार कोयला उपलब्ध नहीं कराया जाता। जो कोयला उपलब्ध कराया भी जाता है, वह अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, चूरा होता है। मैं मंत्री जी से मध्य प्रदेश के बारे में जानना चाहती हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार ने, जो कोयला आधारित विद्युत इकाइयां चल रही हैं, उनके लिए कोयले की जो मांग की है, उस मांग के अनुसार क्या उन्हें कोयला उपलब्ध कराया जाता है? इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में जो

कोयले की खदानें हैं, भंडार हैं, क्या वे वहीं से कोयला लेते हैं या उन्हें अन्य प्रदेशों से आयात करने के लिए कहा जाता है?

श्री भरतसिंह सोलंकी : सभापति महोदय, माननीय सदस्या ने जो कहा है, कोयले का डिस्ट्रीब्यूशन, कोल लिंकेज - जो डिमांड आती है, जो डेवलपर आते हैं, उनके क्राइटेरिया को देखकर, तय करके, पूरे हिन्दुस्तान में जितने भी नए यूनिट आते हैं, उन यूनिट्स को कैसे दिया जाए, वह सब हमारी पॉवर मिनिस्टरी, कोल मिनिस्टरी के साथ मिलकर तय करती है। उस हिसाब से चाहे किसी राज्य में कोयला हो या न हो - पॉवर जेनरेशन पूरे देश के लिए हम करते हैं।

(1के-एमसीएम पर क्रमशः)

SC-MCM/HK/1K/11-45

श्री भरतसिंह सोलंकी (क्रमागत) : उस हिसाब से वह क्राइटेरिया करके हम तय करते हैं। हालांकि देश में कोयले का उत्पादन कम होने की वजह से शॉर्टेज है, इसलिए उन इकाइयों को कोयला इंपोर्ट करने के लिए हम उनको आश्वासित करते हैं।

श्रीमती माया सिंह : सर, मैंने मंत्री जी से पूछा था कि जिन प्रदेशों से आप कोयला आयात करते हैं उन प्रदेशों को आप प्राथमिकता देंगे कि वे अपने ही प्रदेश से अपनी जरूरत के मुताबिक कोयला ले सकें? सर, वहां पूर्व में विद्युत इकाइयां चल रही हैं, इसलिए मैंने मंत्री जी से जानना चाहा था।

श्री भरतसिंह सोलंकी : कोल का लिंकेज तय किया जाता है और उसके लिए It is made with coal companies depending upon the requirement of the States and the utilities. जितनी इकाइयां हैं उसके लिए कितना चाहिए उसको proportionate पॉवर मिनिस्ट्री लिंकेज तय करती है, उसके बाद कोल मिनिस्ट्री यह तय करती है।

श्रीमती माया सिंह : सर, मंत्री जी लिखा हुआ ही जवाब दे रहे हैं। मैं जो पूछ रही हूं उसका जवाब नहीं दे रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Please write to the Minister.

SHRI RAHUL BAJAJ: Sir, the question, of course, assures the supply of coal to the coal-based power units. At the end of the reply it has been mentioned by the Power Ministry that there are indications available to them that there is a shortage of coal and there is a gap between demand and supply. Through you, I would like to ask the Power Minister as to what are these indications. Coal is one industrial raw material for which -subject to quality content about ash -- we have enough laws in our country. If even that item has to be imported -- we are importing everything else -- what is this rigid excessive Government control on these coal mines? Are some undesirable elements in certain parts of the country controlling these coal mines? Can't we do something to make enough coal available in this country?

SHRI BHARATSINH SOLANKI: Mr. Chairman, Sir, the Ministry of Power recommends the requirement of coal to the Ministry of Coal. Then the allocation is done by the Ministry of Coal. The Ministry of Coal is being insisted for more coal to be supplied. For long, efforts are being made to import the coal and we request the Ministry of Coal also for this. The question raised by the hon. Member pertains to the Coal Ministry. So, I think the Coal Ministry could answer better.

(Ends)

श्री नन्द कुमार साय : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने मधु संग्रह, गम कराया, महुआ के फूल आदि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी दी है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रशिक्षण केन्द्रों में कितनी-कितनी राशि खर्च की गई है और यह खर्च किस-किस प्रकार से किया गया है, इसका पूरा ब्यौरा दें?

श्री तुषारभाई चौधरी : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य जो जानना चाहते हैं उसमें हम लोगों ने करीबन हनी कलेक्शन के लिए 12,147 और गम पिकर्स के लिए 15,300 और दौना पत्तल के लिए 1,240 हैं। इन सबको मिलाकर इसमें सब श्रेणियों में 6 लाख 36 हजार रुपए हमने छत्तीसगढ़ में ट्रेनिंग देने के लिए खर्च किया है।

श्री नन्द कुमार साय : मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपने जो प्रशिक्षण केन्द्र छत्तीस गढ़ में स्थापित किए और इसमें 6 लाख 36 हजार खर्च किए हैं, इसमें से जो लाभांवित हुए उनको कितनी राशि का लाभ मिला है और किस प्रकार का लाभ मिला है, यह जानकारी आप देने का कष्ट करें। माननीय सभापति, मैं यह भी जानना चाहता हू कि आपने उत्तर दिया है कि तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना नहीं की गई है। तो क्या भविष्य में तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के संबंध में सरकार के पास कोई योजना है?

(1L/GS पर क्रमशः)

श्री नन्द कुमार साय (क्रमागत) : छत्तीसगढ़ में लाभान्वितों की राशि का किस प्रकार से...।

श्री सभापति : आपका सवाल हो गया है।

श्री तुषारभाई चौधरी : सर, जहां तक तकनीकी शिक्षण के लिए इंस्टीट्यूट की स्थापना का सवाल है, यह सब minor forest produce gatherers जो होते हैं, वे बहुत scattered रहते हैं। उनको एक जगह पर लाकर ट्रेनिंग देना, यह बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए हम तीन तरह की ट्रेनिंग देते हैं। हम इसके लिए मास्टर ट्रेनर तैयार कर रहे हैं, जो गांव में जाकर

minor forest produce gatherers को ट्रेनिंग देंगे और वे लोग वहीं पर ट्रेनिंग लेकर के इम्प्रूवमेंट कर सकें, क्वालिटी इम्प्रूव कर सकें, क्वांटिटी इम्प्रूव कर सकें और इको-फ्रेंडली मैनर में अच्छी तरह से काम कर सकें। इस प्रकार से हमारा मंत्रालय उनके लिए काम कर रहा है।

श्री नन्द कुमार साय : सभापति महोदय,..।

श्री सभापति : आपके सवाल अब खत्म हो गए।

सुश्री सुशीला तिरिया : धन्यवाद सर। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि किसी भी राज्य के ट्रायबल एरिया में नेशनल लेवल का कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, ऐसा मंत्री जी ने अपने जबाव में कहा है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि गांव-गांव में जो ट्रेनिंग देने की बात उन्होंने जबाव में कही है, इस तरह की ट्रेनिंग अब तक राज्यों में और जिलों में कितनी हो चुकी है और ट्रेनिंग लेने के बाद इसका क्या नतीजा निकला है ? ट्रेनिंग देने के बाद लघु उद्योग बनाने की कोई ट्रायबल इंटरप्रेनियोर करना चाहता है, तो जहां पर लघु वन उद्योग का प्रोडक्शन ज्यादा है, अगर वह कुछ करना चाहेगा, तो उसको मदद देने के लिए क्या कोई प्रोग्राम बनाया है ?

श्री तुषारभाई चौधरी : चेयरमैन सर, मैं माननीय सदस्या की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जो हनी गैदरर्स हैं, उसके लिए हमने पूरे देश में 12147 लोगों को ट्रेनिंग दी है, जो गम पिकर्स हैं, उसके लिए हमने 15300 लोगों को ट्रेनिंग दी है, जो महुआ फलावर्स गैदरर्स हैं, उसमें हमने 1000 लोगों को ट्रेनिंग दी है और जो Lac growers हैं, उसमें हमने करीबन 7000 लोगों को ट्रेनिंग दी है और Dona and Pattal की हमने 12040 लोगों को ट्रेनिंग दी है।

जहां तक tribal artisans का सवाल है artisan के लिए हम तीन प्रकार से ट्रेनिंग देते हैं। पहला हमारा काम प्राइमरी लेवल ट्रेनिंग देना, उसमें 60 दिन की सीमा होती है, उसमें हम ऐसे लोगों को पसन्द करते हैं, जो artisan के साथ जुड़े हुए हों, उनके बेटे, उनके सगे-

सबंधियों को हम ट्रेनिंग देते हैं, जिससे कि वह कला लुप्त न हो जाए। दूसरी, इसमें हम उनको 45 दिन की ट्रेनिंग देते हैं । इसके बाद Design Workshop Training होती है, वह 15 दिन की होती है और तब तक वह आर्टिस्ट पूरा तैयार हो जाता है। इस प्रकार से हमारी कार्यवाही चल रही है और हर एक ट्रेनिंग में 20 लाभार्थी होते हैं, तो उनके ऊपर हम एक लाख रुपया खर्च करते हैं। स्टेटवाइज जितने भी लाभार्थी होंगे, प्रति 20 के हिसाब से हम एक लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराते हैं।

श्रीमती वृंदा कारत : सर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि आपने उन लोगों को ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग देने के बाद क्या आपने कोई समीक्षा की है, कोई रिव्यु किया है कि जिन ट्रायबल्स ने ट्रेनिंग ली, उसके बाद उनको कुछ फायदा हुआ है या नहीं हुआ है ? यह मैं इसलिए पूछ रही हैं, क्योंकि हकीकत यह है कि इस समय पूरे ट्रायबल इलाके में minor forest produce का इतना संकट है और दाम इतने गिर चुके हैं कि चाहे आपने ट्रेनिंग दी या चाहे आपने कुछ भी किया, लेकिन उनको जो दाम minor forest produce के मिल रहे हैं, वे बहुत कम मिल रहे हैं। आपने हनी की बात की है, यहां बाजार में हनी का दाम इतना ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन ट्रायबल्स जो इतना कष्ट करके हनी गैदर करते हैं, हनी गैदरर्स स्पाट पर उसका दाम कम से कम एक तिहाई गिरा है। अभी मैं एक प्रदेश में गयी, आप लोग शिकाकाई की ट्रेनिंग देते हैं, अभी शिकाकाई का दाम उस सरकार ने गिरा दिया है। अभी तेंदू पत्ता की बात कीजिए जो भी अभी minor forest produce है, ट्रेनिंग के बाद भी जो दाम गिर रहे हैं, उसके लिए मार्केटिंग फैडरेशन का क्या कोई रोल हो सकता है कि वह कम से कम दाम की गारंटी दे, ताकि ट्रेनिंग का फायदा ट्रायबल्स को मिले।

(1एम पर आगे)

Q. No. 325 (Contd.)

श्री तुषारभाई चौधरी : चेयरमैन सर, मैं माननीय सदस्या के विचार से सहमत हूं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो minor forest produce gatherers है, उनकी आय इतनी कम हो जाती है कि वह मजबूरन वे काम छोड़कर राष्ट्रीय ग्रामीण योजना में, जहां पर उनको एक दिन में सौ रुपए मिलते हैं, काम करने चला जाता है। हमारी जानकारी में यह सब आया है इसीलिए हमने इस साल *राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद* को शहद, गोंदकतीरा, महुआ फूल और गोना पत्ता की ट्रेनिंग तथा उसकी सर्वे रिपोर्ट का काम सौंपा है, जिसकी लागत बारह लाख दस हजार है। हम भी उस minor forest produce gatherers के प्रति चिंतित हैं और हमारा विभाग भी इस काम के लिए कार्यरत है कि उन्हें कैसे ऊंचा उठाया जाए।

DR. (SHRIMATI) KAPILA VATSYAYAN: Sir, I wish to ask who are these trainers. In this country, there is a long, long tradition of specialization of these forest gatherers of honey and *dona-pattas*. Who are the people who are going to train these people, and, what are their qualifications. Secondly, if they have been trained, and, if they have these skills, what is the relevance of these trained people of tribal India with our schemes of education, and, why can't they be put in the primary education as teachers.

श्री तुषारभाई चौधरी : चेयरमैन सर, जहां तक गोना पत्ता का सवाल है, हमने अभी इसके लिए बारह हजार चालीस लोगों को यह ट्रेनिंग दी है। हमने उनको मोल्डिंग मशीन और स्टिचिंग मशीन भी दी है और ज्यादा से ज्यादा जो संगठन हैं, हम उनको भी ...(व्यवधान)..

श्री शिवानन्द तिवारी : महोदय, सवाल कुछ पूछा जा रहा है और जवाब कुछ दिया जा रहा है। ...(व्यवधान)..

MR. CHAIRMAN: Silence please.

श्री शिवानन्द तिवारी : महोदय, यह क्या तरीका है? ...(व्यवधान)..

MR. CHAIRMAN: Please allow the answer to be completed. (Interruptions) आप बैठ जाइए। ...(व्यवधान).. Please allow the answer to be completed.

श्री कमाल अख्तर : इनको ट्रेनिंग दिलावाइए। ...(व्यवधान)..

श्री सभापति : कमाल अख्तर साहब, आप बैठ जाइए। ...(व्यवधान)..प्लीज़, आप बैठ जाइए। ...(व्यवधान)..

SHRI PENUMALLI MADHU: Mr. Chairman, Sir, the Minister should answer the question. (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Mr. Madhu, (Interruptions)...

SHRI GIREESH KUMAR SANGHI: Why are you... (Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Please complete the answer. (Interruptions) Please complete the answer.

श्री तुषारभाई चौधरी : चेयरमैन सर, हमने CCI पुणे को भी उसके लिए संकलित किया है और जहां तक minor forest produce gatherers का सवल है, जैसे छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ में minor forest produce gatherers फैडरेशन गवर्नमेंट संस्था है, जो ट्रेनिंग का कम करती है तथा एक NGO भी है, वह ट्रेनिंग का काम करती है। जहां-जहां पर भी हमारा ट्राइबल सबप्लान चल रहा है, उसके अंतगर्त NGO को चुनकर, हम ट्रेनिंग का काम भी कर रहे हैं।

(समाप्त)

श्री अमीर आलम खान : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि पिछले वर्ष मांग के अनुसार कोयले का उत्पादन काफी कम रहा है। सरकार मांग और आपूर्ति के अंतर को कम करने के लिए क्या प्रयास कर रही है, जिससे इस्पात और विद्युत जैसे उद्योगों को बढावा मिल सके?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : महोदय, माननीय सदस्य को मैं पहली सूचना तो यह देना चाहूंगा कि पिछले साल कोयले का उत्पादन उससे पिछले साल से ज्यादा रहा है, कम नहीं रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे देश में जितनी तेजी से इंडस्ट्रीलाजेशन हो रहा है, उतनी तेजी के साथ हमारे देश की ग्रोथ बढ़ रही है, उतनी ही तेजी के साथ पावर की डिमांड बढ़ती चली जा रही है। जितनी पावर की डिमांड बढ़ रही है, उतनी ही कोयले की डिमांड भी बढ़ती चली जा रही है। पिछले साल के मुकाबले हमने इस साल कोयले का उत्पादन ज्यादा किया है। हम इसकी इतनी ज्यादा व्यवस्था कर रहे हैं कि आने वाले वर्षो में शायद हम देश में कोयले की आवश्यकता के अनुरूप अपना उत्पादन कर लें। इसके अलावा भारत सरकार ने यह भी व्यवस्था की है कि अगर कोई भी इंडस्ट्रीयलिस्ट कोयले का आयात करना चाहता है, इम्पोर्ट करना चाहता है, तो वह विदेशों से कोयले का इम्पोर्ट भी कर सकता है। क्योंकि हमारे देश में कोयले की जो क्वालिटी है, वह एवरेज क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी का कोयला नहीं होता है, जैसे स्टील इंडस्ट्री है, इसको अच्छी क्वालिटी के कोयले की जरूरत होती है। जैसे कि पेपर इंडस्ट्री है, इनको अच्छी क्वालिटी के कोल की जरूरत होती है, इसलिए उनके लिए यह पूरी व्यवस्था है कि वे चाहें तो विदेशों से कोयले का आयात कर सकते हैं। हम यह कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश में पावर के लिए जितनी कोयले की जरूरत है, उतने कोयले का उत्पादन हम आने वाले वर्षों में पूरा कर लें। धन्यवाद।

(समाप्त)

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

PAPES LAID ON THE TABLE

1. **SHRI B.K. HANDIQUE:** Sir, I lay on the Table, a copy (in English and Hindi) of the Memorandum of Understanding between the Government of India (Ministry of Mines) and the National Aluminium Company Limited (NALCO) for the year 2010-11.

(**MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair**)

2. **SHRI JAIRAM RAMESH:** Sir, I lay on the Table:—

I. A copy (in English and Hindi) of the Ministry of Environment and Forests Notification No. S.O. 191 (E), dated the 27th January, 2010, declaring the area around Sultanpur National Park as Eco-sensitive Zone , under Section 26 of the Environment (Protection) Act, 1986.

II.(1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:—

(a)Thirty-second Annual Report and Accounts of the Andaman and Nicobar Islands Forest and Plantation Development Corporation Limited, Port Blair, for the year 2008-09, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b)Review by Government on the working of the above Corporation.

(2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above.

III.(1) A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) of Section 39 and sub-section (6) of Section 40 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974:—

(a)Annual Report and Accounts of the Central Pollution Control Board (CPCB), Delhi, for the year 2008-09, together with the Auditor's Report on Accounts.

(b)Review by Government on the working of the above Board.

(2) Statement (in English and Hindi) giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (1) above.

IV. A copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(a)Annual Report and Accounts of the Animal Welfare Board of India, Chennai, for the year 2008-09, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b)Statement by Government accepting the above Report.

(c)Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

V. A copy (in English and Hindi) of the Outcome Budget for the year 2010-11 of the Ministry of Environment and Forests.

3. **SHRI BHARATSINH SOLANKI:** Sir, I lay on the Table—

I. A copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Power, under Section 179 of the Electricity Act, 2003:—

(1) F.No.L-7/138(153))/2008-CERC, dated the 23rd October, 2009, publishing the Central Electricity Regulatory Commission (Furnishing of Technical Details by the Generating Companies) Regulations, 2009, together with delay statement.

(2) F.No.L-7/139(159))/2008, dated the 24th December, 2009, publishing the Central Electricity Regulatory Commission (Measures to relieve congestion in real time operation) Regulations, 2009.

(3) No. L-1/(3)/2009/CERC, dated the 1st January, 2010, notifying 1-1-2010 as the date on which the Central Electricity Regulatory Commission, (Grant of Connectivity, Long-term Access and Medium-term Open Access in inter-State Transmission and related matters) Regulations, 2009, shall come into force.

(4) No. L-7/25(5)/2003 -CERC, dated the 12th January, 2010, publishing the Central Electricity Regulatory Commission (Fixation of Trading Margin) Regulations, 2010.

(5) No. L-1/12/2010-CERC, dated the 18th January, 2010, publishing the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Recognition and Issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations, 2010.

(6) No. L-1/13/2010-CERC, dated the 21st January, 2010, publishing the Central Electricity Regulatory Commission (Power Market) Regulations, 2010.

II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(a)Annual Report and Accounts of the National Power Training Institute (NPTI), Faridabad, for the year 2008-09, together with the Auditor's Report on the Accounts.

(b)Review by Government on the working of the above Institute.

(c)Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

(Ends)

REPORTS OF DEPARTMENT RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON INDUSTRY

DR. AKHILESH DAS GUPTA (UTTAR PRADESH): Sir, I present a copy each (in English and Hindi) of the following Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Industry:—

(i) Two Hundred and Fifteenth Report on the Demands for Grants (2010-11) pertaining to The Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises (Department of Heavy Industry);

(ii) Two Hundred and Sixteenth Report on the Demands for Grants (2010-11) pertaining to The Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises (Department of Public Enterprises); and

(iii) Two Hundred and Seventeenth Report on Demands for Grants (2010-11) Pertaining to the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises.

(Ends)

REPORTS OF DEPARTMENT RELATED PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON FINANCE

SHRI S.S. AHLUWALIA (JHARKHAND): Sir, I lay on the Table, a copy each (in English and Hindi) of the following Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Finance (2009-10):—

(i) Tenth Report on "Securities and Exchange Board of India (Amendment) Bill, 2009";

(ii) Eleventh Report on "Demands for Grants (2010-11)" of the Ministry of Finance (Departments of Economic Affairs, Expenditure, and Financial Services and Disinvestment);

(iii) Twelfth Report on "Demands for Grants (2010-11)" of the Ministry of Finance (Department of Revenue);

(iv) Thirteenth Report on "Demands for Grants (2010-11)" of the Ministry of Planning;

(v) Fourteenth Report on "Demands for Grants (2010-11)" of the Ministry of Statistics and Programme Implementation;

(vi) Fifteenth Reports on "Demands for Grants (2010-11)" of the Ministry of Corporate Affairs;

(vii) Sixteenth Report on "Action Taken by the Government on the recommendations contained in the First Report (Fifteenth Lok Sabha) on Demands for Grants (2009-10)" of the Ministry of Finance (Departments of Economic Affairs, Expenditure, Financial Services and Disinvestment);

(viii) Seventeenth Report on "Action Taken by the Government on the recommendations contained in the Second Report (Fifteenth Lok Sabha) on Demands for Grants (2009-10)" of the Ministry of Finance (Department of Revenue);

(ix) Eighteenth Report on "Action Taken by the Government on the recommendations contained in the Third Report (Fifteenth Lok Sabha) on Demands for Grants (2009-10)" of the Ministry of Planning;

(x) Nineteenth Report on "Action Taken by the Government on the recommendations contained in the Fourth Report (Fifteenth Lok Sabha) on Demands for Grants (2009-10)" of the Ministry of Statistics and Programme Implementation; and

(xi) Twentieth Report on "Action Taken by the Government on the recommendations contained in the Fifth Report (Fifteenth Lok Sabha) on Demands for Grants (2009-10)" of the Ministry of Corporate Affairs.

(Ends)

LEAVE OF ABSENCE

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have to inform Members that a letter has been received from Shrimati Jaya Bachchan stating that she is unable to attend the House as she will be abroad due to personal reasons. She has, therefore, requested for grant of Leave of Absence from 15th of April to 30th of April 2010 of the Current Session of the Rajya Sabha.

Does she have the permission of the House to remain absent from 15th April to 30th April 2010 of the Current Session of the Rajya Sabha?

(No Hon. Member dissented)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Permission to remain absent is granted.

(Ends)

BILL INTRODUCED

THE COPYRIGHT (AMENDMENT) BILL, 2010

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI KAPIL SIBAL): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Copyright Act, 1957.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, I introduce the Bill.

(Ends)

MATTERS RAISED WITH THE PERMISSION OF CHAIR

RE.: DEATH SENTENCE ANNOUNCED TO SEVENTEEN INDIANS IN UAE

श्री अविनाश राय खन्ना (**पंजाब**) : धन्यवाद उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में उन सत्रह भारतीयों को, जिनको यू.ए.ई. में सजा-ए-मौत दी गई है और उसके अलावा पचास भारतीयों को उस केस में टॉर्चर किया गया है, के बारे में मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सरकार ने जिस ढंग से रवैया अपनाया हुआ है, उससे उन परिवारों में बड़ा जबर्दस्त रोष है। ऐसा लग रहा है कि सरकार उस बात पर इंटरनेशनल दबाव, उस देश पर नहीं बना पाई है। यह एक इनह्यूमन एक्ट है और इसके लिए सरकार को जल्दी से जल्दी उन परिवारों से मिलकर,जो पॉलिसी है, वह क्लियर करनी चाहिए और उन भारतीयों को रिहा करवाने का प्रयास करना चाहिए। जिनको टॉर्चर किया गया है, उनके लिए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में जाकर, यू.एन.ओ. में जाकर उनके कम्पेनसेशन का भी दबाव बनाना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समाप्त)

सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा (**पंजाब**) : उपसभापति जी, मैं स्वयं को इससे संबद्ध करता हूं।

(समाप्त)

RE.: PROBLEM OF STORAGE OF GRAINS IN WAREHOUSES OF FCI AND POSSIBILITY OF ITS ROTTENING BY BEING KEPT IN OPEN

श्री प्रभात झा (**मध्य प्रदेश**) : आदरणीय उपसभापति महोदय, देश में जहां एक ओर महंगाई बढ़ रही है, अगर उसी एवज में देखें तो एफ.सी.आई. की एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि 10,37,738 मीट्रिक टन खाद्यान्न अनाज गोदामों में, पिछले छह-सात वर्षों में सड़ गया है। इनके भंडारण की कीमत लगाई गई थी। यह इतना अनाज है कि एक साल तक

एक करोड़ आदमी को भर पेट खिलाया जा सकता है। इस भंडारण में 243,21,59,726 रुपए लगे हैं।

(AKG/1O पर जारी)

-SK-LP/YSR-AKG/12.05/1O

श्री प्रभात झा (क्रमागत) : मजेदार मामला है कि सड़े अनाज को हटाने के लिए 2,69,40,490 रुपए खर्च हुए हैं। पंजाब में 72 लाख टन गेहूँ खुले में पड़ा हुआ है। मैं यह सड़ा गेहूँ आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लाया हूँ।

श्री उपसभापति : आप इसे नहीं दिखा सकते।

श्री प्रभात झा : सारा गेहूँ सड़ रहा है। 65 लाख टन गेहूँ पर तिरपाल नहीं है। देश भर में गेहूँ के उत्पादन का 50 फीसदी हिस्सा पंजाब और हरियाणा देता है, हम सब जानते हैं। आज यह स्थिति बन गई है कि समय नहीं है, अगर समय पर केन्द्र सरकार नहीं चेती, तो बहुत नुकसान होगा। 18 फरवरी को सी. रंगराजन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कुप्रबंधन के कारण महंगाई बढ़ रही है। देखिए, कितना बड़ा मजाक है कि एक तरफ लाखों टन गेहूँ भण्डारण के अभाव में, तिरपाल के अभाव में सड़ रहा है और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है और लोग भूखे मर रहे हैं। यह क्या है? शरद पवार जी खाद्य मंत्री भी हैं और कृषि मंत्री भी हैं। पता नहीं सरकार ने उन्हें किस काम में लगाया हुआ है, शायद उनकी जानकारी में है कि नहीं, वे कह देते हैं कि यह सारा मामला राज्यों पर जाता है। कितना बड़ा मजाक है? क्या यह राष्ट्रीय अपराध नहीं है, क्या यह national crime नहीं कहा जाएगा कि लाखों लोग भूख से मरते हैं और इतना गेहूँ, जो एक साल तक एक करोड़ लोगों को खिलाया जा सकता है, वह यहाँ पर भण्डारण के अभाव में सड़ जाए? यह कौन सा अपराध कहा जाएगा? आप क्रिकेट खेलिए, लेकिन देश के किसानों की, देश के गरीबों की पूरी चिन्ता करिए। मुझे लगता है कि वे देश के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। पंजाब में सिर्फ 6.67 लाख टन गेहूँ रखने की जगह बची है, लेकिन वे 1.20 करोड़ टन खरीदने वाले हैं। वहीं हरियाणा की भी यही स्थिति है। वहाँ 5 लाख टन रखने की

जगह बची है, जबकि 70 लाख टन खरीदा जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी 11 लाख टन रखने की जगह बची है और वहाँ पर 39 लाख टन खरीदा जाएगा। यह क्या है? FCI की क्षमता 2.86 करोड़ टन की है। हम कहते हैं कि हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। यह कैसा कृषि प्रधान देश है, क्या यह अन्याय नहीं कहा जाएगा, क्या यह अपराध नहीं कहा जाएगा ... (समय की घंटी)... मुझे लगता है कि जो आने वाली फसल है, जो गेहूँ खरीदा जा रहा है, उसके रखने की भी व्यवस्था सरकार के पास नहीं है।

श्री उपसभापति : प्रभात जी, आपका समय समाप्त हो गया है। श्री डी. राजा।

(समाप्त)

श्री एस.एस. अहलुवालिया (झारखंड) : सर, हम सभी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए इस मुद्दे से अपने आपको सम्बद्ध करते हैं।

श्री रवि शंकर प्रसाद (बिहार) : सर, मैं स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए इस मुद्दे से सम्बद्ध करता हूँ।

डा. सी.पी. ठाकुर (बिहार) : सर, मैं स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए इस मुद्दे से सम्बद्ध करता हूँ।

सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा (पंजाब) : सर, मैं स्वयं को माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए इस मुद्दे से सम्बद्ध करता हूँ।

(समाप्त)

DEPORTATION OF MOTHER OF SLAINED LTTE LEADER

SHRI D. RAJA (TAMIL NADU): Sir, with deep sense of agony, I draw the attention of the entire House to a very inhuman, shameful incident that took place at the Chennai Airport on Friday. An 80-year old woman came to Chennai on a valid medical visa given by our own mission in Kuala Lumpur, but she was not allowed to get out of the aircraft. She was kept inside the aircraft and then she

was deported back to Kuala Lumpur. She happens to be the mother of the LTTE Chief Prabhakaran. This incident has sullied the idea and image of India. India is known for love, compassion and humanitarian considerations. Even the basic principle of jurisprudence says that convicted criminals for life imprisonment or death sentence are entitled for medical treatment till their last breath. But she is not a criminal. She is not a convicted criminal either. I don't think there is any criminal charge against her by the Government of India or by the Government of Sri Lanka. She came here for medical treatment on a valid medical visa. Why was she deported? What is the policy of our Government? I hold the Government responsible for such an inhuman act towards an old woman. Is it India? What is the policy of the Government? On the one hand we talk about rehabilitation of Sri Lankan Tamils. On the other hand you don't even allow an old woman for medical treatment. What is your policy? I condemn this policy of the Government. I urge upon the Government to change its policy. I want the Government to make its stand clear. Where does it stand when it talks about rehabilitation of Tamils in Sri Lanka?

(Contd. By VKK/1P)

-YSR/VKK-SCH/1p/12.10

SHRI D. RAJA (CONTD.): There was genocide. The UN Human Rights Commission is investigating the war crimes in Sri Lanka. What is the stand of the Government of India? It is callousness. And, it has let down the Sri Lankan Tamils. Sir, she may be Prabhakaran's mother, but, she is an old woman. What is

the threat from her to the sovereignty of India or to the sovereignty of Sri Lanka?

(Time-bell)

I urge upon the Government to change its policy. I urge upon the Government to explain to the nation as to why such an incident took place at the Chennai Airport.

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Now, Mr. Ahluwalia. (Interruptions)

DR. V. MAITREYAN (TAMIL NADU): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

DR. K. MALAISAMY (TAMIL NADU): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI T.K. RANGARAJAN (TAMIL NADU): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI N. BALAGANGA (TAMIL NADU): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI TIRUCHI SIVA (TAMIL NADU): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI A.A. JINNAH (TAMIL NADU): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

श्री शिवानन्द तिवारी: सर, मैं भी इनसे ऐसोसिएट करता हूं। सर, बूढ़ी औरत को जहाज से उतरने ही नहीं दिया।

श्री उपसभापति: आप पहले अहलुवालिया जी को बोलने दीजिए, उन्होंने नोटिस दिया है।

SHRI S.S. AHLUWALIA (JHARKHAND): I associate myself with what my learned friend Shri D. Raja said about an old ailing woman travelling all the way from Malaysia to Chennai on medical visa. First of all, the question is: If a criminal is punished or if he is eliminated on foreign land, are his parents liable for that crime? The answer is, no. No criminal jurisprudence on the entire earth gives this permission. Why have you issued a medical visa in the name of Parvati, an 80-year old woman, to take specialized treatment in Chennai? She has faith in Chennai doctors. She flew right from Malaysia to Chennai and when she reported to the Immigration Department, she was deported back just because she is mother of slain Prabhakaran. Why? Why is India behaving like this? When Prabhakaran was alive, no Government tried to bring him to India and punish him for the assassination of Rajiv Gandhi. But, now his mother, who is ailing, aged, suffering from some disease which needs immediate and urgent medical attention, was deported back. She travelled so long, but, she was deported back in agony and tension. It is very unfortunate. We are pleading for pardoning off the sentence of Nalini. We are requesting to pardon her. She was involved in the conspiracy and had a direct link. She was punished for whole life. On the one hand, we are demanding that she be pardoned and be let off from jail. On the other hand, we send back an ailing woman. It is not fair. It is very unfortunate. I need an explanation from the Government. The Government should come forward and make a statement as to under what circumstances she was deported back. If it is the fault of the Immigration Department, he should be punished; if it is the fault of our diplomat posted in Malaysia that despite information from MEA, Delhi,

he issued a visa, he should be taken to task. But, the Government must come to the House to explain this.

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Mr. Shivanand Tiwari. (Interruptions) Mr. Raja, it is Zero Hour. (Interruptions)

SHRI D. RAJA: The Government is fit enough to respond. The Home Minister is sitting here. Let him respond. (Interruptions) It is a serious issue. The entire Tamil Nadu is getting agitated; all political parties are getting agitated; all sections of Tamil people in Tamil Nadu are getting agitated. (Interruptions) I urge upon the Government to respond. The Home Minister from that State is sitting here. Let him respond. What is the stand of the Government?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: सर, मैं इनसे ऐसोसिएट करता हूं। माननीय उपसभापति जी, कुछ संवेदनशीलता तो होनी चाहिए, कुछ नियम तो होना चाहिए। यह तो भारतीय संस्कृति का अपमान है। उनको फिर से यहां बुलाकर उनका इलाज कराया जाए।

(Ends)

RE: NEED TO BAN IPL AND ORDER CBI AND INCOME TAX DEPARTMENT INQUIRY INTO THE AFFAIRS OF BCCI AND IPL

--

श्री शिवानन्द तिवारी (**बिहार**): उपसभापति महोदय, आज के इकोनॉमिक टाइम्स में ...(व्यवधान)

श्री उपसभापतिः नहीं, आप पेपर मत दिखाइए, अखबार मत दिखाइए।

श्री शिवानन्द तिवारी: आज के इकोनॉमिक टाइम्स में पहली खबर के रूप में आईपीएल के बारे में छापा गया है। आईपीएल के जो कमिश्नर हैं, श्री ललित मोदी साहब, उनके बारे में यह बताया गया है कि चार साल पहले तक जो भी उन्होंने काम किया, सबमें वह फेल रहे और

साथ ही बैंक के डीफॉल्टर रहे। लेकिन पिछले तीन बरसों में अचानक वह अरबपति बन गए, उनके पास प्राइवेट जेट प्लेन है, लग्ज़री याच है, एस सीरीज़ की कई मर्सिडीज़ गाड़ियां हैं, बीएमडब्ल्यू गाड़ी है।

(1q/Psv पर जारी)

-SCH/PSV-RSS/1Q/12.15

श्री शिवानन्द तिवारी (क्रमागत): उनकी सम्पत्ति देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी जमा है। इनके बारे में Income Tax Department ने investigate किया। उसका investigation छः महीने तक चला। उसने उनका email account देखा, उनके टेलिफोन को watch किया और इंग्लैंड में उनका जो registered telephone था, उसको भी सुना। उसके बाद वह इस नतीजे पर पहुँचा कि उन्होंने IPL के जरिए black money generate की है, वहाँ सट्टा लगवाने में मदद की है और यहाँ तक कि IPL के मैच के रिजल्ट को फिक्स कराने में भी भूमिका अदा की है। ये आरोप उन पर लगाये गए हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि यह रिपोर्ट सरकार के पास छः महीने से पेंडिंग है और अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज क्या हाल है हम लोगों के देश का! पुराने जमाने में जैसे गुलामों का बाजार लगता था और डाक बोला जाता था, आज उसी तरह से IPL के जरिए खिलाड़ियों का डाक बोला जा रहा है कि इस खिलाड़ी की कीमत इतनी और उस खिलाड़ी की कीमत इतनी। यही इस खेल की संस्कृति है कि Cricket को prostitution बनाया जा रहा है। मैं सरकार से यह माँग करता हूँ कि IPL को तत्काल भंग किया जाए। BCCI के पास अकूत सम्पत्ति जमा है जबकि हमारे अन्य सारे खेल मर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। एक तरफ हमारे हॉकी के खिलाड़ी हैं और मुक्केबाज हैं जिनको अपने शरीर के लिए जो खुराक चाहिए उसके लिए भी उनको पैसा नहीं मिल रहा है। हॉकी के खिलाड़ियों को लाख-दो लाख रुपए के लिए हड़ताल करनी पड़ती है और दूसरी तरफ black money, सट्टा, betting हो रही है और मैच के रिजल्ट को प्रभावित किया जा रहा है। हमारे देश में आज किस ढंग का काम हो रहा है, उसका यह एक नमूना है। मैं यह माँग करता हूँ कि

IPL और BCCI दोनों का जो पैसा है, उसको जब्त किया जाए और सी0बी0आई0 तथा Income Tax Department से इसकी जाँच कराई जाए। इसके साथ ही उस जब्त किए हुए पैसे को Ministry of Sports को, डा0 गिल साहब को दे दिया जाए ताकि देश के जो दूसरे खेल हैं, उनको प्रोमोट करने में, उनको आगे बढ़ाने में उस पैसे का इस्तेमाल हो सके। ...(समय की घंटी)... हमारे देश के अन्दर स्पोर्ट्स के नाम पर गंदा काम हो रहा है, उसको तत्काल बंद करके इन सारे अपराधियों को जेल में बंद किया जाए।

(समाप्त)

श्री उपसभापति: धन्यवाद।

SHRI MOHAMMED ADEEB (UTTAR PRADESH): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member with the permission of the Chair.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon'ble Members, on 15th April, 2010, the Vice-Chairman announced that the discussion on the statement made by the Minister of Home Affairs on the Maoist attack on CRPF personnel in Dantewada district of Chhattisgarh was over and the Minister will reply afterwards. Now, I call upon the Minister of Home Affairs to reply.

REPLY TO DISCUSSION ON THE STATEMENT MADE BY THE HOME MINISTER ON THE 15TH APRIL, 2010.

--

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): Mr. Deputy Chairman, Sir, this debate took place last Thursday and I am grateful that I have an opportunity to reply to the discussion today. Meanwhile, of course, I had an opportunity to speak in the Lok Sabha. Much of that has been reported, and I am

sure, hon. Members have read reports of that reply. So, I shall keep my reply brief today. Sir, about three or four months ago, there was a discussion in this House on the internal security situation, and in my reply, I did devote a fair amount of time to deal with the naxalite situation. I am sure many hon. Members recall that debate. Let me go back and trace the evolution of our policy to deal with the menace of Left Wing extremism. As far as my party is concerned, in 2006, at the AICC session, my party adopted a resolution that said *inter alia*, and I quote: "The Indian National Congress views with concern the growing incidence of naxalite-associated violence in parts of India. The party urges the UPA Government to give this matter highest priority and believes that this has to be addressed as a serious law and order issue, but with underlying socio-economic causes as well. Clarity and firmness in handling the threat of violence does not foreclose the possibility of a dialogue in appropriate situations."

(followed by 1r)

-RSS-TMV-DS/1R/12.20

SHRI S. S. AHLUWALIA: Was it of 2007?

SHRI P. CHIDAMBARAM: It was of 2006.

SHRI S. S. AHLUWALIA: What about 2004? You read that also.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Now, you please sit down. That was an AICC Resolution. That was of 2006.

SHRI S. S. AHLUWALIA: You read 2004 also.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Therefore, Sir, as far as we are concerned, we have kept in mind three basic principles. Firstly, it raises a serious law and order situation. It has to be dealt with as such. Secondly, one must not be unmindful of the socio-economic causes. Thirdly, the door for dialogue is always open provided the conditions for dialogue are acceptable and there is a situation which allows a dialogue to take place. After I took over I began to address the issue of Left-Wing Extremism and, as hon. Members are aware, we had so far three conferences of Chief Ministers. The first two conferences of Chief Ministers were followed by a special meeting with Chief Ministers of naxal-affected States. I have with me the minutes of the meetings that we held with the Chief Ministers of naxal-affected States. I don't wish to go into it. But let me tell you that, after a very exhaustive discussion, all Chief Ministers and the Governor of Jharkhand -- Jharkhand was under President's rule at that time -- broadly agreed with the approach that we had placed before the meeting and endorsed it. In fact, I made an opening statement at the conference of Chief Ministers on 17th August, 2009 and I said in that statement and I want to quote:

> "The third challenge is left-wing extremism, naxalism. On more than one occasion the Prime Minister rightly cautioned the nation that Left-Wing Extremism posed the single biggest internal security challenge to India. In the last few months, the CPM Maoists stepped up its attacks on the Indian State and on the Indian people. I would like to draw your attention to a document put up by the CPM Maoists on June 12, 2009 which is titled "Post-election situation -- our task". Anyone reading that document would have no illusion about the nature and gravity of the threat. Let me make our policy stance clear. We believe in the two-pronged approach of development and police action. However, the naxalites are anti-

development and have targeted the very instruments of development, school buildings, roads, telephone towers, etc. They know that development will mean the masses, especially, the poor Tribals, will be weaned away from the grip of the naxalites. Hence these deliberate attacks on the developmental activities. Our response, therefore, will be police action to wrest control of the territory that is now dominated by the naxalites, restoration of civil administration and undertaking developmental activities. Meanwhile, we will encourage the State Governments to talk to the naxalites, both individuals and local units, on condition that they give up their misconceived armed liberation struggle. Let our message to the naxalites be clear. We will talk, we will act, we will restore order and we will undertake developmental activities. I am happy to report that all the naxal-affected States have resolved to confront and overcome the challenges of CPM Maoists and later this evening I shall hold a separate meeting with the Governor and the Chief Ministers of those States".

(Contd. By 1S/VK)

SHRI P. CHIDAMBARAM (CONTD): We have not swerved from this path. Our policy remains the same. It is a serious law and order problem, and, therefore, quite rightly, the Chief Ministers have asserted that it is their right and their responsibility to deal with the problem. The Central Government provides Paramilitary Forces, intelligence and other assistance to them to deal with the problem. The goal is to restore the civil administration which is not there. And if anyone of you thinks that there is some kind of a civil administration in these areas, I think we are harbouring an illusion. In many of these areas, there is simply no civil administration worth the name. So we have to restore the civil administration and then take development of these areas. It is not a question of which comes first. If there is an opportunity with the district administration to do some developmental activities, certainly they must do it even if the place is infested with the CPI (Maoist). But where it is not possible to do anything, where it is not possible to build the roads, where it is not possible to build a school building, where it is not possible to take electricity, surely, then the first thing that has to be done is to regain control over the area and restore the civil administration. Sir, we have not swerved from this path. This remains our policy. It will be our policy and I intend to continue to work with this policy.

Why do I say that the CPI (Maoist) target developmental activities? I have with me their targets in the last four or five years. Their principle target is the security forces. Their second target is, whoever he is, they call him police informer. They will kill a party cadre, they will kill an SPO and they will kill a village

Mukhiya and then name him a police informer. Their third target is infrastructure. In 2009 alone, they have demolished 71 school buildings and 23 Panchayat bhawans; two power plants were attacked; 67 telephone exchanges or mobile towers were attacked and demolished; there were 46 attacks on railway properties and 17 attacks on specific industrial establishments. Now people say, "Talk to Maoists". I will come to 'talks' in a moment. Let me make an offer. It perhaps took five or six or ten years to build a school building in that district. You know how it is in each of our districts. If an old school building is dilapidated, how long does it take to get the money, to get the plan approved and to get the work started to build a school building? I am sure these 71 school buildings in these States came up after five or six years of efforts by the local MLA or the local MP or the local Panchayat leader. These 71 school buildings have been demolished. This year, so far, nine have been demolished. This is up to the end of March. In April alone, more school buildings have been demolished in Bihar, in the Jamui district. If the Maoists are really pro poor, let me ask this question: we will find money and I will beg, borrow or steal money to rebuild these 71 school buildings, but can anyone guarantee that those buildings will not be attacked again? Will anyone, any of these human rights organizations, any of these NGOs stand up and tell the people of this country, "Rebuild these 71 school buildings; we assure you that the CPI (Maoist) will not attack any more school buildings?"

(Contd. By 1T)

SHRI P. CHIDAMBARAM (contd.): Let me persuade all the telephone companies, including the BSNL, to rebuild the 74 telephone towers and Exchanges. Will any NGO, will any Human Rights Organisation, be willing to assure us that these towers will not be demolished? I think we must understand the nature of the CPM (Maoist). I have said this before; the other speakers have said it. Their goal is the seizure of political power and the overthrow of the established authority of the State. Their method is Armed Liberation Struggle, and their instrument is the People's Liberation Guerilla Army which, under the June 12 document, they hope to convert it into a regular Liberation Army. They want to overthrow the Parliamentary system. And how should Parliament respond to this challenge? I think the Human Rights Organisations and the NGOs are living in a fool's paradise. If the CPM (Maoist) overthrows the established authority and seizes power, will they allow any Human Rights Organisation to function in this country? Will they allow any NGO to function in this country? Will there be a Parliament? Will all those, who write 33-page articles, be allowed to write 33-page articles? Will there be a magazine to publish a 33-page article? I think the gravity of the situation must be recognized, and I am willing to be advised, as I have been advised, if necessary, what cross-corrections we need to make, what fine-tuning we need to make. But there is no escape from the fact that the challenge has to be met squarely and fearlessly. It is a serious law and order problem. It is also a problem where we have to address the underlying socio-economic issues.

In 2009 alone, they killed 211 people, and named them as police informers. This is not an indention of any of my agencies. Once they kill somebody, they

issue a statement saying, "We killed him because he is a police informer", and simply counting the number that 211 people were killed in 2009, and they were mainly police informers. In 2008, 170 people were killed, named as police informers. In this year, in the first quarter, 35 people have been killed and named as police informers. Sir, what happened in Dantewada will, of course, be inquired into by Shri Rammohan. As I said, in my statement, preliminary reports, preliminary inquiries, indicate that there has been a terrible failure of Command and Control. Please recall what I said. This is a battalion which was given to the Chhattisgarh Government. The 55th Battalion was given earlier, about three years earlier. Since its tour of duty was over, the 55th Battalion was replaced by the 62nd Battalion. The 62nd Battalion went into this area in the month of March-April, 2009. It was a battle-hardened battalion. It had earlier done a tour of duty in Bihar. Now, there are standard operating procedures. It was agreed in the Chief Minister's meeting, and we have reiterated this in the Standard Operating Procedures, that intra-State operations must be conducted under the direction of the DGP and the State Police, and inter-State operations will be conducted by the Special D.G., CRPF, because that requires coordination between States. The exercise, which was undertaken in Dantewada, was purely an intra-State exercise. Nevertheless, -- the reasons can be established only in the Inquiry -- only one Head Constable of the State Police accompanied them. Otherwise, all the officers and men belonged to the CRPF. They were ambushed and 74 of them were killed. The rescue party was sent, and the vehicle which accompanied

the rescue party also came under attack. The driver and the Head Constable died.

(Continued by 1U)

SHRI P. CHIDAMBARAM (CONTD.): So, we have got 76 lives were lost. The inquiry is under way. Shri Ram Mohan has promised me that he will give me the Report by the 25th of this month. He will debrief the seven injured jawans who have fortunately survived. He will do a thorough inquiry. He will examine the post-mortem reports. He will examine the forensic evidence, and he will present the Report. I have requested him to fix responsibility from the Assistant Commandant right up to the Minister in the Ministry of Home Affairs. I said please fix responsibility who failed in his or her duty at every level from the Assistant Commandant right through to the Deputy Commandant, the Commandant, the DIG, the SP of the District, the DIG of that Zone from the State, the IG of the Zone, the DG(P), come up to the Special DG, the DG of the CRPF, and come right up to the Minister. Let him fix the responsibility where this failure of command and control took place. And as soon as that Report is available, we will draw the right conclusions, and I am sure, there will be an opportunity for me to share those conclusions with this House. But, until then I request that we suspend judgment. Let the Report come, and surely action will be taken based on that Report.

Sir, there have been instances in the past. We know that in 2006, 55 men of the Chhattisgarh Police were ambushed. That was the biggest tragedy until then. The famous Greyhounds were ambushed in Orissa, when they were crossing a dam; 34 people died. There was another ambush in 2009 in Chhattisgarh where about 27 people died. We have the Sealdah Massacre where

24 people died. I mean, no one asked anyone to resign or no one came forward to resign. When this happened, I was truly heart-broken, and, therefore, I felt that it was my moral responsibility to resign; I resigned. The Prime Minister and the UPA Chairperson rejected my resignation. I have received support from many sections of the House. I am grateful for the support. I am determined to continue to provide leadership in the Ministry of Home Affairs, and to our paramilitary forces, and I am determined to continue to extend assistance to the States to fight the menace of Naxalism. We have to do so with greater determination and without fear. Fear is the biggest enemy. We have to fight this menace fearlessly. At the same time, let me repeat, we must show greater compassion, greater concern for the poor, greater dedication in taking development to the places where the Naxals seem to have some dominance. We are assisting the State Governments in a number of ways. We have got the security related expenditure, and the special assistance that is being provided to the States for modernization of police force. We also have a Special Task Force under the Cabinet Secretary looking at these 34 districts. Huge amount of money is being given under various programmes. Extra money is being given under various programmes. Unfortunately, not all the money is being spent. We have programmes that applied throughout the country applying these 34 districts also, and, additional money is being given. I do not wish to read the figures. But, I wish hon. Members will please ask their State Governments how much of the money is being spent. We are giving money for Vidyutikaran Yojana; we are giving money under Drinking Water; we are giving money under Pradhan Mantri Sadak Yojana; we are giving special funds to these

34 districts. There is a Task Force under the Cabinet Secretary which monitors it. The Secretary, Planning Commission gets a weekly report, and she updates it every month. But what she has shown me not all the money is being spent. I think money must be spent. We must take development to the extent possible to these areas, and as and when our security forces gain control over these areas, we must rush in development. That is our approach; that will continue to be our approach.

(Contd. by 1w-kgg)

kgg/1w/12.40

SHRI P. CHIDAMBARAM (contd.): Sir, there are some recent developments which are heartwarming. As you know, CPI (Maoists) has set up some front organizations and carries on its activities through front organizations. The PCPA in West Bengal is a front organization. They have now set up a militia organization called Siduka. What is happening is, in Many States, tribals, villagers affected by Maoist activities are also setting up their own organizations. This is not to be confused with the controversial Salwa Judum. That is a controversial matter. For example, in Jharkhand, villagers in East Singhbhum district and in district Saraikela-Kharsawan have formed a Gram Ganarajya Panchayat Parishat. They are organizing mass meetings and they are opposing the free run of the Maoists.

In Orissa, villagers in district Sudargarh have also risen against the Maoists following harassment by Maoist cadres including demand for villagers' participation in Maoists' armed actions, assaulting of villagers for maintaining links

with the police and demanding that one person from each house should join the CPI (Maoists).

In Chhattisgarh, tribals under the banner of Ma Danteshwari Bastar Adivasi Swabhiman Manch have protested against the activities of pro-Maoist organizations. So, it is not as though the people who live in fear are not revolting against what the Maoists are doing. It is still at an incipient stage. But, clearly people are beginning to recognize that it is not the Maoists who are going to give them freedom or development.

I went to Lalgarh. This is pretty obvious. They had a host of complaints against the State Government. I am not here to say whether the complaints are right or wrong. They had many complaints. But, they immediately added that the only one who can bring them development was the State Government. They are pretty clear in their perception that the Maoists are not going to bring them any development. Their poser to me was, "We have had no development, nobody visited us, the Maoists are here on the rampage with their guns, nobody to protect us, what are we supposed to do?" Really, that is the question that we have to address. If we can protect the people, surely they will rise against the Maoist oppression. If we can win their confidence, take the civil administration to that area, opportunities will open up for bringing development to that area.

As I said, this is a complex task, a task which I believe the State Governments have to address. As I said in my statement, there is no question of it in my mind that the primary responsibility lies with the State Government. At the same time, I assure you that the Central Government is ready and willing to assist

the State Government in every manner possible in dealing with the matter as a law and order issue as well as for developmental matters.

Sir, these 74+1+1 will be paid compensation. I have instructed that the compensation must be paid by the end of this month. We have already worked out the compensation. The families have been contacted. They have been asked to name the next of kin. We will give them adequate monetary compensation. The word 'adequate' may be misplaced. There can be nothing adequate to compensate loss of life, but we will give them substantial monetary compensation. The salary of the martyred jawan will be paid for the rest of his life if he had lived and retired; until the date of his retirement, that salary will be paid.

(Contd. by kls/1x)

KLS/1X-12.45

SHRI P. CHIDAMBARAM (CONTD): And one member of the family will be given a job. The family will have to choose which member of the family will get the job. The State Governments are also giving compensation to those Jawans who come from that States. So, that will be in addition to what the Central Government gives as compensation. Sir, I am grateful to the Member for the broad support they have given to me and to the Government. We will continue to remain focussed on this problem. This problem will remain with us for many, many years. We will be able to substantially contain and control this menace in about two to three years. We have to set for ourselves a time horizon. No Government, no Home Minister can say that we cannot contain this for the next twenty years. That is not the message that we can give to our police forces and to our security

forces. We will have to set for ourselves a time horizon, we will have to contain this menace in the next two to three years and we will have to bring development to these areas. Yes, remnants will remain. Kalu Sanyal and Charu Majumdar started a movement in 1967. But long after they gave up, one of them died and one of them disowned the movement, the remnants remain. But these remnants will have to be addressed. But a determined, organised armed liberation struggle cannot be allowed in this country which strikes the very root of democracy, which strikes the very root of our concept of a nation, therefore, it has to be squarely and fearlessly met. Finally, Sir, word about talks and I know that to talk about talks now seems misplaced, but, nevertheless the door must be kept opened for talks. There is this bizarre interview given by Koteshwar Rao and even more bizarre interview given by Azad which was published in one of the newspapers in a sanitised version. I would urge Members not to read the sanitised version but go the website and read the unexpurgated version of the interview and the choicest abuses that are being used in that interview. Be that as it may, what is our condition? I know that they will not lay down arms. I am not so naïve as to believe that they will lay down arms immediately. But how do you expect the Government of India to talk to a militant group unless they give up violence? Should they not say, "We give up violence"? Once they give up violence, our policy is that we will set in motion a process of talks. The State Governments can talk to them. The Central Government will facilitate those talks. If the Central Government has to join the talks, the Central Government is willing to join the talks. But the condition is that they should not indulge in violence. On the last

occasion they gave this offer suddenly one day that they are willing for talks. But within three hours of that announcement, there was an incident in Bengal, the police patrol party was attacked, the police patrol party had to retaliate and one of them was killed. Within 24 hours there was a series of incidents. How can we talk under the shadow of the gun, under the shadow of violence? Therefore, I repeat that we will facilitate talks with the CPM Maoists provided they say, "We will give up violence." At least, as long as talks take place, there should be no violence, there should be no killing, there should be no abductions, and there should be no targeting the infrastructure. At the end of talks, if there is progress, then, we can move on. But at the moment, from what I gathered from the interviews, they are unwilling and unprepared to give up violence. They say, "To ask us to give up violence is absurd. We believe in armed liberation struggle, so how do we give up violence?" Anyway, I reiterate Government's policy. We will deal with this as a serious law and order problem and face the challenge fearlessly. We will also address the underlying socio-economic causes. The door for dialogue is open provided they give up violence. With these words, Sir, I am grateful to the hon. Members. I will come back to this House at an appropriate time when I have the Report of the Rammohan Committee. Thank you.

(Followed by 1Y/SSS)

SSS/1Y/12.50

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI ARUN JAITLEY): Sir, we heard an elaborate reply from the hon. Home Minister and the hon. Home Minister has

rightly pointed out that various sections of the House, both inside the House and the society outside, had broadly supported the effort of the Government to fight this Armed Liberation Struggle. The Minister began by quoting the 2006 Resolution of his own party. I got an impression that he was probably trying to remind his own party rather than us as to what the party's conventional position on this issue has been. That could be a strategic issue as far as the Minister and his party is concerned. The core issue which the Minister pointed out was that there are areas where civil administration's control has been minimized and therefore, these guerrilla armies have really taken control of these areas. How is it possible for anyone particularly, when schools are being broken, when Panchayat Bhawans are being broken, when dispensaries are being demolished? How does the civil administration under these circumstances enter those areas and start development activity? How does the Minister try and convince all his colleagues in his side? When you referred to bizarre interviews being given by the Maoists, let me just read out two or three sentences from an equally bizarre interview. And who gives it? It is the gentleman from your party who initiated the debate and therefore, I am not so sure what your party's position is and I am referring to a report in the Economic Times of 16 April where it says, Congress Working Committee Member, Dr. K. Keshava Rao joined etc. etc.... In this growing chorus amongst the Congress Leaders, he told the Economic Times that he completely supported Mr. Digvijay Singh except for a personal attack component by Mr. Chidambaram. What I am saying is, development must come first. Start the political process. If there is a law and order problem, the State must then

tackle it. Now, how do you enter those areas and start the development? The law and order component will have to be tackled. This iron wall which the Maoists have created in those areas will have to be broken and then the developmental activity takes place. Where it is possible to do it simultaneously, please do it simultaneously and your offer for talks, your party's spokesperson was asked if it was the right time to commence talks with the Maoists, given the scale of Dantawada attacks on 76 CRPF Jawans who lost their lives, Mr. Rao replied, hundreds of people died in Kargil, did we not speak to Pakistan? Therefore, irrespective of the violence continuing, irrespective of their failure to abjure violence, you must now start talking.

DR. K. KESHAVA RAO: Sir,...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let him complete. I will give you an opportunity. Let him complete.

SHRI ARUN JAITLEY: In fact, the whole country is willing to support you on this battle against the Maoists. How do you convince your own colleagues? This is not that after the debate your minds have changed and after your reply in the Lok Sabha your minds have changed. This is given after that and given by him, the persons again fielded by your party to give your party's stand on this Maoist issue. How do you intend tackling them? Please tell us this.

(Ends)

SHRI SITARAM YECHURY (WEST BENGAL): Sir, we have heard the detailed response of the hon. Home Minister with great interest and I commend the fact that the approach that has been taken has been an approach that this problem...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is some problem. There is power problem. You carry on.

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, there are many problems. The hon. Minister of Power is here. We will come to him later but let us talk about the Maoists' problem. As far as tackling the Maoist problem is concerned, there has to be a unified approach by all of us and I think, that sentiment which was there in the discussion has been echoed by the hon. Home Minister and that is good. But, Sir, there are certain issues that need to be addressed more pointedly. I, for one from my party have always maintained that the restoration of the writ of the civic administration is one of the most important tasks in this entire battle and it is the absence of the writ of the civic administration that has denied development in these areas. Very correctly, he pointed out the problems when he visited Lalgarh and the problem is the inability of the State Government to reach those areas because of the manner in which they have been cordoned off. This is a problem and how we are going to resolve it? My request is to strengthen the process of coordination between the Centre and the various State Governments.

(Followed by 1Z/NBR)

-SSS/NBR-GS/1Z/12.55

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You seek clarifications. I cannot allow another debate.

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, I am not debating at all. Given the gravity of the situation, I am only seeking clarifications.

As I said in my speech, we have had failure -- without the Maoists and without the Naxalites -- in fighting with Veerappan for twenty years, because three State Governments were involved. But, five are involved here. I only want the Central Government to pay more attention on the issue of co-ordination between them. This is number one.

Secondly and more importantly, the hon. Leader of the Opposition talked about the inner party things of the Congress Party. I am not going there. I am asking about the alliance. Sir, I mentioned it in my speech also that 28 meetings were called in Bengal but all of them were boycotted by an ally of the Government which is now in the Cabinet. What is not merely surprising but actually worrying is: I believe, since the debate took place, I do not see their Members neither present in this House nor, as per the reports, in the other House. We doubt whether they are actually boycotting the Parliament because of the unified approach that all of us are having with regard to tackling the Maoist violence. It is a very serious contradiction for the Government. How can you live with this contradiction of having the Cabinet Ministers who are opposing the Government's own stand? That is a very serious problem that has to be answered. Thank you.

(Ends)

SHRI D. RAJA (TAMIL NADU): Sir, there are reports with regard to use of Army and Air Force. If the Government is contemplating seriously about that, I would like to warn the Government that it would lead to colossal damage of life and property of tribal people. So, the Government should restrain itself and it should

not think of using Army and Air Force against tribal people in the name of fighting Naxalites.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please seek clarifications.

SHRI D. RAJA: That is one clarification, because he has not answered to this.

Secondly, the tribal people, now, are starving and are not getting foodgrains. If at all the Government has to use Air Force, it should be used for dropping foodgrains in the tribal areas so that you can win the confidence of the tribal people.

Thirdly, there is tension in all the tribal areas. The tension is on the issue of handing over the tribal land and forest wealth in the name of mining operations to big business and corporate houses. The Government should assure this House that it will not be done and the rights of the forest dwellers and tribal people will be protected.

Since the hon. Minister has raised an issue, I would like to ask him. The school buildings are demolished. Yes. School buildings are demolished. Will the Government assure that schools will be allowed to run as schools, not as camps of security forces? That is the fear why tribal people do not send their children for schools. The school buildings have been taken over by security forces. Can he assure the nation that school buildings will be used for schooling the children of tribal people?

Then, Sir, the hon. Minister casually said that Salwajudum is a controversial issue. But, it is a serious issue. What is the rehabilitation given to the victims affected by Salwajudum? What is the response of the Central

Government? These are the clarifications I wish to seek from the hon. Minister. Thank you.

(Ends)

DR. K. KESHAVA RAO (ANDHRA PRADESH): Sir, I just wanted to clarify to the hon. Leader of the Opposition and also the hon. Home Minister that there are no differences in the party vis-à-vis the Government stand, because both law and order and development are intertwined. They are the two sides of the same coin. The question is more about articulation. But, nonetheless, since Dantewada comes as a symptom and where we are not looking at the symptom but the disease we are trying to stress and articulate from the disease point of view. Sir, we said that development is first and I continue to say so. But, it does not mean, as the hon. Home Minister rightly said, that if development is not allowed in a particular place or location, what do we do? You come with your own right, which you need not speak. I said that you have quoted from the Economic Times. I said that it is the duty of the Government. The two things, Mr. Chairman, Sir,....

(CONTD. BY USY "2A")

-NBR-USY/ASC/2A/1.00

DR. K. KESHAVA RAO (CONTD.): ... the political process, which the Leader of the Opposition talked about the other day, and the formulation policies. As far as the Government is concerned, it is a constitutional legality. So, the police or the

military or whatever it is, it is a duty. We don't evolve a policy which is already contained in the Constitution.

Sir, lastly, let me make it very clear to the Minister that there is a fundamental difference between us and the BJP. Our first priority is the maintenance of law and order. For us... (Interruptions) Please let me speak. You can have your own formulations. For us, it is a social order. Entire Constitution was quoted the other day. For us, the governance is the priority and the 'governance' is maintenance of social order. Law comes into picture to maintain the social order. But, at the same time, law and order is a part and parcel of it. It gets priority; it gets first place where the social order is not able to sustain or is not maintained in the usual course.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Shivanand Tiwari. (Interruptions) I cannot give opportunity to the whole House again.

श्री शिवानन्द तिवारी(बिहार): उपसभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री जी के बयान पर जो चर्चा हुई थी, हमने उसमें कहा था कि हमारे सिस्टम को चुनौती दी जा रही है और जो हमारे सिस्टम को चुनौती दे रहा है, हम उसके विरुद्ध हाथ पर हाथ रखकर बैठे नहीं रह सकते। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि मैं बिहार के उस इलाके से विधायक रहा हूं, जिस इलाके में नक्सलवाद काफी सक्रिय था। मैंने यह कहा था कि उस इलाके में जो सामंतों का जुल्म हुआ था, ..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : आप क्लेरिफिकेशन पूछिए।

श्री शिवानन्द तिवारी : उन लोगों को कभी न्याय नहीं मिला। अगर वह अपनी पत्नी के साथ घ्ार में चारपाई पर सोए हुए हैं, तो लोग उनकी पत्नी को उठाकर ले गए। पुलिस ने कहीं किसी की मदद नहीं की। हमारे साथ जिला प्रशासन था और अजीत भट्टाचार्य, सुमन दुबे,

प्रभात जोशी सब उस गांव में गए हुए थे, जहां कलैक्टर की मौजूदगी में हजारों लोगों ने दलित बस्ती पर गोलियां चलाई थी, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है। मैं यह कह रहा हूं कि डेवलेपमेंट सेकन्ड्री है, असली बात यह है कि आदमी को जस्टिस मिलना चाहिए, जो कि मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।

मैं एक दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी से कोई भी यह एक्सपेक्ट नहीं करता है कि वे दंतेवाड़ा में जाकर स्कूल बनाएं। हमारा यह कहना है कि आदिवासियों या गरीबों के जिन इलाकों में अभी माओवादी सक्रिय नहीं हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ में ऐसे कई जिले हैं, जहां माओवादी सक्रिय नहीं हैं, उन इलाकों में...(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : आप क्लेरिफिकेशन नहीं पूछ रहे हैं। यह क्लेरिफिकेशन नहीं है। डा. वी. मैत्रेयन।

श्री शिवानन्द तिवारी: आप इसके बार में क्या करने जा रहे हैं? हम यह नहीं कह रहे हैं कि दंतेवाड़ा में जाकर और विकास कर सकते हैं। लेकिन उन इलाकों में जहां अभी ...(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : देखिए, आप...।

श्री शिवानन्द तिवारी: आप उन इलाकों में विकास के लिए, न्याय देने के लिए क्या कर रहे हैं? (Ends)

DR. V. MAITREYAN (TAMIL NADU): Sir, I commend the hon. Union Home Minister for his no-nonsensical approach in tackling the issue in today's reply. My party will definitely extend a whole-hearted support in crushing the menace of Maoist violence. My specific question to the hon. Minister is this. What is the exact number of Maoists operating in West Bengal?

SHRI H.K. DUA (NOMINATED): Mr. Deputy Chairman, Sir, I would like to seek a small clarification. He spoke about the cooperation between the Central

Government and the State Governments. At the same time, if I heard him correctly, he said that only one Head Constable from the local police was accompanying the CRPF people. Does it mean that the CRPF did not seek more substantive cooperation from the State police, or, the State Government did not lend that kind of cooperation?

श्रीमती मोहसिना किदवई (छत्तीसगढ़) : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि इतने बड़े ऑपरेशन से पहले जो बेसिक चीज है, जिसके ऊपर डिपेंड करती है, वह है इंटेलिजेंस की रिपोर्ट। कि उस एरिया में क्या हो रहा है, किस तरह से जाना है और कैसे करना है। इतने बड़े ऑपरेशन से पहले ये सारी चीजें सामने आनी चाहिए थीं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि दो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, एक स्टेट की और एक सेन्टर की।

(क्रमशः 2B/LPपर)

-ASC/LT-PK/1.05/2B

श्रीमती मोहसिना किदवई (क्रमागत) : मैं समझती हूं कि जो स्टेट लेवल की इंटेलिजेंस होती है, उसकी ज्यादा सुनी जाती है, उसकी ज्यादा इम्पोर्टेन्स होती है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि इंटेलिजेंस की यह क्या रिपोर्ट थी, जिस पर इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस पर डिपेंड किया? मान्यवर, उस दिन मैं इत्तेफाक से वहीं पर थी, उसी संभाग में थी, हमारा पंचायती राज का सम्मेलन हो रहा था, मैं यह पूछना चाहती हूं कि स्टेट गवर्नमेंट की अपनी जिम्मेदारी है, वह उससे अलग नहीं हो सकती है, वह सबसे पहली चीज तो यह बताएं कि इंटेलिजेंस की किस रिपोर्ट पर वहां पर इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ?

(समाप्त)

محترمہ محسنہ قدوائی: مہودے، میں مانّئے منتری جی سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اتنے بڑے آپریشن سے پہلے جو بیسک چیز ہے، جس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے، وہ ہے انٹیلی جینس کی رپورٹ، کہ اس ایریا میں کیا ہوا رہا ہے، کس طرح سے جانا ہے اور کیسے کرنا ہے؟ اتنے بڑے آپریشن سے پہلے یہ ساری چیزیں سامنے آنی چاہئیں تھیں۔ میں مانّئے منتیر جی سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ دو انٹیلی جینس ایجنسیاں ہوتی ہیں، ایک اسٹیٹ کی اور ایک سینٹر کی۔

میں سمجھتی ہوں کہ جو اسٹیٹ لیول کی انٹیلی جینس ہوتی ہے، اس کی زیادہ سنی جاتی ہے، اس کی زیادہ امپورٹینس ہوتی ہے۔ میں مانّئے منتری جی سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ انٹیلی جینس کی یہ کیا رپورٹ تھی، جس پر اتنا بڑا آپریشن ہوا، سینٹرل گوورنمینٹ نے کس پر ڈپینڈ کیا؟ مانیور، اس دن میں اتفاق سے وہیں پر تھی، اس سنبھاگ میں تھی، ہمارا پنچایتی راج کا سمّیلن ہو رہا تھا، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اسٹیٹ گوورنمینٹ کی اپنی ذمہ داری ہے، وہ اس سے الگ نہیں ہو سکتی ہے، وہ سب سے پہلی چیز تو یہ بتائیں کہ انٹیلی جینس کی کس رپورٹ پر وہاں پر اتنا بڑا آپریشن ہوا؟

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I think everybody has sought his or her clarification. ..(Interruptions).. Please, please. ..(Interruptions)..

श्री विक्रम वर्मा (मध्य प्रदेश) : सर, एक सवाल ..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : आप बोले थे, ठीक है..(व्यवधान)..आप क्लैरिफिकेशन नहीं पूछ रहे हैं..(व्यवधान)..

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Sir, I will seek my clarification in just one sentence.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Just in one sentence.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR (MAHARASHTRA): Yes, Sir, I will seek my clarification in one sentence only.

I had raised the point of continuous coordination with the State Governments because this is a multi-State problem. So, please clarify whether the mechanism set up by the then Home Minister, Lal Krishan Advani*ji*, of having

every month or bi-monthly Home Secretary meeting to coordinate the inter-State action will be revived. The other clarification..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR:The other clarification is this. Unless political parties stop taking assistance from Maoists for winning elections, this menace will not stop. So, will that be guaranteed?

(Ends)

SHRIMATI VIPLOVE THAKUR (**HIMACHAL PRADESH**): Mr. Deputy Chairman, Sir, I am grateful to you. I want to know from the hon. Minister इन्होंने, जो मरे हैं, I am sorry for them, उनके लिए तो बहुत अच्छी स्कीम बनाई है कि उनकी तनख्वाह भी मिले, लेकिन जो जख्मी हुए हैं, जो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, मैं देखने गई थी, जिनकी पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर गुजरेगी, क्या उनके बारे में भी सोचा जा रहा है? क्या उनको भी कुछ ज्यादा दिया जाएगा, उनके बच्चों का भी ख़याल रखा जाएगा, मैं यह पूछना चाहती हूं?

(समाप्त)

श्री उपसभापति : पूरे हाउस ने पूछना शुरू कर दिया तो कैसे होगा..(व्यवधान).. Please, please.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD (**BIHAR**): Sir, I am grateful to you. Hon. Home Minister, my question is very clear. How many groups are there among the naxals which are operating in the country and which is the deadliest? Do you find any nexus of these naxal elements with some terrorist groups, out to destabilize India? ..(Interruptions)..

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. I cannot allow a new discussion on the same issue.

श्री अली अनवर अंसारी (बिहार) : मान्यवर, पार्टी के कई लोगों ने पूछा है..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : वह ठीक है, लेकिन पार्टी का स्टैंड भी होता है।

डा. अखिलेश दास गुप्ता(उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, मैं माननीय गृह मंत्री जी से सिर्फ एक प्रश्न यह जानना चाहता हूं कि जो माओवादी प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां के बारे में आपने बहुत विस्तार से बताया है और हम हर तरह से आपको सहयोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो बॉर्डर क्षेत्र हैं, जहां पर निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार ने इस तरह के टेरेरिज्म या इस तरह के extremism को कंट्रोल कर रखा है, उत्तर प्रदेश में इस तरह की समस्या तो थी, लेकिन वहां के बारे ..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : यह क्लैरिफिकेशन नहीं है..(व्यवधान)..

श्री अखिलेश दास गुप्ता : वहां के बारे में ..(व्यवधान)..मैं यह पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के आस-पास के जो क्षेत्र है, क्या आप उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार को पूरा सहयोग देंगे? मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं और इस संबंध में उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

(समाप्त)

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): Sir, without converting this into a second round of the debate and the second reply, let me briefly clarify some issues on which the hon. Members have sought clarifications. Alienation of tribal land and mining licenses granted in some of these areas are, indeed, two very important issues which the CPI (Maoists) capitalizes and agitates for. There is no denying the fact. In fact, in Orissa, the major issue is that the tribal land is now gone into the hands of non-tribals. The Orissa

Government has been advised more than once to apply the Orissa laws to see that the tribal land is restored to tribals.

(Contd. By PB/2C)

PB/2c/1.10

SHRI P. CHIDAMBARAM (CONTD.): Mining licences have been granted. Under the law as it stands today, it is the State Government which recommends grant of mining leases and the Central Government's approval is taken; MoUs have been entered into. But we have said that these matters can be brought to the table and discussed and solutions can be found. But it is not as if the CPI(Maoists) activities are present only in areas where tribal lands have been alienated and the mining licences have been granted. What is there in Lalgarh? There is no mining licence in Lalgarh. There is no mineral in Lalgarh. Why is that district today the centre of Maoist activity in Bengal for a while? These are indeed issues that have to be addressed and solutions found. That can only be found if they come to the table. That is why in an interview that I gave to Tehelka I said, 'you abjure violence, agree to talks and we can discuss anything under the Sun, including the MoUs that you are concerned about, including issues like alienation of tribal land.'

Sir, it is difficult to make a very accurate estimate of the number of cadres. The principal organization that is now leading this armed liberation struggle is the CPI (Maoists). This was formed after the merger of the PWG and MCC in 2004. They are now one organization called CPI(Maoists) and 92-95 per cent of all depredations are committed by the CPI(Maoists). There are some splinter groups. There are internecine quarrels among the splinter groups too. But the

depredations that we are talking about, the vast majority of them, close to 95 per cent, are committed by the CPI (Maoists). They have a Politburo; they have a Central Committee; they have a Central Military Commission; and they have a People's Liberation Guerilla Army. They organize themselves into battalions, companies and dalams. Four of the Polit Bureau members are in custody; four former members of the Polit Bureau are also in the custody; nine Central Commission members have been arrested. ...(Interruptions)... There are 14 Polit Bureau Members. Therefore, it is not as though we are not aware of their structure. But to make a very accurate estimate of the number is difficult. We think there are about 10,000-15,000 armed cadres. But they also have the support of what they call the Jan Militia, people whom they have armed with local weapons. That number perhaps runs to 15,000 or 20,000. But these are in the estimates; nobody has made a headcount of who these people are.

Sir, there is no proposal to use the Army in these areas; nor is there any proposal to use the Air Force in these areas. What is being examined is whether some special forces have to be used to supplement the work of the trained paramilitary forces and whether aircraft can be used for purposes of surveillance, logistics, supplies and evacuation. There is no proposal to use the Army or the Air Force against the Naxals.

Then there is a question about cooperation. I think, Mr. Dua should read my statement. The decision to launch this operation on April 4 was a joint decision taken by the IG of the State, Mr. Longkumar, the DIG of that region, Mr. SRP

Kalluri and the DIG of the CRPF, Mr. Nalin Parbhat. There is a joint decision. Now, what went wrong, who is responsible will come out in the inquiry.

Finally, Sir, the sub-text of Shri Arun Jaitley's, Shri Sitaram Yechury's comments, we are a robust democracy.

(Contd. by 2d/SKC)

2d/1.15/skc

SHRI P. CHIDAMBARAM (Contd.): I am sure, Mr. Arun Jaitley buried his head in a book when Mr. Vinay Katiyar was speaking on the Liberhan debate. I do not think you should make an attempt because you will not succeed in trying to divide my party. That will not happen. (Interruptions)

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: They use their democratic rights against you, Mr. Chidambaram! (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM: Our Party is totally united. The UPA is totally united. And I am glad to notice that the whole House is now totally united in the fight against Naxals. (Interruptions) Sir, the problem with Mr. Sitaram Yechury and his unnamed antagonists...(Interruptions)...

SHRI SITARAM YECHURY: No, no, I named them. They are not unnamed. I have told you clearly. (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM: It is a problem that arises in West Bengal and a problem that would be resolved in the State of West Bengal in about 12 months from now. (Interruptions)

SHRI MOINUL HASSAN: It is a problem of the whole country and not West Bengal alone. (Interruptions)

SHRI SITARAM YECHURY: What will happen to the country in these 12 months? That is the point. (Interruptions)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Madhu, please take your seat. (Interruptions)

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, over 150 of our cadre have been killed fighting the Maoists and the Home Minister is making a joke about it. (Interruptions) What is this, Sir?

SHRI P. CHIDAMBARAM: I am not making a joke of it. (Interruptions) I am not making a joke of it.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He was referring to Mr. Sitaram Yechury. (Interruptions)

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, 150 of our cadre have been killed in West Bengal and he is talking in this way. (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, I don't think this is an appropriate time to go into the numbers and details of who has killed, who has been killed, etc. These are very controversial matters. We have the numbers. This is not the place to debate these numbers. We are sorry that cadres of more than one Party and cadres of the two principal parties in Bengal are being killed. In fact, I have raised this with the Chief Minister of Bengal and I have said, these inter-Party clashes, killings of party cadres by the Maoists must come to an end.

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, he is again...(Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, this point has...(Interruptions)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You had your say. You wanted a debate. (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM: This is not the way. (Interruptions)

SHRIMATI BRINDA KARAT: Sir, he is confusing the House. (Interruptions)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: How many people of your Party want to speak? (Interruptions)

SHRI SITARAM YECHURY: I am only appealing to the Home Minister to...(Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM: Mr. Yechury, I have already said that CPI(Maoists) are killing party cadres. A large number of CPI(M) cadres have been killed. I have condemned it in Kolkata.

SHRIMATI BRINDA KARAT: In your own Cabinet people are saying that there are no Maoists in Lalgarh. Why don't you... (Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM: But if some Members want to bring in inter-Party clashes...(Interruptions)... Don't bring in inter-Party clashes here. We have Members here. We have discussed this with the Chief Minister. The Chief Minister has said that he is equally concerned. These numbers are alarming numbers. He is equally concerned. He has promised me that it was his intention to put an end to inter-Party clashes.

SHRI SITARAM YECHURY: That is different. We are speaking of Maoist attacks.

SHRI P. CHIDAMBARAM: I have condemned it in Kolkata... (Interruptions) I have condemned it in Kolkata. (Interruptions)

SHRIMATI BRINDA KARAT: He is deliberately confusing the House and trying to protect...(Interruptions)

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, as I said, we are a robust democracy. We must allow for shades of opinion. It is the Government's duty to evolve a policy after listening to every shade of opinion, a policy that has the support of Parliament. I believe, what I have said today, the policy that I have outlined today, has a very large measure of support in this House. I thank the Members. I think the debate should be concluded on that note that this policy has a large measure of support.

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned for one hour for lunch.

The House then adjourned at
twenty minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at twenty minutes past two of the clock, MR. DEPUTY CHAIRMAN, in the Chair.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up the working of the Ministry of Power. Shri Shyamal Chakraborty.

DISCUSSION ON WORKING OF MINISTRY OF POWER

SHRI SHYAMAL CHAKRABORTY (WEST BENGAL): Mr. Deputy Chairman, Sir, thank you for giving me the opportunity to initiate the discussion on a very important subject. Sir, power situation is very grave in our country. It is well-known that we are suffering from power crisis for a long time. It is not only a phenomenon of this year only, but the entire country is suffering from power shortage for past decades. All of us are aware that power is the backbone of our civilization, for social and economic development, for industry, for agriculture, for health institutions, for educational institutions, for domestic consumption and for every branch of civilization. I remember, last time one hon. Member from the Treasury Benches referred to a famous statement of Lenin that 'electricity is 50 per cent socialism.' It is correct but Lenin never said that 'electricity is not 50 per cent capitalist development.' Sir, the crisis that we are facing now in the power sector in our country is a cumulative effect of inefficiency of the subsequent Governments in general and the Ministers in particular. Power cuts is a regular phenomenon for the last two or three decades. Now we have entered into the Eleventh Five Year Plan. Ten Five Year Plans have been passed. What is our experience? In no Five Year Plan, our Power Department could achieve the target

fixed by the Planning Commission. The Planning Commission never fixed the target according to the needs of people of our country. Always the target was fixed much below the need of people, even then the Government or the Power Department failed to achieve the target fixed by the Planning Commission. No Five Year Plan could achieve, at least, 50 per cent of the target. So, the accumulated power deficit has become bigger and bigger every year.

(Contd. By 2f/KSK)

KSK/2.25/2F

SHRI SHYAMAL CHAKRABORTY (CONTD): So, there always remains a gap - a gap between the need and the target, and between the target and the achievement. This is the fourth year of the Eleventh Five Year Plan. The target for the Eleventh Five Year Plan was 79,000 MW. Three years have passed and we have achieved only 27,000 MW. So, how can we expect that in the remaining two years, the Ministry of Power will be able to achieve the remaining 52,000 MW? Here, I would like to ask the hon. Minister whether it is possible to achieve the target in these remaining two years.

Sir, in the Question Hour today, we were discussing the problem of supply of coal. Thermal power stations are fully dependent on supply of coal. But, what is the supply position? No power station gets the required coal for their power generation requirements. The allotment of coal is fixed by the Coal Authority of India, which is under the Central Government. Quota of coal for power stations is never fixed according to their need. Generally, the quota is fixed below the need of the power stations. Even then, the quota, which is fixed, is not available for the

power stations. So, there is always a gap. Now, not only the supply of coal, but also the quality of coal is not good. Ash content is so high that generally, power station machineries get damaged. In the last six or eight months, the Coal Authority has decided that it will allow the supply of coal with bigger sizes which cannot be used for the power generation. As a result, the machinery in power stations is getting damaged day by day. Sir, today, we are 17 per cent short of power. Our Government is very rapidly going in for privatisation of power sector. Right from NTPC to BHEL, everything is in the market for disinvestment. On the one hand, they are going to de-nationalise the power sector, but, at the same time, they are trying to nationalise the power cuts to our country. A personal monitoring is needed by the concerned Minister himself. It is essential, but we have experienced that our hon. Power Minister -- he has been in this Ministry for a long time -- has never visited any State. He does not want to know the details of the problems faced by the management, by workers, and the Governments of those States, or the power stations. I have a different experience. Sir, Shri Jairam Ramesh was deputed for one year as the MoS in the Ministry of Power. But, I saw his initiative. Once, there was some problem with the workers in U.P.

(continued by 2g - gsp)

GSP-AKA-2.30-2G

SHRI SHYAMAL CHAKRABORTY (CONTD.): He immediately contacted me. Actually, I am associated with the trade union in the power sector. I contacted the agitated workers, who apprised me of denial of their economic rights by the

management. I communicated the same to Mr. Jairam Ramesh. He, immediately, intervened and settled the issue just in two days' time. He also visited so many places. I saw him in West Bengal. He visited the West Bengal Power Plant, had a discussion with the management and the workers, and, tried to settle the issues. This kind of initiative is totally absent from the Minister, who is in charge at present.

Sir, in some nationalized power sectors, workers are denied of their legitimate rights, particularly, in Kashmir and Himachal Pradesh. I am not accusing the State Governments there. The problems are going on in the nationalized power sectors. Take for example, the NHPC. Workers are denied of their legitimate rights. They are not getting their Provident Fund; they are not getting daily wages; they have to work beyond eight hours, and, when the workers got agitated, even security forces were used against them. At the gun point, they snatched their overcoats, torn their clothes and pushed them into the difficult terrain of forest areas in the winter season. They were treated as if they were anti-nationals or militants. Sir, they are our workers, our citizens, and, they are agitating for getting their legitimate rights, their Constitutional rights. And, this is the bad treatment which they are getting due to the policies of the Ministry of Power!

Sir, BHEL is one of the world's famous companies. Once, India said that in the power sector, it was walking on two legs; in generation, it is sufficient; and it is sufficient also in manufacturing of equipments. Ninety per cent of our power

industry was nationalized. But, now, they are rushing for privatization. We boast of NTPC. Disinvestment started there three, four years back.

In the UPA-I when we were supporting the Government from outside, the Government was restrained to some extent. Now, they are free to move, and, I wonder when the Finance Minister says that the sale of shares or equity means, people's participation. What does he mean by 'people'? Who are those people who purchase the shares of these big companies? They are less than one per cent of India's population. We have more than one billion population, and, only one per cent people are purchasing or selling shares. Does one per cent represent the people of the country as a whole?

Sir, I would like to draw your attention to another important matter. This Government is really going to deprive rural people of their right to get electricity.

(Contd. by 2h-sk)

-gsp/sk/2.35/2H

SHRI SHYAMAL CHAKRABORTY (CONTD.): But how? Only the Rajiv Gandhi Grameen Vidutikaran Yojana does not explain everything. Sir, I would like to remind you that in the Electricity Act 2003, it was stated that "The appropriate Government shall endeavour to supply electricity to all areas, including villages and hamlets". 'The appropriate Government' means State Governments. The Central Government try to take away power from the rural people. Then, we insisted inside the Parliament as well as outside the Parliament that Government cannot deny its own responsibility. So, due to this pressure, the first UPA

Government amended that clause. It was stated there, they amended that clause, "The concerned State Government and the Central Government". So, the 'Central Government' entered here. "The concerned State Government and the Central Government shall jointly endeavour to provide access to electricity to all areas including villages and hamlets through rural electricity infrastructure", it was a new amendment, "through rural electricity infrastructure and electrification of households", that means, all houses. In this background, the National Electricity Policy was declared in 2005. What was that? The clause 1.2 says electricity is an essential requirement for all facets of our life. It has been recognized as a basic human need, Sir, I repeat, as a basic human need. It is a critical infrastructure on which the socio-economic development of the country depends. Supply of electricity at reasonable rates to rural India, I repeat, to rural India at reasonable rates is essential for its overall development". So, an impression was created that the Government of the State attributing to the rural people. But, unfortunately, when the Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojna came out, which came out with much fanfare, in this period, Government inserted a condition. What is the condition? Undertaking by States, not by the Central Government, undertaking by the States for supply of electricity with minimum electricity of 6 to 8 hours in the RGGVY was taken. Sir, are they second class citizens? I would like to ask the hon. Minister, through you, are the rural people second class citizens? Should they be treated like that? The Electricity Policy stated that they will be denied of the basic human need. They will be regarded as just one hon. Minister, who probably resigned yesterday, said that such type of

people are cattle-class. Is it the uniform understanding of the Congress Party to think like that?

Coming to the question of nuclear power, Sir, we never opposed nuclear power generation in our country. In fact, the Left Front Government of West Bengal is trying to install a nuclear power station in West Bengal in East Midnapur district. It is being opposed by a partner of the ruling UPA Government.

(Contd. by ysr-2j)

-SK-NB/YSR-VNK/2.40/2J

SHRI SHYAMAL CHAKRABORTY (CONTD.): We are still trying it. But what did we oppose actually? We opposed the very agreement which endangered our sovereignty and our own case of independent nuclear power generation. I am referring to the Hyde Act here. What is the fate of utilization of our own resources? Our great scientists are saying it again and again to the people of India that our country is very rich in Thorium. We have huge reserves of it. Nuclear energy based on Thorium can be generated which will continue for 400 years. Every year we can generate 4 lakh mw of power. What is the position of our three-stage nuclear energy development programme? Where does it stand now? That should be cleared by the Ministry.

Another point towards which I would like to draw the attention of the hon. Minister is this. They have taken a very good decision. If any State agrees to set up hydel power project, there is a very good incentive for it. The States are coming up to explore the possibility of hydel projects. We are rich in resources. Why should not a new thermal power station be given that opportunity?

National and private power stations are coming up in various States. If you give the States this guarantee that they will get the incentive of 12 per cent power free of cost for their own people then many States will come forward and start to solve the power crisis. I am referring to the case of West Bengal. Power stations with a capacity of 3,000 mw electricity generation are going to be set up in West Bengal by the DVC. But the DVC authorities are denying the States their right. They are saying that they will not set it up here but in other parts of West Bengal. This is creating agitation among the people. The DVC is under the Central Government. It is overseeing not just power stations. It is working on utilization of water resources. The DVC was created in the 50s by Jawaharlal Nehru. A Committee was formed at that time. One of its recommendations was that there should be a good number of reservoirs. They suggested Balpahari reservoir. But it has not been done. It is incomplete. In the summer season, reservoir cannot give sufficient water to the peasantry. In the rainy season, we see that they have to release abundant water.

(Contd. By VKK/2K)

-YSR/VKK/2k/2.45

SHRI SHYAMAL CHAKRABORTY (CONTD.): So, five or six districts in Bengal are devastated by water. If the Balpahari reservoir can be constructed, if the decision is taken, the people of West Bengal may overcome this suffering of every year.

Sir, here, I would like to refer to River Hwang Ho of China which is said to be sorrow of China. Now, Damodar is said to be Hwang Ho of Bengal. Sir, the Damodar Valley Corporation, every year, drowns 5-6 districts, as I have already

told you. Now, the people sarcastically call it 'Drowning Valley Corporation'. Every year, 5-6 districts are being devastated by floods, by the release of water from the reservoir.

Sir, I request the hon. Minister, through you, that please visit West Bengal. You see the suffering people. Don't be a *Dhritarashtra*, sitting here. Go to the people there. Please listen to their agony. Please try to remove the tears from the eyes of the affected people, particularly peasantry and rural people. You try that. After all, what do you mean by a Government or a Minister if this thing goes on year after year? Sir, with this, I conclude. I thank you for giving you me so much time.

(Ends)

SHRI SANTOSH BAGRODIA (RAJASTHAN): Honourable Deputy Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to participate on the Discussion on the Working of the Ministry of Power. I was listening with rampant attention the speech and points made by my hon. colleague from the Communist Party. All of us know that the need for power for any kind of development is a must. Either it is required for industries or it is required for agriculture or it is required for domestic use, education, health, etc. This morning, we had some problem in the House also and I thought the House may not run because there was no power. Now, if we need nine or ten per cent GDP growth, which the present Government wants, and rightly so, I would say that we have to think of 15 per cent GDP growth. Then only the advantages of the growth can go to the last man in the country and the

last man in the pyramid. Then only, we can surpass the development of developed countries like the USA or European countries. But, that cannot happen without the development of power.

(**THE VICE-CHAIRMAN** (**PROF. P.J. KURIEN**) **in the Chair.**)

For nine or ten per cent GDP growth, we need growth of power to the extent of 15 per cent and when we need that kind of growth, we will have to find out all different avenues. It may be thermal, hydel, solar, wind, lignite and nuclear power. (Contd. By RSS/2L)

RSS/2L/2.50/

SHRI SANTOSH BAGRODIA (**CONTD.**): We cannot stop for any consideration. Of course, sovereignty of the country is super most in everybody's mind. Even to think for a second that anybody in the country thinks differently, will be wrong on my part and wrong on the part of anybody sitting here or sitting outside. We have to make every effort to increase the production of power. The achievements, what the Government has made, the hon. Minister is sitting here, he will like to speak. But a few things, the major things that are within one Plan, that is, 11th Plan, at least, we dared to have a target, so much big target which was not even thought over during the last so many Plans taken together, that is the vision of this Government from 2004 onwards. Unfortunately, whenever Congress Governments were not there, the development went down steeply, and to recover from that, the Congress Governments had to take more effective steps.

Sir, despite all this, I cannot but mention a few things for the information of the hon. Minister which he already knows, but we need more care, probably,

more monitoring. For example, in the Eleventh Plan itself, that is, 2007 to 2012, the total power capacity was expected to increase to 78,700 megawatt. But if you see the results, Sir, under the Central Government, we wanted 37,000 megawatt, up to 31.12.09, we could get only 5,000 megawatt, and the plants for the rest which is under construction is also 16,000 megawatt. That means the total target was 37,000 megawatt, and even if believing that under construction plants will come into production, we can reach 21,000 megawatt, there will be a shortfall of a large quantity of about 16,000 megawatt. Pardon me for saying this that this kind of achievement cannot be accepted as a satisfactory achievement. Even if as I said within one last year, we have achieved much more than many other previous years, but does it give us full satisfaction? In the case of States--my colleague has already left, it appears--the target fixed based on the advice of the States was 27,000 megawatt. Actually, what we have actually achieved is only 9,000 megawatt, and 12,000 megawatt is in the pipeline. Here also, there is a shortage of 6,000 megawatt.

Coming to the private sector, the target was 15,000 megawatt, the target achieved is 5,000 megawatt, and in the pipeline under construction, as per the information given by the Ministry, is 15,000 megawatt.

(contd. by 2m)

-RSS-TMV-MCM/2M/2.55

SHRI SANTOSH BAGRODIA (CONTD.): There is a surplus of 5,000 megawatts. It didn't matter who produces the power, whether it is the public sector or the private sector or the joint sector, if the power produced is used for

the benefit of the country. The hon. Minister has to take a decision on how we can improve upon this performance position. I would just mention about the Budget for 2009-10. The original Plan Budget was Rs.9,230 crores. It was reduced to Rs.6,814 crores in the revised Budget. In the Budget for 2010-11, it is Rs.10,630 crores. I am happy because it is nearly double the revised Budget. I request the hon. Minister to start planning for the Twelfth Plan and for 2010-11, and to explain to us whether we are going to spend this Rs.10,000 crores or, again, we will come back to Rs.6,000 crores. In this process, what is happening is that when an ordinary citizen knows that so much of power is available, he starts planning. He decides to set up a hospital or he decides to set up an industry or he decides to increase his agriculture production. He puts up many electric equipment. In the end he thinks that there will be power. But if we are not able to achieve that, they don't get power. There is an indirect national loss and wastage of capital which could have been used otherwise. I just wish my hon. colleague had been present here. He has mentioned about the Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana and he has mentioned that it is not everything. I don't think that anybody has stated that this Yojana is everything. This is a very ambitious Yojana and through this Yojana the Government has taken the full responsibility. He has mentioned that the Government has not taken the responsibility. Then, who else has taken? I don't think that he or his party can take this responsibility. Obviously, the Government has to take the responsibility. But the responsibility of his own State has to be there. What is its achievement? If we look at the all India figures, we will find that for 2009-10 an amount of

Rs.6,300 crores had been allocated and the Revised Estimate was Rs.4,296 crores. In the current Budget, we have increased it to Rs.4,852 crores. I request the hon. Minister to kindly ensure that the money allocated is spent. Then, all this kind of criticisms which are coming from the opposition side will automatically stop. It is not Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana alone. There is APDRP also where, instead of Rs.66 crores in the revised Budget, we have added more to it. This time it is Rs.100 crores. It is for village electrification. Even the PFC has given loans under this Scheme. An amount of Rs.1,477 crores had been allocated for giving loans under this Scheme and it has been increased to more than double in the current Budget, that is, Rs.3,230 crores.

(Contd. By 2N/VK)

VK/2N/3.00

SHRI SANTOSH BAGRODIA (CONTD): Why I am giving these figures is because my hon. colleague has mentioned that the Government is not taking the responsibility. How does the Government take the responsibility? They have taken full responsibility. From whatever source they can get funds, they are making use of that for this Yojana so that the villages in this country can be fully electrified.

So far as thermal power is concerned, many big projects have been sanctioned. There is no doubt about it. In fact, eight ultra mega power projects have also been sanctioned. Out of these eight projects, four are in the process. But the other four, that is, Chhattisgarh, Tilaiya, etc., do not have environment clearance. My suggestion is, if you want faster growth of production of power,

please decide the project at a particular site, whether thermal or hydel, and try to get the clearance from the Ministry of Environment, try to get pollution clearance from the Pollution Board and then offer it either to the PSUs or to the private sector. In this way, it will move very fast; otherwise, we go on planning, but it gets stuck at one place. Clearance does not come for two years, three years or four years. Obviously, the entire blame comes on you that you have planned it but you have not been able to achieve it. But if you take all these clearances yourself, nobody will blame you because things will move faster. It will be more realistic. After all, this is a coordinated effort of the entire Government. The entire Government is responsible. I request you not to leave it to private people or the bureaucracy to delay the projects like this. Out of the annual target of 13,000 MW additional thermal power capacity, by December, 2009, we could add only 6,000 MW, which is less than 50 per cent. This is happening not because of lack of resources. I don't think the efforts of the NTPC or the NHPC are inadequate. But the system is such that delays are taking place. That delay has to be avoided. You have to find out a way so that the time period can be reduced for all the other sanctions which are required. Supposing, if the Chhattisgarh Project cannot be done because of environment reasons, then forget about that. Let us think of something else. I will go a step further. Give 20 or 30 proposals to the Ministry of Environment. Let them suggest that these are the places where we will give clearance and you take up only those projects. Take, for example, coal mines. The Coal Minister is sitting here. We allot coal mines either to the private sector or to the public sector, but it does not start for seven years or eight years

or nine years because clearances are not coming. You can't hold him responsible for that.

(Contd. By 2O)

RG/3.05/2O

SHRI SANTOSH BAGRODIA (**contd.**): There also, I would request the hon. Coal Minister, who is sitting here; please take the clearance and then allot it. Then, the allottee will be responsible. He will have no excuse for not doing things.

Sir, in case of thermal, we have gone far ahead. It is good and I congratulate both the Ministers sitting here. But one sad thing, which is in my mind, which I would like to mention here, is that we are taking care of all big, big projects. But, unfortunately, we are forgetting our small brethren. All over the country, there are lakhs of them who need 25 MW, 50 MW or 100 MW. There are a number of small industry clusters. And to those clusters, we neither give them power -- forget about quality power -- nor do we allot them coal. That is the only fuel which can be transported to those places. They call it Captive Power Plants (CPP). I would request the hon. Minister to go out of the way to help these small units. The total requirement in the country will not be more than 3,000-4,000 MW, which we give to one party. Instead of that, this can be distributed to lakhs of parties. They will really produce, and they will produce faster. They will generate more employment. That is how the small industries will start functioning. And that is the only way for survival of those small industries. As it is, they are finding it difficult to survive, and this constraint has put them into more difficulties. I would request the hon. Minister; you can't have the same procedures of C.As.,

recommendations, probably, from the Ministry concerned, recommendations from the Power Ministry, and then give them one lakh tonnes coal for the year. These people cannot come to Delhi. You cannot expect them to run to Delhi and follow it up. Why is it that something cannot happen automatically, at least, for these small people, more so, when this Government is meant for *Aam Aadmi.* Please formulate a policy by which these small manufacturers can get the benefit within a time-frame, and they don't have to run from pillar to post to get permissions.

Coming to hydro power, the annual target was 850 MW. For additional hydro capacity, we could only get 40 MW. Again, it is a question of clearance. In fact, the structure is not there; clearance does not come. My hon. colleague mentioned about DVC. I find from DVC's record that whatever target they have put, they have achieved it. They have installed it; they have done a good job. The DVC is a national organization, and it is a commercial organization. They can sell to West Bengal, or, they can sell to anybody in the country. I have no objection to it. If they find it economical, they can give it to anybody as per the law. But if you fine them, then, I don't think this will be in the right spirit in the federal system.

(Continued by 2P)

TDB/2P/3.10

SHRI SANTOSH BAGRODIA (CONTD.): Now, I would like to come to nuclear energy. Broadly speaking, Sir, all over the world, people know about minerals whether it is coal or water resources. Though hydel power is known as a

renewable energy source, but there is a limit. There is too much limit for coal. First, there is the forest. You have the problem of removing the forests, and then getting the coal out. Then, there is the question of rights of the tribals who live in those forests. Sir, if you go to USA, you will find that the original people who were actually the inhabitants of USA are no more there. They have been completely either cordoned off or their population has come down to negligible percentage. Go to Australia, we don't even know what is happening to the original people of that country. But, I am glad to mention here that our country is more civilised than any of these countries, where our tribals are fully taken care of. I salute our forefathers; I salute the leadership of Congress Party from day one, from Pandit Jawaharlal Nehru; maybe even earlier, Mahatma Gandhi, Indira Gandhi and now under the leadership of Dr. Manmohan Singh, under the leadership of Soniaji and Rahulji, we are looking after the interests of these tribals. Sir, a number of times people asked me about land acquisition. How do we acquire the land in these forests? My suggestion to the hon. Minister here is this. He said it is done either for the hydel projects or because a number of villages are drowned. You see, either it is for mines or for some other things. Everything has got a timeframe. Thirty years, forty years. After that, the reserves will be all over. Please don't take the ownership of the land from these tribals. You will have no difficulty. The problem arises because we are asking for the ownership of land. Take it on lease; give a definite employment to those people immediately. Pardon me saying this, our own Government, at a number of places, including Bikaner in Rajasthan, has still not given employment for 15 years. Obviously, there will be an agitation in the

minds of these tribals. If you make them part of the development, there will be no difficulty. But, in saying all this, I have deviated a little. It is because this subject of land acquisition is very dear to me. I think it should not have taken place the way it has taken place. That is why I mentioned it. Because fuel is a big problem, the Government of India has taken a conscious decision to acquire coal mines outside the country. They have taken some mines in Mozambique. I think they are taking more in Australia. But you cannot take what you call hydel power or you cannot take water from Australia.

(Contd. By 2q-kgg)

kgg/2q/3.15

SHRI SANTOSH BAGRODIA (contd.): Maybe, you can have some hydel power projects in Nepal and bring that power here. But, you cannot bring the water itself here. So, in view of the shortage of fuel supply, coming to the nuclear energy, UPA-I had the courage under the leadership of Soniaji and Rahulji and under the Prime Ministership of Dr. Manmohan Singhji, even at the cost of the Government, it decided that we must have the nuclear agreement. We may lose the Government, but we cannot lose the country. We need more power.

He is talking about the country's sovereignty. Let him pinpoint even one clause in that agreement where the question of sovereignty is compromised. Rather, it is because of the power of the Government of India, it is because of the confidence of our Government that the U.S. had to change its rules. They had to make the agreement as per our choice and not as per their choice. They did it.

I can understand that when this kind of agreement was being made, most of my communist friends are missing now... (Interruptions)

SHRI MOINUL HASSAN: What is this?

SHRI SANTOSH BAGRODIA: I have seen you, you are there, I know that. I am talking about the one who spoke especially, I wish he were here.

I can understand their reservations. My colleague has mentioned that the West Bengal Government itself want to have a nuclear power plant. (Time-bell) Sir, I will not take more than five minutes.

Sir, I can understand the Leftists opposing this because, unfortunately, they would bow their heads before the photographs of people who do not belong to our country. I do not care.

SHRI MOINUL HASSAN: I do not agree with this. This is absolutely a blame. It is not related to the subject.

SHRI SANTOSH BAGRODIA: I am not blaming. Do you not promote Marxism? Do you not have Stalinism? Do you not follow Maoism? They do not belong to this country. You may say that you do not belong to it, it is fair enough. You say CPI (Marxism). What does it mean? Anyway, I can understand their allergy to the U.S. But I cannot understand why BJP has allergy with the U.S. Why did they oppose? There is no logic for them to oppose when the nuclear deal was being passed. This is what is worrying me even today, despite the Bill having been passed.

Sir, with this, I only quickly give a few suggestions. I have already mentioned those in my earlier comments. I request the hon. Minister to have a

single window clearance, after clearance from environment, after making agreement for land, etc., if possible. Then, the projects would go faster. Similarly, about coal mines, the Minister is here, if it can happen, the projects will be much faster.

There are a number of points which we can raise. Sir, just in honour of the Minister, I must mention that in every Plan we are targeting for more and more. The last Plan achievement was better than any other Plan.

(Contd. by kls/2r)

SCH/KLS/2R-3.20

SHRI SANTOSH BAGRODIA (CONTD): This credit I will give. But my only worry is that it was not as good as we wanted. Sir, in one Plan only proposed addition was higher than the total of the last of the Plan taken together. So, I congratulate the hon. Minister and I hope that in the coming Plan, we will be able to achieve what we are going to plan. Let there be no excuses. The country does not need excuses, the country wants achievements. Thank you, Sir.

(Ends)

श्री भगत सिंह कोश्यारी (उत्तराखंड): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आपने मुझे बिजली विभाग की वर्किंग पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अपने दोनों पूर्ववक्ताओं को सुन रहा था। अगर मैं पहले बोलता, तो शायद बहुत सी वही बातें बोलता, जो वे बोले, इसलिए मैं प्रयास करूंगा कि जो बातें वे कह चुके हैं, मैं उन बातों को न दोहराऊं। हमारे देश के अन्दर आज बिजली की जो स्थिति है, आज सुबह मैं देख रहा था, विद्युत मंत्री जी यहीं पर थे और कम से कम आधा दर्जन बार बिजली ने काफी आंख-मिचौनी

की। शायद वह इस बात को बताने जा रहे थे कि अगर संसद में इन सब चीज़ों की हालत सही नहीं है, लोक सभा और राज्य सभा में सही नहीं है, तो बेचारी ग्राम सभा का क्या हाल होता होगा? थोड़ा सा ही सही, लेकिन सुबह यही संकेत बिजली यहां पर दे रही थी।

मान्यवर, यह एक इतना महत्वपूर्ण विषय है, मुझे अभी रहीम जी का एक दोहा याद आ रहा था, उन्होंने कहा है, "रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून"। आजकल पानी तो आप बिस्लरी या एक्वा की बोतल में ले करके जेब में रख सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं, लेकिन बिजली को तो आप अपने जेब में भी नहीं रख सकते। इसे तो आपको पावर हाउस में ही पैदा करना होगा और पावर हाउस से ले करके आपको घर-घर तक पहुंचाना होगा। यह समाज के लिए बहुत अधिक आवश्यक चीज़ है। हम लोगों ने इसके लिए जो लक्ष्य रखा है, अभी मैं उसी को देख्ा रहा था। इस देश के अन्दर बिजली की हमारी कुल स्थापित क्षमता लगभग 1,56,783 मैगावाट है। अभी तक इसमें से ज्यादातर बिजली, यानी 1,00,000 मैगावाट से अधिक बिजली हमें थर्मल पावर से ही मिलती है। हाइड्रोपावर से मिलने वाली बिजली का प्रोडक्शन कुल मिलाकरके 36,885 मैगावाट है, न्यूक्लियर पावर से मिलने वाली बिजली का प्रोडक्शन लगभग 4,120 मैगावाट एवं अन्य स्रोतों से कुल मिलाकर 15,000 मैगावाट के आसपास बिजली मिलती है।

इसके साथ ही अभी मैं अन्य देशों के बारे में भी देख रहा था। मैं हिन्दुस्तान का कम्पैरिज़न चाइना से कर रहा था, चाइना हमारा पड़ोसी देश है। अगर अपने देश के अन्दर मैं आपको केवल उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर के बारे में बताऊं, मैदानी भाग की बात मैं छोड़ भी दूं, तो केवल इन चार प्रदेशों से ही आपको 1,00,000 मैगावाट से ऊपर हाइड्रोपावर से बिजली मिल सकती है। इन प्रदेशों में इतनी अधिक संभावनाएं हैं। लेकिन आज आजादी के 63 साल के बाद भी स्थिति यह है कि हम हाइड्रोपावर पोटेंशियल से केवल 36,000 या 37,000 मैगावाट ही बिजली उत्पन्न कर पाते हैं। हमारे बगल में ही चाइना है और वह हाइड्रोपावर से 75,000 मैगावाट के लगभग बिजली जनरेट कर

रहा है। यह तो मैं केवल मेजर हाइड्रोपावर जनरेटर्स की बात कर रहा हूं, स्मॉल हाइड्रोपावर्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं।

(2s-psv पर जारी)

-SCH/PSV-SSS/2S/3.25

श्री भगत सिंह कोश्यारी (क्रमागत): यह मैं उनके major and mega power plants की बात कर रहा हूँ। उनके जो छोटे-छोटे small hydropower plants हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। वह आज केवल अपने major and mega power plants से अगर 75 हजार मेगावाट बिजली पैदा करता है तो वहीं हमारे यहाँ केवल 36 हजार मेगावाट ही hydropower पैदा होती है। मैं सोचता हूँ कि इसमें कहीं-न-कहीं हम लोगों की प्लानिंग में दोष है।

माननीय मंत्री जी, शायद हो सकता है कि मैं अपने बारे में बोलूँ तो वह अच्छा नहीं लगे, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। THDC का जो टिहरी प्रोजेक्ट है, उसके बारे में आप जानते हैं कि वह पिछले 30 सालों से कैसे पड़ा हुआ था। उत्तरांचल बनते ही एक साल के अन्दर न केवल उसकी rehabilitation की समस्या हल हुई, उसके tunnels भी बंद हुए। उसकी सारी समस्याएँ एक साल में कैसे हल हो गईं? उसका एक ही कारण था कि प्रदेश में हम लोग थे तो केन्द्र में जो सरकार थी, जैसे केन्द्र में हमारे विद्युत मंत्री हों, विद्युत राज्य मंत्री हों या स्वयं उस समय के प्रधान मंत्री और गृह मंत्री हों, सब के प्रयास से वहाँ 30 सालों से चली आ रही समस्याएँ एक साल के अन्दर ही हल हो गईं। आखिर आप कभी यह सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो गया? माननीय मंत्री जी, मैं आपसे यह तो नहीं कहूँगा कि आप रात-रात भर मत सोइए। Don't have sleepless nights. आप तो बहुत समझदार हैं, अनुभवी भी हैं। बिना दर्द के कुछ नहीं होगा। गंगा को बंद करने जैसा पाप मोल लेना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए शायद सरल नहीं था, लेकिन उस पर देश के 7 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, तो

जब हमने एक बार determination किया तो वह समस्या हल हो गई। मंत्री जी, मैं आपसे एक अनुरोध कर रहा हूँ। इसे आप ध्यान से सुनिए। उसका जो 3rd part है, 400 मेगावाट का कोटेश्वर का, उसमें मैंने अपने सामने सारी चीजें समय से clear करवाई थीं। उसी के साथ-साथ मैंने उत्तरांचल गवर्नमेंट के मनेरी भाली सेकंड के लिए 800 करोड़ रुपए आप ही के सेंटर से मंजूर करवाया था। आज वह 320 मेगावाट की योजना 2 सालों से चल रही है। बागड़ोदिया जी, आप इसे ध्यान से सुनिए। आप इनकी बहुत तारीफ कर रहे थे। आप इसमें 'but' बहुत लगा रहे थे। ...(व्यवधान)... वैसे आप 'but' ठीक ही लगा रहे थे। शायद एक ही पार्टी में होने के कारण उनकी तारीफ करना आपका फर्ज था। अब क्या किया जाए, वह आपकी पार्टी में हैं। यह आपकी मजबूरी थी, लेकिन विषय क्या था? आप जितने 'but' लगा रहे थे, वे 'but' ही ज्यादा सही थे, वे 'किन्तु' तथा 'परन्तु' ही ज्यादा सही थे। मंत्री जी, आप जरा अपने अधिकारियों से कहिए कि कोटेश्वर के बगल में हम मनेरी भाली सेकंड पूरी करके उससे दो सालों से बिजली पैदा कर रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है, सब कुछ है फिर भी 400 मेगावाट की कोटेश्वर योजना आज तक क्यों नहीं बनी है? उसमें से कब बिजली पैदा होगी, मैं नहीं जानता। उसमें से एक हजार मेगावाट का जो सेकंड है, उसका pump storage, जो PSP का था, वह आज तक शुरू भी नहीं हुआ है। जब आपके अधिकारियों से पूछते हैं कि क्या हुआ तो वे बताते हैं कि वह कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है। वह हिन्दुस्तान की सुप्रीम कोर्ट में ही तो है, किसी प्रीवी काउंसिल में तो नहीं है? मैं जानता हूँ कि टिहरी के मामले में हमारे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कितने लोग गए। They all supported us. वह एक genuine काम था, इसलिए सबों ने उसे सपोर्ट किया। लेकिन आखिर ऐसा क्या कारण है कि वहाँ अभी तक पिलर भी नहीं पड़े? इसका सीधा अर्थ यह है, मैं आपको एक particular उदाहरण दे रहा हूँ कि कहीं-न-कहीं हम लोगों की ओर से slackness है। हम यह नहीं जानते कि अगर एक बार में आप किसी योजना को एक साल पीछे करते हैं, दो साल पीछे

करते हैं या तीन साल पीछे करते हैं तो उसके पीछे होने से वह कितनी महँगी हो जाती है। एक ओर हम बिजली के लिए रोते हैं वहीं दूसरी ओर उसकी कीमत तिगुनी हो जाती है। अभी बागड़ोदिया जी कह रहे थे कि where is that monitoring? क्यों नहीं होता है ऐसा? इसका सीधा अर्थ यह है कि कहीं-न-कहीं हम सब लोगों ने ये सारा कुछ अधिकारियों पर छोड़ दिया है। मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों का कितना लक्ष्य था और हमने कितना पैदा किया? इस बात को बागड़ोदिया जी भी बोल रहे थे। मैं उतना ज्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन Eleventh Five Year Plan में आपका लक्ष्य 78 हजार 700 मेगावाट था। आपने इसे घटा कर 62 हजार 374 मेगावाट कर दिया। इसे आपने 62 हजार किया है और इन तीन वर्षों में आपने 20 हजार 682 मेगावाट ही पैदा किया है। वह 27 हजार के लगभग भी नहीं है, जो शायद एक सदस्य अभी यहाँ बोल रहे थे।

(डी0एस0/2टी पर क्रमशः)

-PSV/DS-NBR/3.30/2T

श्री भगत सिंह कोश्यारी (क्रमागत): कुल मिलाकर आपने 20682 मेगावाट पैदा किया है। अब आप घटे हुए 62374 मेगावाट में से दो सालों के अंदर 41692 मेगावाट पैदा करना चाहते हैं। मैं सोचता हूँ कि आपके पास ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप इसमें 42000 मेगावाट पैदा कर लेंगे। क्योंकि जो ढंग दिखायी दे रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप पैदा करें, यह अच्छी बात है। अगर आप 78000 मेगावाट पैदा कर देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आज हम सब लोग, मैंने कहा कि अगर चीन इतना अधिक कर पैदा सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? मैं जब टिहरी की बात करता हूँ तो पाता हूँ कि वहाँ एक लाख से भी अधिक लोगों को rehabilitate करना पड़ा और आप 22000 मेगावाट पैदा करने की बात कर रहे हैं! उनको पांच साल भी नहीं लगे और उनके यहाँ 22000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है और हमारे यहाँ की सारी योजनाएँ - अभी मैं अरुणाचल प्रदेश गया था, वहाँ भी वही रोना होता है। अगर हिमाचल प्रदेश जाएँ तो वहाँ भी वही रोना होता है और अगर उत्तराखंड जाएँ तो वहाँ भी इसके

लिए वही रोना होता है। मैं और विषय पर नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे साथियों को इस पर बोलना है। मैं यह बोल रहा हूँ कि हमारे पास पानी का जो renewable source है, आखिर उस पानी का भी हम लोग क्यों नही सदुपयोग कर रहे हैं? हम उसका उपयोग आखिर ठीक से क्यों नहीं करा पा रहे हैं? इसका सीधा अर्थ यह है कि उसमें कहीं न कहीं हम सब की लापरवाही है। मैं माननीय मंत्री जी यह कह सकता हूँ कि जब तक आप इस पर ठीक से ध्यान नहीं देंगे तब तक यह नहीं होगा।

मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ और अभी बागड़ोदिया जी ने बोला होगा कि आपके जो Central PSUs हैं, इस पंचवर्षीय योजना में उनका बिजली उत्पादन का लक्ष्य 35824 मेगावाट था। Right from NHPC और अन्य PSUs जो आपने बना रखे हैं, उनका लक्ष्य 35824 मेगावाट का था, जबकि तीन साल में कुल उत्पादन कितना हुआ? क्या आपको यह पता है? यह उत्पादन 5700 मेगावाट हुआ। अब आप बताइये कि आपके PSUs के ये हाल हैं! आखिर ऐसा क्यों है? क्या इनकी कोई accountability नहीं है? अगर नहीं है तो why not wind them up? आपने इन्हें क्यों बना रखा है? आपके पास 35000 मेगावाट का लक्ष्य है और उनके पास पूरे फंड हैं जबकि किसी प्राइवेट संस्था को इस काम में किसी बैंक के साथ जाना पड़ता है, आपके PFC के यहाँ उनको सिर मारना पड़ता है और फिर भी यह पूरा नहीं हो पाता है? इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारी बिजली उत्पादन का जो लक्ष्य है, जनता के अंदर एक प्रकार से जो बिजली के लिए त्राहि-त्राहि हो रही है, इस संबंध में आप इस सदन को निश्चित रूप से कोई एक आश्वासन दें। अभी आप जो जीडीपी की बात कर रहे थे। देश की प्रगति की चाहे कोई भी बात हो, आज बिना बिजली के देश की प्रगति हो ही नहीं सकती है। आपका यह जो कोल वाला विषय है, यह बहुत कठिन है। मैं आपसे एक बार और निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इसको ज़रा देखें। मैं यह देख रहा था कि यू.एस.ए., जिसकी आबादी हमसे एक-चौथाई है, उसका बिजली उत्पादन 4167 बिलियन किलोवाट है। चीन का बिजली उत्पादन 3256 बिलियन किलोवाट, जापान का 1195 बिलियन किलोवाट और रूस

का 1016 बिलियन किलोवाट है, जबकि भारत का उत्पादन केवल 665 बिलियन किलोवाट है। मैंने जिन देशों के नाम लिये, अगर उन सब की आबादी मिला दें तो भी वह हिन्दुस्तान की आबादी से कम होगी जबकि हमारी यह स्थिति है। आपने बहुत सुन्दर लक्ष्य रखा है। आपने बिजली के लिए राजीव गांधी मिशन और न जाने कितने मिशन्स बना रखे हैं। आपने यह तय कर रखा है कि 'Power to all by 2012'. ऐसा ही है न, मैं गलत तो नहीं बोल रहा? जबकि आज हालत यह है कि हम गांवों और घरों को, जहाँ बिजली जा रही है, वहाँ 6 घंटे भी बिजली नहीं दे सकते, जहाँ बिजली नहीं जा रही है उसको तो छोड़िए। इस देश के अंदर जो लोग इस देश के बारे में सोचते हैं और जो इन विषयों का ज्ञान रखते हैं, आखिर क्या आपने कभी उनसे कोई अनौपचारिक बातचीत की या उनसे उनके suggestions मांगे और यह तय किया कि हम किस ढंग से इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं या हम उस दिशा में आगे कैसे बढ़ेंगे?

इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस संबंध में आप जितनी जल्दी काम करेंगे और आपके जो Ultra Mega Power Projects (UMPP) चल रहे हैं, मैं नहीं जानता कि वे कब तक पूरे होंगे, लेकिन जो sure and certain है, जो आपके सामने सरल है, मैं चाहूँगा कि आप उस पर जल्दी से जल्दी कदम उठाएँ। अभी बागड़ोदिया जी tribals के बारे में बोल रहे थे। सवाल केवल tribals का नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि आप जिसकी भी जमीन लेते हैं,

(2यू/एकेए पर क्रमशः)

Aka-usy/2u/3:35

श्री भगत सिंह कोश्यारी (**क्रमागत**) : जब आप बिजली के लिए जमीन लेते हैं तो उस समय आप कोशिश क्या करते हैं कि जिस भाव से आप जमीन सामान्य वैलफेयर स्कीम्स के लिए लेते हैं - अस्पताल, स्कूल या और अच्छे कामों के लिए लेते हैं, उसी भाव पर बिजली के लिए भी उनकी जमीन एक्वायर करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस बारे में एक नेशनल पॉलिसी बननी चाहिए कि अगर कमर्शियल प्रोजेक्टस के लिए जमीन एक्वायर की जाए तो उस जमीन के दाम सामान्य वैलफेयर स्कीम्स के लिए ली गई जमीन से दुगुने, चौगुने या और भी ज्यादा

हों और वे हो सकते हैं। आपको ध्यान होगा कि टिहरी समस्या का आपको जब समाधान करना था, मेरा नया-नया स्टेट था, लेकिन मैंने 15 करोड़ रुपया बाजार खाली कराने के लिए अपने स्टेट से दिया। मुझे उनसे कुछ नहीं लेना था, लेकिन मैंने इसलिए दिया कि वह एक नेशन की समस्या थी और आज उससे नेशन को, दिल्ली को पीने के लिए पानी मिल रहा है, आपको बिजली मिल रही है, इसलिए मैंने दिया। इसलिए इस पर आपको विशेषकर विचार करना होगा।

एक अन्य चीज के बारे में मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जितने भी हाइड्रो पावर जेनरेट करने वाले हिमालयन स्टेट्स हैं, इनकी समस्या यह है कि जब लीन ऑवर्स होते हैं, लीन पीरियड होता है तो इनकी बिजली कम हो जाती है। खुद के लिए भी कठिनाई होती है, बजाए बाहर देने के। तो ऐसी जगहों पर, जहां आपको पर्यावरण की दृष्टि से भी नुकसान न हो, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इन जगहों पर, इन स्टेट्स को आपको तत्काल गैस बेसड् बिजली प्लांट देने चाहिए, सब्सिडाइज्ड रेट पर देने चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए - चाहे वह असम हो, अरुणाचल हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो या जम्मू-कश्मीर हो। इससे उनका मॉरेल भी ऊंचा होता रहेगा। वे आपको पानी दे रहे हैं, अपने लिए पीने का पानी छोड़कर आपको बिजली के लिए पानी दे रहे हैं। इसलिए, इस प्रकार की व्यवस्था अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है कि इसमें आपको काफी सुविधा मिलेगी।

मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां विशेषकर पर्यावरण की समस्या है। मैं दो-तीन बिन्दुओं पर बात करके अपनी बात समाप्त करुंगा। लेकिन अगर अकेले पर्यावरण पर आपकी योजनाएं पांच-पांच साल तक लटकी रहेंगी, तो इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए, मेरा कहना है कि या तो आप उनको परमानेंटली बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए या एक साल के अंदर आप जो भी योजना बनाते हैं, उसे टाइम बाउंड करके पूरा कीजिए। पर्यावरण मंत्रालय भी आपका है, बिजली मंत्रालय भी आपका है, एक ही सरकार है, तो एक साथ बैठकर समस्याओं का समाधान क्यों नहीं होता है। इसलिए, मेरा

कहना है कि यह जो आप पांच-पांच साल तक पर्यावरण के नाम पर योजनाओं को लटकाए रखते हैं, तो कोई न कोई टाइम बाउंड, इस तरह का कोई कार्यक्रम रखिए ताकि पर्यावरण की समस्या जल्दी से जल्दी हल हो। पर्यावरण के नाम पर यदि आपने पहाड़ पर या आदिवासी क्षेत्रों में पानी के उपयोग को रोका और अगर हमारी योजनाएं रुकीं, तो मैं समझता हूं कि इसके कारण देश को बहुत अधिक हानि होगी। इसलिए इस पर भी तात्कालिक काम होना चाहिए।

तीसरी बात मैं आपसे रिहेबलिटेशन की समस्या के बारे में कहना चाहता हूं। जब आपका पोंग बांध बन रहा था, उसका लाभ राजस्थान को मिलना था। तो पोंग से जो लोग रिहेबिलेट होने थे, जो लोग डिस्प्लेस हो गए, उनके लिए राजस्थान में जमीन दी गई है और वे लोग आज भी वहां पर प्रसन्न हैं। जहां-जहां पर भी हमारी पानी की योजनाएं बन रही हैं, उनके रिहेबलिटेशन के लिए, योजना शुरु करने से पहले अगर आप जमीन एक्वायर नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि आपका जो लक्ष्य है, आप चाहे कितना ही बड़ा लक्ष्य रखें, वह लक्ष्य पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो स्टेट्स हाइड्रो पावर से लाभान्वित होने वाले हैं, मैं केवल हाइड्रो पावर ही नहीं कहता हूं, अभी उत्तर प्रदेश में तापीय बिजली का मामला था, प्राइवेट बिजली कम्पनी के बीच में कितना झगड़ा हो गया, सारी योजना खत्म हो गई। तो इस तरह से योजनाओं को पोलिटिकल बनाकर खत्म करने की जगह पर, मैं चाहता हूं कि एक ऐसी योजना आप सारे प्रदेशों के मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों से मिलकर बनाएं कि जो भी स्टेट्स इस हाइड्रो पावर से लाभान्वित होने वाले हैं, उन स्टेट्स में आप जमीन एक्वायर करिए, क्योंकि हिमाचल में जमीन आपको नहीं मिलेगी रेगुलेटिड करने के लिए, न हिमाचल में मिलेगी, न उत्तरांचल में मिलेगी, न जम्मू-कश्मीर में मिलेगी। इसलिए यह आवश्यक है कि इसको आप बिल्कुल तत्परता से और प्राथमिकता के आधार पर उन स्टेट्स में, जहां उनको लाभ होने वाला है, वहां उसके लिए जमीन का प्रबंध कराएं।

('2w/nb' पर जारी)

NB/2W/3.40

श्री भगत सिंह कोश्यारी (**क्रमागत**) : मैं समझता हूं कि आपके जो Transmission & Distribution losses हैं, वे भी कम होने चाहिए। आपने ARDP वगैरह योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन उनकी प्रगति संतोषजनक नहीं है। अगर आपके line losses and distribution losses ही 34% से अधिक हों, तो यह बहुत अच्छा दृश्य नहीं है। यदि इसको जल्दी से जल्दी सुधारा नहीं गया, तो ठीक नहीं होगा। मैं समझता हूं कि इसमें जितनी भी pilferage है, जितना भी नुकसान हो रहा है, उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए।

अभी हमारे माननीय सदस्य आपके विभाग की बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन दिक्कत यह है कि आपके विभाग वालों से यदि पूछा जाए कि योजना पूरी करने के लिए कितना पैसा चाहिए, तो वे कहते हैं कि 10 लाख करोड़ रुपए चाहिए और पूछिए कि आपके पास अभी कितना पैसा है, तो वे कहते हैं कि सब कर्ज़ा वगैरह मिलाकर 6 लाख करोड़ रुपए का इंतजाम हुआ है। आप पूछिए कि जब 3 साल के बाद भी केवल 6 लाख करोड़ रुपए का इंतजाम हुआ है, तो बाकी के 4 लाख करोड़ रुपए आप कहां से लाएंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आपको कहीं से रुपया मिल भी गया, जब आपके अंदर वह willpower नहीं है, तो वह काम कैसे होगा? वैसे तो आप Power Minister हैं, आपकी willpower ठीक ही होगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वह willpower कम है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बिना willpower के जो आपकी Power Ministry है, मैं समझता हूं कि It will be just powerless. आप तो हमारे बहुत ही सुलझे हुए और अच्छे मंत्री हैं, इसलिए कम से कम आप ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कीजिए कि आने वाले 2 सालों में आप यह कहें कि UPA-I was not UPA-I; UPA-II is UPA-I in the matter of power. अगर आप यह कह सकेंगे, तो मैं समझता हूं कि बहुत लाभ होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समाप्त)

श्री गंगा चरण (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, आपने मुझे इस बिल पर अपने विचार रखने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। आज देश के विकास के लिए ऊर्जा की बहुत जरूरत है, क्योंकि बगैर ऊर्जा के, बगैर पावर के हम 21वीं सदी में नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन हमारी सरकार ने विद्युत उत्पादन का जो लक्ष्य रखा है, उसको वह पूरा नहीं कर पा रही है। न्यूक्लियर बिल पास हुआ, लेकिन पिछले 2 सालों में उसमें कोई प्रगति नहीं दिखाई दे रही है। मैं मंत्री जी का ध्यान खास तौर से उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन होता है। वहां NTPC और NHPC द्वारा 9,172 मैगावाट बिजली बनाई जाती है तथा उसके बदले में उत्तर प्रदेश सरकार को 3,580 मैगावाट बिजली सप्लाई की जाती है। हमें 6,000 मैगावाट से ज्यादा बिजली की आवश्यकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, देश का सबसे बड़ा प्रांत है और यहां औद्योगिक विकास की अत्यंत आवश्यकता है। यहां के किसानों को बिजली की आवश्यकता है, व्यापारियों को बिजली की आवश्यकता है। आप देश का विकास चाहते हैं और उत्तर प्रदेश का विनाश चाहते हैं, यह कैसे संभव है? उत्तर प्रदेश, देश का सबसे बड़ा प्रांत है। हमारे द्वारा उत्पादित बिजली आप दूसरे प्रांतों को देते हैं और फिर उन प्रांतों से हम महंगे दामों पर बिजली खरीदते हैं। उत्तर प्रदेश द्वारा जो बिजली का उत्पादन होता है, उसमें से आप दिल्ली को 2,000 मैगावाट, पंजाब को 900 मैगावाट, राजस्थान को 900 मैगावाट, हरियाणा को 600 मैगावाट, जम्मू-कश्मीर को 600 मैगावाट, हिमाचल प्रदेश को 270 मैगावाट, उत्तराखंड को 415 मैगावाट और रेलवे को 100 मैगावाट बिजली देते हैं।

(2X/VNK पर क्रमशः)

-NB/VNK-PB/2x/03:45

श्री गंगा चरण (क्रमागत): यह सबसे बड़ी विडंबना है और फिर हम जम्मू और कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से महंगे दामों पर बिजली खरीदते हैं। हमें अपनी ही बिजली को प्रदेश में

उपभोग के लिए दूसरे प्रांतों से खरीदनी पड़ती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इसका क्या कारण है, क्या आप उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास नहीं चाहते हैं, क्या आपको उत्तर प्रदेश की किसानों की चिंता नहीं है? आप उत्तर प्रदेश को टारगेट बनाए हुए हैं कि उत्तर प्रदेश को जीतना है, तो आप उत्तर प्रदेश को ऐसे ही जीतना चाहते हैं कि वहां के लोगों को बिजली नहीं देंगे। जब वहां के लोगों को बिजली नहीं मिलेगी, तो पानी भी नहीं मिलेगा। वहां के उद्योग तबाह हो जाएंगे, कृषि क्षेत्र तबाह हो जाएगा और किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएगा। इस तरह आप उत्तर प्रदेश को जीतना चाहते हैं?

आपका लक्ष्य उत्तर प्रदेश में political power gain करने का है, वहां electric power बढ़ाने की नहीं है। चूंकि वहां दलित की बेटी कुर्सी पर बैठी हुई है, इसलिए आपका पूरा लक्ष्य है कि उस दलित की बेटी को कैसे हटाएं। यह आपकी पीड़ा है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने आपको पावर मंत्री बनाकर आपको भी powerless कर दिया है। आपको मुख्य मंत्री की कुर्सी से हटा दिया है और पावर मंत्री बना दिया है ..(व्यवधान).. आप दलित का एजेंडा छोड़ दीजिए कि हम दलित के हितैषी हैं। दलितों के साथ अन्याय करना छोड़ दीजिए ..(व्यवधान).. आपने नहीं दिया है। दलित की बेटी ने झोपड़ी में पैदा होकर अपनी मेहनत से पावर लिया है। किसी के रहमोकरम पर पावर नहीं लिया है। गरीबों की कृपा से पावर लिया है।

श्री रुद्रनारायण पाणिः 96 के विधान सभा चुनाव में समझौता हुआ था।

श्री गंगा चरणः आप विपक्ष में बैठे हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। मैं सत्ता पक्ष की बात कर रहा हूँ। महोदय, हमारा कहना है कि देश में जो आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद, माओवाद बढ़ रहा है, इसका भी सबसे बड़ा कारण यह है कि आप दलितों के साथ अन्याय कर रहे हैं। दलितों को सत्ता से वंचित करने का षडयंत्र रच रहे हैं और जब आप दलितों को सत्ता से वंचित करने का षडयंत्र रचेंगे, तो गरीब आदमी सत्ता के लिए हथियार उठाएंगे। आप कितने षडयंत्र रच रहे हैं, बिजली नहीं दे रहे हैं, सड़कों के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं, इनकम टैक्स के

छापे डाल रहे हैं, आय से अधिक के मुकदमे थोपे जा रहे हैं, ये सारे अत्याचार आप दलितों के ऊपर और पिछड़ों के ऊपर ही करेंगे।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के साथ अन्याय करना बंद कीजिए। उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव करना बंद कीजिए, वरना उत्तर प्रदेश की जनता आने वाली विधान सभा चुनाव में आपको सबक सिखा देगी। अभी आप दो दर्जन आए हैं, फिर एक दर्जन पर आ जाएंगे।

महोदय, बिजली मनुष्य के लिए प्राण तत्व है। आप कहते हैं कि हम देश को 21वीं सदी में ले जाना चाहते हैं, अमेरिका, चीन और यूरोप का मुकाबला करना चाहते हैं। क्या आप बगैर राज्य का विकास किए देश का विकास कर सकते हैं? मैं आपको आंकड़े देना चाहता हूँ कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं है, वहीं आप बिजली की कटौती कर रहे हैं। चण्डीगढ में 1446 मेगावाट बिजली की डिमाण्ड है और आप वहां 1446 मेगावाट बिजली देते हैं। दिल्ली में 22439 मेगावाट बिजली की डिमाण्ड है और आप वहां 22301 मेगावाट बिजली देते हैं।

(2y/MP पर क्रमशः)

MP/2Y/3.50

श्री गंगा चरण (**क्रमागत**) : हरियाणा की जो 29 हज़ार मेगावॉट की डिमांड है, वहां आप 25 हज़ार मेगावॉट बिजली की सप्लाई देते हैं, लेकिन यू.पी. की डिमांड जो 62 हज़ार मेगावॉट है, वहां आप 3380 मेगावॉट बिजली देते हैं। आप राजस्थान में पर्याप्त बिजली दे रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां आप बिजली में कटौती कर रहे हैं - 41 हज़ार मेगावॉट की जरूरत है, आप 3500 मेगावॉट बिजली दे रहे हैं। बिहार में, जहां आपकी सरकार नहीं है, वहां 9 हज़ार मेगावॉट की जरूरत है, आप 7 हज़ार मेगावॉट बिजली दे रहे हैं। क्या यह नाइंसाफी नहीं है? आप कह रहे हैं कि हम देश को इक्कीसवीं सदी में ले जाना चाहते हैं। आपने शपथ ली थी कि हम बगैर किसी भेदभाव के काम करेंगे, तो क्या यह भेदभावपूर्ण काम नहीं है?

आपने जो मेगा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट लगाने की बात की थी, उसमें हमारी मुख्य मंत्री, बहन मायावती जी ने मांग की थी कि बुंदेलखंड में एक मेगा पावर प्रोजेक्ट लगाया जाए, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट लगाया जाए। हम उसके लिए फ्री में ज़मीन देंगे, फ्री में पानी देंगे, फिर भी आपने यह प्रोजेक्ट यू.पी. को नहीं दिय। क्या यह यू.पी. के साथ नाइंसाफी नहीं है? आज माननीय सदस्यों को इस बारे में विचार करना पड़ेगा कि जो गैर-कांग्रेस शासित राज्य हैं, केंद्र सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है, चाहे वह पश्चिमी बंगाल हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो या उत्तर प्रदेश हो, इस तरह की भेदभावपूर्ण नीति से देश आगे नहीं बढ़ सकता है और मुझे लगता है कि आपका 2000... हमारे कोश्यारी जी कह रहे थे ....(समय की घंटी)... कि सबको हम बिजली देंगे। आपका लक्ष्य सबको बिजली देने का नहीं है, बल्कि इन राज्यों पर कब्ज़ा करने का है। आपकी निगाहें, जो आज गैर-कांग्रेसी राज्य हैं, उनकी कुर्सी पर लगी हुई हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर) : समाप्त कीजिए, आपका समय हो गया है।

श्री गंगा चरण : समय कैसे हो गया?

उपसभाध्यक्ष : आपका दस मिनट का समय था।

श्री गंगा चरण : कितने मिनट था?

उपसभाध्यक्ष : दस मिनट।

श्री गंगा चरण : दस मिनट नहीं, हमारा समय बाईस मिनट था।

उपसभाध्यक्ष : दस मिनट हो गए हैं। हम देखकर बता रहे हैं। आपका दस मिनट का allotment था, अब आप खत्म करें।

श्री गंगा चरण : सर, पार्लियामेंट की बिजली जा रही है।

उपसभाध्यक्ष : जल्दी खत्म करें।

श्री गंगा चरण : जब पार्लियामेंट की बिजली जा रही है, तो देश की बिजली का क्या हाल होगा? तो आज मैं अपने पावर मंत्री जी से यही कहूंगा कि पावर का डिस्ट्रिब्यूशन सही ढंग से

करें, भेदभावपूर्ण न करें और उत्तर प्रदेश को, जितनी डिमांड है, उस हिसाब से पर्याप्त बिजली दी जाए।

सर, ये बिजली में कटौती कर रहे हैं और आप समय में कटौती कर रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष : मैंने कोई कटौती नहीं की है। आपके दस मिनट थे।

श्री गंगा चरण : नहीं सर, हमारी पार्टी को 22 मिनट allotted थे, फिर भी आपने समय दिया, धन्यवाद।

(समाप्त)

उपसभाध्यक्ष (श्री तारिक अनवर) : श्री वीर पाल सिंह यादव, बोलिए। आपके भी दस मिनट हैं।

श्री वीर पाल सिंह यादव (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, बिजली विभाग की इस चर्चा में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। महोदय, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। बिजली की आवश्यकता पूरे देश को और सभी वर्गों को है। बगैर बिजली के हिंदुस्तान ठप सा हो जाता है। किसी भी क्षेत्र को ले लें, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे खेती का क्षेत्र हो, बिजली के बगैर कुछ भी नहीं है। जिस प्रदेश में कम बिजली की उम्मीद होती है, वहां लोग उद्योग लगाने बंद कर देते हैं। जहां बिजली की कमी होती है, वह प्रदेश उद्योग विहीन हो जाता है। अब तक जो पंचवर्षीय योजनाएं बनी हैं, अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि जब-जब इधर वालों की सरकार नहीं होती है, तो हर तरह का विकास ठप होता है और जब-जब सरकार आती है, तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है।

(2Z/SC पर क्रमशः)

-mp/sc/3.55/2z

श्री वीर पाल सिंह यादव (क्रमागत) : आजादी के बाद 10 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 11वीं चल रही है। अधिकतर पंचवर्षीय योजनाएं आपके ही पास में रहीं। विद्युत के मामले

में हम लोग अब तक कितनी पूर्ति कर पाए हैं, यह भी सबके सामने है। हम लोग योजना बनाते रहते हैं। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना बनी। पूरे देश में उसकी बड़ी तारीफ हुई - खासकर उन इलाकों में जहां बिजली देखने को नहीं मिलती थी। गांव के सुदूर इलाके जो थे, जहां गरीब रहते थे, किसान रहते थे, दलित रहते थे - लोगों को यह उम्मीद हुई कि ऐसी जगहों पर राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के नाम पर उनके यहां भी तार लग जाएगा और रोशनी हो जाएगी। उन्हें केवल रोशनी की जरूरत थी और खेत में काम करने के लिए पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए बिजली की जरूरत पड़ती थी। इस योजना के शुरू होने के बाद जो आंकड़े आए, उसमें गांवों का विद्युतीकरण होना दर्शाया गया। गांव में, देहात में - जो लोग ग्राम से ताल्लुक रखते हैं, वे लोग जानते होंगे कि जो ग्राम सभा होती है, उसमें कम से कम चार-छः मझरे होते हैं, छोटे-छोटे होते हैं। वे ग्राम सभा के नाम से नहीं होते, कोई गोटिया के नाम से और कोई किसी और नाम से होते हैं। अधिकतर उन मझरों में दलितों की बस्ती होती है, पिछड़ों की होती है, गरीबों की होती है। वे गांव के सुदूर इलाके में अलग बसा दिए जाते हैं। उनमें तार नहीं लगा है। जो मझरे हैं, उनमें तार नहीं लगा है। ग्राम सभाओं में जो बड़ी ग्राम सभाए हैं, उनमें विद्युतीकरण हो गया है, यह रिपोर्ट आ गयी है कि इस गांव का पूरा विद्युतीकरण हो गया है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जब ग्राम सभा का विद्युतीकरण हो, या जो रिपोर्ट ग्राम सभा के विद्युतीकरण के संपूर्ण होने की आए, तो यह जरूर सुनिश्चित करवाएं कि क्या उस गांव के समस्त मझरे जो हैं, उनका विद्युतीकरण हो गया है? वरना आपकी जो योजनाएं हैं, जो आपका लक्ष्य है, जो आपकी मंशा है - गरीबों को उजाले में बिठाने की, उनके यहां पर भी तार पहुंचाने की, दलितों और पिछड़ों को बिजली देने की, वह अधूरी रह जाएगी। अगर गांव के सभी मझरों में बिजली के तार नहीं जाएंगे तो राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का मकसद पूरा नहीं होगा। एक तो मेरा मंत्री जी से यह कहना था। दूसरा, यह सही है कि विद्युत मंत्रालय इस समय देश के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा जरूरी मंत्रालय हो गया है। एक मिनट भी आदमी बिजली के बिना

नहीं रह सकता। जैसे आज जब यहां चर्चा हो रही है और दो-तीन बार बिजली चली गयी तो बड़ी अकुलाहट लोगों में हुई। चाहे आदमी दफ्तर में बैठा हो, चाहे गांव में घर में बैठा हो। पहले हम लोगों पर इतनी मौसम की मार भी नहीं पड़ती थी, न ही इतने A.C. थे। आज पहले से बहुत ज्यादा फैक्टरियां हो गयी हैं। खेती में किसान के लिए डीज़ल महंगा हो गया है। उसे पानी की जरूरत होती है। अगर बिजली नहीं होगी तो किसान खेती नहीं कर पाएगा। अब गांव में भी टीवी और पंखा चलाने के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है। शहर में पहले से ही बिजली की बहुत जरूरत थी, अब वह और ज्यादा हो गयी है। बगैर बिजली के मनुष्य का जीवन अब एक मिनट भी नहीं चल सकता। ऐसे में विद्युत मंत्रालय की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गयी है। अब विद्युत मंत्रालय यह कहकर अपना पीछा नहीं छुड़ा सकता कि हमारे पास कोयले की कमी हो गयी है, या हम कोयला मंत्रालय के अधीन है। कई बार ऐसा हुआ है कि जो कोयले से बिजली बनती है, उसमें केवल एक-एक दिन का कोयले का स्टॉक रह गया है, जबकि कोयले का स्टॉक कम से कम एक महीना और 6 महीने का होना चाहिए। जहां पर विद्युत परियोजना लगी है, माननीय मंत्री जी को मालूम होगा कि कई बार वहां पर केवल एक दिन का स्टॉक रह गया।

(3ए-एमसीएम पर क्रमशः)

KSK/MCM/4.00/3A & GSP/4.05/3B

श्री वीर पाल सिंह यादव (क्रमागत) : अगर आपूर्ति नहीं आएगी, रेल विभाग की वजह से नहीं आएगी तो इसमें कोई दोषी रेल विभाग को नहीं ठहराएगा, कोयला नहीं मिलेगा तो कोयला विभाग को कोई नहीं देखेगा। यह तो विभाग दूसरों पर ही आधारित है, पूरा का पूरा विभाग दूसरों के ऊपर चलता है। आपने कहीं परियोजना लगाई और वन विभाग ने एन0ओ0सी0 नहीं दी तो इस कारण परियोजना 6 महीने लटक गई। जिस तरह से महंगाई हर चीज पर बढ़ रही है, मशीनरी पर, जमीन पर, उसकी बनवाई पर अगर परियोजना 6 महीने रुक गई तो पता लगा कि जितना पैसा आपने एलौट किया था उतने पैसों में वह परियोजना नहीं हो पाएगी। इसमें वन विभाग आड़े आता है, राज्य सरकारों पर भी कोई अंकुश नहीं है। आपने विद्युत

परियोजना लगाई और राज्य सरकार जमीन एक्वॉयर नहीं कर रही है और अगर जमीन एक्वॉयर कर रही है तथा वह अच्छी जमीन है, खेती के लायक जमीन है तो किसान आंदोलन कर रहा है। तो उस वजह से भी परियोजना लटक गई। यह बात वहां कोई कहने नहीं जा रहा है, न कोयला वालों से कहने जा रहा है, न रेल वालों से कहने जा रहा है और अगर गैस नहीं मिलेगी तो गैस वालों से नहीं कहने जा रहा है, यह सारी की सारी जिम्मेदारी आपकी है, आप किस तरह से सभी विभागों से समन्वय बनाते हैं सभी विभागों को और अपने विभाग को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए और जितनी मांग है देश में बिजली की, उसकी आपूर्ति हम कैसे कर पाएं, विद्युत मंत्रालय उतना उत्पादन कैसे कर पाए, यह केवल आपको सोचना है, आपके मंत्रालय को सोचना है, दूसरे मंत्रालयों से किस तरह से आप संबंध रखें और किस तरह से काम समय पर लेंगे, यह आपकी जिम्मेदारी है, इसके लिए आपको ही कुछ करना पड़ेगा।

माननीय महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से इतना और कहना चाहूंगा कि विशेषकर उन क्षेत्रों पर ध्यान दें जहां पर जनसंख्या अधिक है, बड़ा प्रदेश है और जहां बिजली की बड़ी भारी जरूरत है। उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान का आधा हिस्सा है और दिल्ली से सटा हुआ भी है। अगर उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए उसे अलग से आपको बिजली का इंतजाम करना पड़ेगा। जब माननीय मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, तो एक परियोजना लगी थी, गैस पर आधारित एक संयंत्र नोएडा में लगाया था। किसी कारण से, यह राजनीति हो सकती है या कोई और कारण हो सकते हैं, वह परियोजना ठप्प हो गई। अगर वह परियोजना बन गई होती तो उत्तर प्रदेश बिजली के लिए किसी का मोहताज नहीं रहता, बल्कि उत्तर प्रदेश की स्वयं की आपूर्ति होती और वह दूसरे प्रदेशों को भी सप्लाई कर सकता था। मगर आपस की लड़ाई में वह भी राजनीति की भेंट चढ़ गया। इस तरह से वह हाथ से चला गया। उत्तर प्रदेश को गैस पर आधारित और हिन्दुस्तान में जिन-जिन चीजों से बिजली पैदा होती है चाहे हवा से हो, चाहे पानी से हो, चाहे गैस से हो, चाहे जल से हो, किसी भी चीज की हिन्दुस्तान में कमी नहीं है।

अभी कोश्यारी जी नहीं है, शायद चले गए हैं, उन्होंने कहा था कि इच्छा शक्ति की कमी है, हमारे देश में पानी की कमी नही है, हमारे देश में हवा की कमी नहीं है, मगर कहां पर और कैसे उस हवा का, पानी का, गैस का, धूप का इस्तेमाल करें, यह तो सरकार पर और विद्युत मंत्रालय पर ही निर्भर करता है, यह तो आप ही करेंगे। आप यह कह कर नहीं बच सकते कि जब से हिन्दुस्तान आजाद हुआ है तब से थोड़े समय को छोड़कर इस देश की बागडोर आपके हाथ में रही है, इसलिए आप यह कह कर नहीं बच सकते हो कि हमारी सरकार नहीं है इसलिए देश पीछे चला जाता है। पूरे समय आपकी सरकार रही है और अब तक इंतजाम नहीं कर पाए हो, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा और विद्युत के मामले में जरूर ध्यान देना पड़ेगा तभी देश की तरक्की होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समाप्त)

SHRI N.R. GOVINDARAJAR (TAMIL NADU)*:

Hon'ble Vice Chairman Sir,

On behalf of my party (AIADMK), I thank you very much for giving me this opportunity, to participate in this discussion on the functioning of the Ministry of Power. During the past five years of the UPA-I Government and during the incumbent UPA-II Government, the functioning of the Ministry of power has not been satisfactory. Sir, I would like to state that it is not my intention to point out only the shortcomings of the Ministry. As far as we are concerned, the jasmine flower of the neighbour's garden also will spread its fragrance. On behalf of AIADMK, we will appreciate the good performance of the Ministry and also criticise the shortcomings of the Ministry. As we belong to the opposition benches, it is our duty to point out the shortcomings of the Ministry.

Hon'ble Vice Chairman Sir,

Our nation attained independence sixty two years ago. But even after sixty two years of Independence, we have not achieved self-sufficiency in meeting our power requirements. This is a regrettable feature. Power has

---

*English translation of the original speech in Tamil.

become an essential need now. Various sectors such as industry, agriculture, education, health, banking and commerce need power. Power cuts affect day to day life. It affects the growth of industrial sector thereby leading to economic downturn.

The incumbent Union Government contested the General Elections with the promise of giving 'Electricity to all till the end of the year 2009'. But even after occupying the office for the second term, the Government is not able to fulfil its promise. On the other hand, the power cuts have increased throughout the country. The promise has become a dream now. Even during today's sitting, we have experienced so many power cuts.

It has been announced that the Ministry of Power feels proud of two schemes - Rajeev Gandhi Grameen Vidyutikiran Yojana (RGGVY) and Accelerated Power Development and Reforms Programme(APDRP). But the implementation of these two schemes is not satisfactory. Rajeev Gandhi Grameen Vidyutikiran Yojana (RGGVY) has been formulated to provide electricity connections to 23 million people living Below Poverty Line(BPL), and aims at covering 1,25,000 villages. But, this scheme has so far provided electricity only to 4.5 million people living in 55,000 villages. What is the main reason for this unsatisfactory performance? It is mainly because of the fact that the Government stops only at formulation of new schemes, and does not pay proper attention to implementing them.

Hon'ble Vice Chairman Sir,

The Hon'ble Minister should not be angry with us for pointing out the shortcomings. Criticism has to be taken in the right perspective, irrespective of who the critic is.

The gap between the power requirements and the power generation of our country has been widening. Due to power shortage, our economy has been severely affected. In the Eleventh Five year plan, a target has been fixed to increase power generation upto 78,700 Mega Watts (MW). But, the target has now been reduced to 70,000 Mega Watts due to the delay in the establishment of new thermal power stations. Sir, we have no other choice but to criticise the unsatisfactory performance of the Ministry of Power. This has severely affected the economy of our country. This is mainly because of the slackness in the construction of new power plants, shortage of coal and the delay in obtaining the required capital of five lakh crores of rupees.

The power generation of our country has not improved satisfactorily. Hydro Electric Power stations and Thermal Power stations have achieved some progress. The private sector has performed well in power generation. Proper facility has to be given to the private sector to improve their performance.

The power generated in Hydro electric power stations of our country is estimated to be 1,50,000 Mega Watts. But, only 35,000 Mega Watts of power has been generated from Hydro electric power stations so far. Therefore, steps have to be taken to increase the power generation in Hydro electric power stations. More investments have to be made to encourage research and development activities in Public Sector Units such as

National Thermal Power Corporation Limited (NTPC) and Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL).

Except for a few states, many states have been affected by power shortage. The power cuts in Tamil Nadu exceed those in other states. This has severely affected the industrial sector of Tamil Nadu. During the tenure of our esteemed leader Dr. Puratchi Thalaivi Jayalalitha, Tamil Nadu had surplus power generation to the extent that we were able to help our neighbouring states. But now, Tamil Nadu is in darkness.

Industrial units are severely affected and they are unable to fulfil their export orders. Many power loom industries have been closed down. As a result, a large number of workers have lost their jobs. Economic depression is being felt in industrial sector. People's day to day life is affected. Various sectors such as agriculture, education, health and industry have been severely affected by power cuts. Though the State Government of Tamil Nadu has brought so many schemes to solve the problem of power shortage the Union Government has to take the responsibility of implementing its schemes. This situation prevails not only in Tamil Nadu, but also in many other states. In order to overcome this shortcoming, the Union Government has to set up many new thermal and hydro electric power plants.

Neyveli Lignite Corporation Limited has established another Power plant with the power generation capacity of 4,000 Mega Watts near Seyyarru at Kanchepuram District

in Tamil Nadu. The Union Government has to give full support for the said project. Moreover, Neyveli Lignite Corporation Limited and Tamil Nadu Electricity Board, have decicded to set up a Thermal Power Station at Tuticorin with the financial capital of 49.10 crore rupees. It will have a power generation capacity of 1000 Mega Watts. The Union Government has to render its full cooperation for this project also. The Government also has to come forward to operationalise the Koodangulam Power Project with Russian collaboration.

Hon'ble Vice Chairman Sir,

At present, Southern Grid has been functioning in isolation. But Northern Grid, Eastern Grid, Western Grid and North-Eastern Grid have been functioning in a co-ordinated way. Therefore, they share surplus power among themselves. This facility is not available to Southern Grid. Therefore, the Government has to come forward to establish a National Power Grid by including Southern Grid also.

Hon'ble Vice Chairman Sir,

Industrial growth of the country depends on power supply. If there is power shortage, industrial growth will be adversely affected. Industrial growth will enhance the economic development of the nation also. Therefore, I would like to submit that the Hon'ble Minister has to take all these points into consideration and to take necessary steps to improve power generation capacity of our country and to achieve self-sufficiency

in power generation. Thank you.

(**ENDS**)

(followed by 3c - sk)

Sk/3C/4.10

SHRI N.K. SINGH (BIHAR): Thank you, Sir. I have ten questions to ask from the hon. Minister. The first, what is called the long haul, our per capita consumption of electricity, as he must be knowing, is 700 kilowatt hour which is one-fourth of the global average of 2,400, half of China's consumption, one-twentieth of the United States' and less than most countries of Africa. Does the Minister, my first question, have any credible plan where India will reach average global benchmark for per capita consumption of electricity?

Second question, Sir, cost of power. Cost of power, as we know, which greatly hampers the competitiveness of Indian industry, cripples us, is one of the most debilitating infrastructure happens to be Rs. 5 per kilowatt hour compared to 2.8 of Bolivia, 2.5 of Argentina and 3.1 of Malaysia, I can go on rappelling the international comparison. Does the Minister or the Ministry have any credible plan by when the cost of Indian electricity to Indian consumers, to Indian industry and Indian farmers become comparable to acceptable global averages even of emerging markets leaving aside the more developed markets?

My third question, Sir, reliability of power. If you look at reliability of power, in respect of industrial power, our loss, per minute outage is Rs. 5 to Rs. 22 in Karnatka, which may be among the highest. To farmers, it deters their productivity from 13 to 18 per cent, resulting in a loss of Rs. 2 to Rs. 4 for each unit of electricity not supplied. Does the Minister have any credible plan when power supply to Indian consumers, to Indian farmers and to Indian industry will become more reliable?

(Contd. by ysr-3d)

-SK/YSR-LP/4.15/3D

SHRI N.K. SINGH (CONTD.): My fourth question, Sir, is about capacity creation. We had heard Minister *ad nauseam* on this 78,000 mw project, what you are doing, and what you are planning to achieve, and so on and so forth. We know that you cannot reach the 78,000 mw target. What is worse, Sir, is that if you look at the Parikh Report on Integrated Energy Policy, by 2030 as against 78,000 mw, you would require 395,000 mw. There are issues like financial linkages, linkages in terms of inputs, and ability to be able to finance this. And who is going to do so? Do we have a credible PERT chart which will show in what manner you are going to produce 950,000 mw which you yourself have accepted by the Cabinet having adopted the Kirit Parikh Report on the Integrated Energy Policy?

My fifth question, Sir, is the restructured APDRP. Sir, I have had the privilege of being the Chairman of the first APDRP and then we restructured it. It had three important objectives. One is the templates, the ten templates on power, namely, power reforms and so on and so forth. Unfortunately, in spite of the templates being adopted, the loss on account of T&D losses has come down very nominally. It has hovered around 30-40 per cent constituting five per cent of the GDP and the PLF, unfortunately, also has really shown a very marginal improvement. On franchising system, we have lagged behind. In terms of compulsory metering, we have not been able to achieve hundred per cent compulsory metering. Will you, therefore, consider another more basic restructuring of the APDRP to realize the main objective of making the power

sector viable, which was the original intention of doing so, and since even the restructured APDRP has not been able to achieve this objective?

My sixth question is this. I think it did involve the Minister in the drafting of the Electricity Act, 2003. The principal objectives of the Electricity Act adopted after considerable discussion in both the Houses of Parliament were three-fold. One is unbundling of power sector. In this, regrettably, unbundling took place only in 13 States, out of which many have not issued tariff orders. Another was having open access, to introduce the bouquet of choice to average consumers, and having a sunset clause in getting rid of the distortionary cross-subsidy which has bedevilled the electricity sector. Will you consider, Minister, which is my sixth question, of improving the implementation of the Electricity Act, 2003? You yourself have committed to it and you have taken upon yourself this obligation.

My seventh question, Sir, is this. Considering the fact that it is now well known that environmental consequences are something which you have accepted in reducing the energy intensity in use. What is your plan for future power stations on carbon sequestration, carbon capture, and cleaner kinds of fossil fuel which will enable us to harmonize achieving electricity usage, particularly per capita electricity usage, and not denying it to the 400 million Indians, who do not have assured access to electricity? What is your plan for achieving lower levels of carbon dioxide emissions by progressive adoption of carbon capture and carbon sequestration technology?

My eighth question, Sir, relates to the quality of your regulatory framework. You have regulators. But, unfortunately, there is regulatory capture. The domain

knowledge, for which you have regulators, is missing. The quality of orders of your regulators leaves much to be desired. When do we expect to have a regulatory structure, which meets the kind of requirement, which you have in improving the overall comparative viability of the electricity sector both as far as the Central Government and the State Governments are concerned? Believe me -- and this is talking, unfortunately, against the area in which I myself worked -- if you give the kind of salary, which you are giving to the regulators here and in the States, if you appoint the kind of people who you are appointing, they are not likely to bring huge amount of domain knowledge to improve the quality of regulatory orders. Please have a re-look at what kind of regulators you want to have to be able to govern this sector in the long term.

My ninth question, Sir, is about the whole area of regional imbalances. Many of my colleagues have spoken today that large parts of country have very poor quality of electricity. I agree with you that each State cannot become self-sufficient. India is one country. We need to have a better system of transmission and not necessarily each State producing it. There are very, very severe regional imbalances.

(Contd. By VKK/3E)

-YSR/VKK/3e/4.20

SHRI N.K. SINGH (CONTD.): When do you think and in what manner do you think, you will truly de-politicise the allocation of coal and in terms of the allocation of the unallocated power so that the country as a whole can benefit? (Time-bell)

Sir, now, with your permission, I come to my last question. It is a question not to the Minister, but it is a question to the Prime Minister. You are the Minister for Power and yet it is clear that you have no control on coal, coal productivity in terms of quality of coal, quality of supply, etc. You have no control on the comparative cost of variation of inputs in terms of how gas is priced, other forms of energy are priced and to be able to arrive at a harmonious conclusion. You have no say on renewable energy. You have little say on usage of technology. Will you consider, therefore, recommending to the Prime Minister that for enabling you to discharge your mandate effectively, you need to recreate an integrated Ministry of Energy? We had a Ministry of Energy. I can recognize that coalition politics and its compulsion of accommodating many Cabinet colleagues will prevent us from abolishing Ministries. But, let's make a beginning for recreating what we once had with, at least, coal and power being combined since coal, for a long time, will constitute one of the principal sources of energy. Mr. Minister, I had little answers to give. But, I had ten questions to pose. Thank you very much.

(Ends)

SHRI Y.P. TRIVEDI (MAHARASHTRA): Thank you, Sir, for giving me this opportunity to voice my feelings. Everybody has talked about it. I need not repeat it that one of the biggest challenges facing the country is the challenge of power. I am talking of power not in the sense of political power. I am talking of power as the Minister is now holding.

I would also like to make it clear that it is not as if the States where the Congress Government or coalition Government is in power, there is no problem of

electricity. I come from Mumbai and we have got continuous and occasional shortage of power or breakage which we all resent. Sir, this problem affects the cities as well as the villages. There are industries which are affected and which require 24-hour continuous power supply. If it is not given, then, the industries suffer and sometimes, they have to close down. As I was glancing through the Eleventh Five Year Plan, our emphasis seems to be mainly on three sources of energy. One is thermal; second is hydro; and, the third is atomic. According to me, there are about 12 different centres or points from where we can draw energy. The first is, of course, the Sun, the solar energy about which much has been talked about. It was talked about today also in the morning in the Question Hour. Then, there is the wind energy. We are a tropical country. We have got a lot of Sun energy. We have got a lot of wind. But, we are not taking proper advantage of the wind energy. Then, we are endowed with sea on southern side. We have got huge tidal waves. We have not been able to harness the energy which can be derived from tidal waves. Then, the fourth is coal. Much has been talked about the quality of coal. But, the coal with the modern technology can be improved and the ash content can also be reduced but we have not decided about it. Then, there is hydro-electrical energy about which much has been talked. We have got so many areas of huge mountains and waterfalls from which the hydro-electric energy can be generated and we should try to concentrate on that. Then, there is oil, much of which is found on the offshore which can be taken into use. Then, there is natural gas which also can be the source of energy. Nuclear energy is the next item on which much has been said and much

discussion has taken place. Then, there are also experiments being carried out in some of the countries which we can also replicate in our country about the fission energy, which is probably going to be answer. I am not sure as to what type of research you are making in that field. But, I think, we can certainly devote our attention to that. (Contd. By RSS/3f)

RSS/3F/4.25

SHRI Y.P. TRIVEDI (CONTD.): Then there is geo thermal industry, geo thermal power which also we can harvest, which probably we have in plenty in certain pockets of our country. Then there is recycling of energy. There is something like bio fuel energy which can also be drawn from some of the plants. I do not know what progress you have made in that sector. Then it has been said and rightly said by my friend Mr. N.K. Singh that there is no coordination. You have got various Ministries. We have got Coal Ministry, we have got Energy Ministry, we have got the Ministry dealing with atomic energy. There must be coordination between the various Ministries either by intra-ministerial talks or by discussions from time to time and coordination. But it has to be done. The problem with us in the field of energy is two-fold. The first is about the generation of power. The generation of power can be tackled if the various Ministries come together and try to find out as to how there is so much of wastage of energy in trying to harvest the energy of the nation. Then there is also the second failure, which is the policy of distribution. The policy of distribution fails for two reasons. One is, there is in this country the theft of power. The theft of power is largely attributed in the States due to the connivance of the political bosses. Something should be done to see

that the theft of power should be considered as a very serious offence which drains the resources of our country. Then there is wastage in transmission. The wastage in transmission is because of two reasons. The first is, because of the faulty equipment or because of the inefficient management. In either case, both the generation of electricity and the distribution of electricity are the two areas on which maximum concentration should be made. I am sure we have a very dynamic Minister. He was a Chief Minister in Maharashtra, and I knew that when he was there, the buck used to stop on his table. He never used to say, go to anybody else, and I am sure, he is a very energetic person, and he will be able to tackle these issues.

AN HON. MEMBER: He is smiling.

SHRI Y.P. TRIVEDI: He is always smiling. I have never seen him not smiling. But the smile should result ultimately into achievement, and I am sure, he will be able to do so. Thank you.

(**Ends**)

SHRI SYED AZEEZ PASHA (**ANDHRA PRADESH**): Sir, thank you for giving me this opportunity. At the very outset, I want to join along with other colleagues to tell about the importance of energy generation in our country as it is the topmost agenda which we have to achieve. We have put a target of 90,000 megawatt to be completed in 2012. I think, unfortunately, we could not meet even half way also. I do not know what the reasons are. Whenever we asked about the reasons, we are told that there are some difficulties in environmental clearances and land clearances. But I think with the firm hand and with determination, the Government

can easily work on all these hurdles and impediments and we can achieve our desired goals. Sir, in this connection, I just want to say that the main strategy of a better management of electricity is efficiency and conservation. So, if you go through the examples of various countries how they are conserving the energy and then using it in a most efficient way, we can learn a lot. Unfortunately, we failed to do this job properly.

And then if you look at the demand side management, I am very sorry to say that CFL penetration in India is only 3 per cent compared to 33 per cent in Singapore and 40 per cent in South Korea. So, why cannot we see the brighter aspect of those countries to improve the CFL penetration in India?

(contd. by 3g)

-RSS-TMV-PSV/3G/4.30

SHRI SYED AZEEZ PASHA (CONTD.): Sir, if you look at the conservation of energy, I think, our Power Ministry is found wanting in propagating proper information and imparting knowledge to the people as to how they can conserve energy and lessen the burden of the electricity bills. In the last four or five years, I have seen only once an advertisement in the newspapers on how to conserve energy and how to utilize it properly. Why can't the Government just allocate a small amount for regular advertisements in the Press to give proper information to the people about efficient use of electricity?

Sir, last time, we have announced the Bachat Lamp Yojana under the United Nations Framework Convention on Climate Change and we have thought

of providing high quality CFLs at Rs.15 per lamp. It aims at replacing 40 crores of incandescent lamps which would save 6,000 megawatts of power. I want to know from the hon. Minister how much of the target is achieved in this regard.

There are several countries which are taking various steps to conserve energy. We are always looking towards the United States. I just want to give an example. In California, during summer, 30 per cent of electricity is consumed by air-conditioners. So, the Government has offered interest-free loans to replace the old air-conditioners with efficient air-conditioners. The repayment can be made within one or two years. They save a lot of energy by doing these kinds of things. There are several ways for saving energy if we look into this matter. We are suffering a lot due to power shortage. It is very necessary that the Government should take various steps to overcome the deficiency in electricity generation. Thank you. (Ends)

SHRI M. V. MYSURA REDDY (ANDHRA PRADESH): Sir, at the outset, I would like to say that the most important item in the Government's agenda is power reforms. There is no doubt that electricity is important for development and it is also a common denominator for advanced societies. In India, the *per capita* income and the *per capita* power consumption is low. So, definitely, it will affect the growth of the country. The supply of power to the Parliament today reflects the performance of this Department. The Planning Department has ambitious targets for the Eleventh Plan and the Twelfth Plan. It is only in the target stage. The achievement is only 12,000 megawatts, as my other colleagues have mentioned. For achieving the remaining part of the target, they are depending on

private investment. In the name of reforms, the State Governments were given no option to evolve alternative strategies. Even though there is a need for private investment, the Government should not forget the important element of the UPA's Common Minimum Programme or the Electricity Policy. One point is availability of reliable and quality power of specific standard in an efficient manner at a reasonable rate. But when we look into private investments in thermal generation or gas-based generation or hydel generation or nuclear generation of power and in the distribution system, the actions of the Ministry are quite opposite. Because of paucity of time, I can't explain all these things. But I would like to mention one important issue regarding gas-based power generation. It consumes 40 per cent of the gas produced in India. For example, the NTPC in the case of Kawas and Gandhar had, through an international competitive bidding, contracted for supply of gas at US dollars 3.4 per mmtu for 17 years from RAS-KG basin.

(Contd. By 3H/VK)

VK-DS/3H/4.35

SHRI M.V. MYSURA REDDY (CONTD): It is also a fact that NTPC had a detailed discussion with all its bidders on various issues before finalizing the draft agreement and certain amendments were issued based on the discussions with the bidders. An LoI was also issued to RIL which was duly acknowledged by RIL. I am having all the documents to authenticate it. This is one chapter. Then GSPA was also not signed. This is another chapter.

I would also like to bring to the notice of the Ministry the NTPC's announcement to the State Exchange. It says, "The expansion project of 2,600

MW at Kawas and Gandhar will generate 19.38 billion KWh of electricity in a year. The total savings in a year for purchase of this electricity by DISCOMs/SEBs will be around Rs. 2,130 crores per year. For 17 years, it works out to around Rs. 32,000 crores and will directly benefit the consumer". This is the NTPC's announcement to the Stock Exchange.

In view of this, Shri T. Sankarlingam, CMD of NTPC wrote a letter to Shri Prajab Mukherjee, the then Finance Minister regarding this contract. It says, "In continuation of the presentation I made on the gas pricing issue of the Reliance Industries Ltd. for KG Basin with a particular reference to NTPC contract, I would like to convey that implication of the price differential between gas price as delivered at Kawas and Gandhar as per NTPC contract and RIL's proposed price, will be of the order of Rs. 24,000 crores for the quantity contracted by NTPC during the entire contract period of 17 years. This aspect may please be kept in view".

This is the situation. The Government did not heed to the NTPC advice. They have not given a free hand to fight out this case. The gas price was fixed at US dollars 4.32. Sir, this is a burden on the consumer and it will have great ramifications over the entire power industry, gas-based power industry. My statement is also substantiated by the Minister's reply given to an Unstarred Question No. 2744, dated 14.12.2009. The Minister's reply is, "As per the regulation for fixing the tariff under the Electricity Act, 2003, there is no loss to NTPC on account of fuel cost as the fuel cost is a pass-through to beneficiaries". Sir, this Government is not interested in supplying power at affordable price. This

clearly shows that the Government is interested in encouraging private companies. I have no hesitation in saying that this is nothing but cronyism. Thank you.

(Ends)

श्री विक्रम वर्मा (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि पावर जैसे सबसे महत्वपूर्ण विषय पर आज इस सदन में चर्चा हो रही है। हालांकि सदन में जब इस पर चर्चा हो रही है तो अनेक बार बिजली ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। मैं सोचता हूँ कि शायद वह अपनी अनुपस्थिति के माध्यम से सरकार को चेताना चाहती है कि स्थिति क्या है? हम इस तथ्य से परिचित हैं कि आज हम इक्कीसवीं सदी में हैं और हम दुनिया की तीसरी ताकत की आर्थिक शक्ति बनने की बात कर रहे हैं। वह आर्थिक शक्ति बनने की जब हम बात करते हैं तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि बिना पावर के यह संभव ही नहीं है।

(3जे/एकेए पर क्रमशः)

Aka-rg/3j/4:40

श्री विक्रम वर्मा (क्रमागत) : यदि पावर नहीं है, ऊर्जा नहीं है, बिजली नहीं है, तो हमारे डेवलपमेंट की जितनी भी और जो स्कीम्स हैं या हमारा डेवलपमेंट का जो भी प्लान है, वह आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए बाकी सब चीजों के अलावा हमारी पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए थी। विकास का पहिया तभी तेजी से घूम सकता है, जब हमारे पास पर्याप्त बिजली होगी। फिर चाहे इस विकास में आप सभी को लें, इंडस्ट्री को लें, एग्रीकल्चर को लें, ट्रेड को लें या अन्य सब को लें, लेकिन बिना पावर के यह संभव नहीं है। इस दिशा में लक्ष्य तो तय हुए लेकिन उस दिशा में प्रयास जितना होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया। आज स्थिति यह है कि हमारी जो टोटल पावर सप्लाई है, अभी हमारी installed capacity 31 March,

2009 तक 1,47,966 मैगावाट थी, इसमें हाइड्रो 25% है, 36,877 मैगावाट, न्यूक्लिअर है 4,120 मैगावाट, 3% है, renewable 13,242 मैगावाट, 9% और थर्मल है 93,725 मैगावाट यानी 63% और 24% captive plant से है, यह हमारी बिजली की स्थिति है। लेकिन अगर हम सप्लाई की स्थिति को देखें कि किस तरह की हमारी सप्लाई की स्थिति है, actual power supply position के मैं केवल 2008-09 के फिगर्स आपके सामने रखना चाहूंगा कि पीक पीरियड में जब रिक्वायरमेंट होती है 1,09,809 की तब हमारी availability 96 हजार के करीब रहती है, शॉर्टेज है 18,073 मैगावाट की। It is that कि 12-14% हमारी शॉर्टेज पीक ऑवर्स में होती है। अब हम प्लान बनाते हैं और उसमें हम 10-12% बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी उतनी शार्टेज तो पीक ऑवर्स में आज की तारीख में है। आज जितना करते हैं, तब तक आपकी डिमांड और बढ़ जाएगी, जितनी आपकी डिमांड बढ़ती जाएगी, वह और कम होगा। इसके अलावा per capita consumption आप इनका देखें, बाकी का अभी भगत सिंह कोश्यारी साहब ने बताया था, मैं उनको नहीं दोहराना चाहता, लेकिन आज भी आपने टारगेट दिया है कि हम 11वीं पंचवर्षीय योजना में हर व्यक्ति को कम से 1000 यूनिट्स देंगे, लेकिन आज आप 600-700 के बीच में दे पा रहे हैं। जबकि हमारा 11th five year plan लगभग आधे से ऊपर हो चुका है, यह हमारी per capita है, जिस पर हम बात कर रहे हैं कि हर हाउस होल्ड तक हम बिजली पहुंचाना चाहते हैं, यह हमारी स्थिति बनी हुई है। इसके साथ ही आप अगर अपने 11th five year plan को देखें कि 11th five year plan में आपने खुद तय किया था कि कितने गांवों तक आप बिजली ले जाएंगे, कितनी बिजली आपकी बढ़ेगी। 15 जनवरी, 2010 तक 69,963 villages तक बिजली हमारे यहां पहुंची है। 2012 तक आपका लक्ष्य था कि सभी गांवों तक, all villages will be covered by electricity. 1991 की जनगणना के हिसाब से देश में 6,35,335 गांव हैं और हम अभी पहुंच रहे हैं लगभग 70,000 में। आपके 11th five year plan में ही एक्स्ट्रा 49,000 villages तक आपको जाना था, लेकिन आप इससे ही अंदाज लगाएं कि यदि आज हमारी यह स्थिति है तो हिन्दुस्तान में 6,35,335

villages हैं, वहां तक जाने के लिए हमें कितने वर्ष लगेंगे, कितने five year plan लगेंगे, जबकि आप 11th five year plan में यह टारगेट तय करके चले थे। इसलिए हमने जो लक्ष्य तय किया था, उस दिशा में अगर आप देखें तो हम आज की तारीख में बहुत पीछे हैं। फिर villages को कवर करने की आपने definition बहुत गलत है। पहले तो यह होता था कि किसी एक मकान में एक सिंगल कनेक्शन हो गया तो आप मान लेते थे कि हो गया, बाद में NDA Govt. के समय में इसको चेंज किया गया और चेंज करके इसको 50% से ऊपर लाए, जबकि इससे भी पूरा नहीं होता। पूरे गांव के electrification का मतलब है कि जब तक आप हरेक हाउस होल्ड के घर तक बिजली न पहुंचाए और यही 11th five year plan का टारेगट था कि every village and every house hold तक आप बिजली पहुंचाएंगे। लेकिन इसमें भी हम अभी किसी तरीके सफल नहीं हो पाए हैं। BPL परिवारों के लिए आपका टारेगट था, 162.96 लाख BPL परिवारों को बिजली देने का आपका प्रथम चरण में वादा था। इसके भी फिगर्स इसमें नहीं हैं कि आप कहां तक पहुंच पाए हैं। गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को देने का जो टारगेट था, वह भी पूरा नहीं हो पाया। उम्मीदें देश को बहुत थीं कि यू0पी0ए0 अपने II पार्ट में 11th five year plan में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उनके आधार पर बहुत कुछ करेगा।

('3k/nb' पर जारी)

NB/3K/4.45

श्री विक्रम वर्मा (क्रमागत) : मैं इनकी नीति के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि 2003 में एक Act बना। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 3 के अंतर्गत 12.2.2005 को राष्ट्रीय विद्युत नीति घोषित की गई। जो Electricity Policy, 2005 में घोषित की गई, अब जरा उसके points देख लीजिए कि हम उनको कहां तक achieve कर पाए हैं और हमारी क्या स्थिति है। उसमें एक प्वाइंट यह था कि आगामी 5 वर्षों में सभी परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना। यह Act के अनुसार है, आपने Act के अंतर्गत जो पालिसी तैयार की है, मैं उसी का उल्लेख कर रहा हूं। इसमें ये प्वाइंट्स भी थे कि 2012 तक पावर की मांग को पूरी तरह पूरा करना, ऊर्जा और

उसकी प्रमुख आवश्यकता के समय होने वाली कमी को पूरा करना, पर्याप्त मात्रा में आरक्षित ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना और तर्कसंगत ढंग से मानक दरों के साथ, विश्वसनीय और गुणवत्तायुक्त ऊर्जा की आपूर्ति करना। गुणवत्ता का प्वाइंट भी उसके साथ है। अब जहां तक विश्वसनीयता का सवाल है, इस पार्लियामेंट में ही विश्वसनीयता के साथ सप्लाई नहीं हो पा रही है। गुणवत्ता की बात छोड़िए, वोल्टेज की क्या स्थिति रहती है, यह मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मैं गांव का किसान हूं, मुझे मालूम है कि कितनी ही बार किसानों की मोटरें जल जाती हैं, क्योंकि वोल्टेज पूरी नहीं रहती है। इसके कारण पंप जल जाते हैं। किसान आता है, चिल्लाता है, कई बार हमसे शिकायत करता है कि पावर सप्लाई तो प्रॉपर दें, वाल्टेज तो प्रॉपर मिले। यानी कहीं भी विश्वसनीयता की स्थिति नहीं बनी है। इसलिए आपकी पालिसी के आधार पर आप देखें, तो पता लगेगा कि उसका पूरी तरह पालन नहीं हो पाया है।

मुझे बार-बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है, आपने 11वें प्लान में 78,700 मैगावाट की क्षमता के विस्तार का लक्ष्य रखा था, किन्तु हम अभी इससे बहुत पीछे हैं। आपने यह जो आर्थिक सर्वेक्षण दिया है, इसमें सरकार स्वयं इस बात को मंजूर करती है कि चालू वित्त वर्ष में 14,507 मैगावाट की क्षमता बढ़ाने के लक्ष्य की तुलना में अप्रैल-दिसंबर, 2009 में वास्तविक संवर्धन 43.9 परसेंट था, यानी आप ही इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि आपने जो टारगेट तय किए थे, आप उनसे कितने पीछे चल रहे हैं। यहां इन्होंने इस बात को छिपाने की कोशिश की, इसमें बताया नहीं कि कितना-कितना एचीव हुआ, लेकिन यदि पृष्ठ 234 पर आप देखें, तो उस टेबल से यह स्पष्ट हो जाएगा कि 2007 से पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, 2007-08 में आपने 9,263 मैगावाट, 2008-09 में 3,454 मैगावाट और उसके बाद अप्रैल-दिसंबर, 2009 तक 6,375 मैगावाट Power capacity addition का लक्ष्य रखा। इस तरह कुल मिलाकर आप लगभग 19,000-20,000 मैगावाट का अतिरिक्त लक्ष्य प्राप्त कर पाए हैं। अब यदि बचे हुए 2 सालों को और जोड़ लें, तो आप इसमें 10,000 मैगावाट सरप्लस बिजली पैदा कर पाएंगे, यानी कुल मिलाकर आप 30,000 मैगावाट सरप्लस तक पहुंच पाएंगे। एक तरफ आप बात कर

रहे हैं कि हम बिजली उत्पादन को 78,700 मैगावाट तक ले जाएंगे और दूसरी तरफ आप केवल 30,000 मैगावाट तक पहुंच पा रहे हैं, तो यह हमारी एचीवमेंट है, यह हमारा टारगेट है, यह हमारी प्लानिंग है, इस आधार पर हम चल रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम हिंदुस्तान को बिजली के मामले में पूरी तरह से सक्षम बना देंगे। इसलिए मेरा यह कहना है कि यह हालत तो तब है, जब हम 7-8 परसेंट ग्रोथ की बात कर रहे हैं। जब हमें 7-8 परसेंट की ग्रोथ के लिए इतनी बिजली की आवश्यकता है, इसके लिए हमारी यह स्थिति है, तो यदि हम 10 परसेंट ग्रोथ के टारगेट तक जाते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं, तो क्या स्थिति होगी?

उपसभाध्यक्ष जी, मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने लिखा है कि यदि आप यह मानकर चलते हैं कि 8 प्रतिशत सालाना विकास दर जारी रही, तो अगले 27 वर्षों में आपको बिजली का उत्पादन 7 गुना बढ़ाना पड़ेगा। अब 7 गुना के हिसाब से हम देखते हैं कि यदि इस पंचवर्षीय योजना में आप इतना पीछे चल रहे हैं, तो आगे क्या होगा? यदि हम यही मानकर चलें कि विकास दर 8 प्रतिशत रहेगी, जब कि आप कह रहे हैं कि हम इसको 10 प्रतिशत तक और इससे आगे ले जाएंगे, तो इस हिसाब से आपको कितनी बिजली की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए नए विद्युत स्टेशन, ट्रांसमिशन लाइनें, इन सब पर हमको 300 अरब डॉलर का खर्च करना पड़ेगा, यानी 13,25,200 करोड़ रुपए का खर्च करना पड़ेगा। अब इन सारी चीजों को देखते हुए हम कहां खड़े हैं, इस पर हम सबको विचार करने की आवश्यकता है। इसके लिए जो गंभीरता होनी चाहिए, जो विलपावर होनी चाहिए, वह गंभीरता और विलपावर कहीं देखने को नहीं मिलती है।

3L/VNK पर क्रमश:

-NB/VNK-KGG/3l/04:50

श्री विक्रम वर्मा(क्रमागत): आप महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण में ऊर्जा विषय को देखें, तो यह सिर्फ सवा तीन लाइन में है। ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट के बारे में महामहिम राष्ट्रपति

जी से भाषण करवाते हैं और केवल सवा तीन लाइन में उसकी पूर्ति हो गई और उसमें भी शब्द क्या है - "फलस्वरूप ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दसवीं योजना में शामिल क्षमता से तीन गुना अधिक क्षमता वृद्धि की संभावना है।" केवल संभावना है। हम महामहिम राष्ट्रपति जी से भाषण करवा रहे हैं, उसमें भी हमारे पास यह जानकारी नहीं है कि हम कितना करेंगे, क्या करेंगे और कैसे करेंगे। केवल कह दिया कि तीन गुना अधिक क्षमता वृद्धि की संभावना है। मात्र संभावनाओं के आधार पर यह पूरा का पूरा डिपार्टमेंट या हमारी पूरी की पूरी प्लानिंग चल रही है। मैं वित्त मंत्री जी की निष्ठा पर नहीं जाना चाहूंगा, चूंकि समय कम है। लेकिन यदि इस चीज को देखते हुए सरकार को चाहिए कि वह अपनी असफलता को स्वीकार करे, क्योंकि सारी असफलता सामने आई है। सरकार को सदन में इस बात को स्वीकार करनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए कि हमारी पंचवर्षीय योजना पावर के मामले में पूरी तरह से फेल है। मैं बाकी के बारे में नहीं जाता हूँ, लेकिन इतने articles आए हैं, जिन्होंने इतना लिखा है, इतना criticize किया है, उन सबको यहां दोहराने की जरूरत नहीं है। More power for power. 78,000 MW question. उसके बजाए कि इतना आप कहां से लाएंगे? "The country is once again set to miss power target a 20 per cent shortfall in Eleventh Plan, 28,000 MW target. The reasons are many and familiar. Time-overrun in construction indicates coal and Rs.5 lakh crores for shortfall in the funding figures."

(श्री उपसभापति पीठासीन हुए)

ये सारी चीजें हैं। कोल में हम नहीं कर पा रहे हैं, हम फंडिंग में पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हमारे थर्मल पावर या पावर स्टेशन के जो construction हैं, वहां हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आज की स्थिति में हमारा shortfall इतना ज्यादा जा रहा है, ये सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट है। मैं एक नहीं, अनेक articles आपको बता सकता हूँ, जिनमें एक-एक चीज को क्लीयर करते हुए

बताया कि यूपीए का सेकण्ड टर्म और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना विद्युत के मामले में पूरी तरह से असफल हुई है और सरकार को इस बात को स्वीकार करनी चाहिए।

श्री उपसभापति : वर्मा जी, आपके पार्टी का सात मिनट समय बाकी है और अभी एक और सदस्य को बोलना है।

श्री विक्रम वर्मा: महोदय, मैं केवल दो चीजें और बता देना चाहूंगा कि यदि पंचवर्षीय योजना अच्छी तरह से पूरी हो जाती, तो इससे कितना employment generate होता, मैं इसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। यदि यह होता, तो construction में 20,000 Engineers की जरूरत पड़ती। Operation and maintenance - 40,000. Total is 60,000. Supervisors - 33,000. Operation maintenance - 75,000. 1,08,000 की आवश्यकता होती। Skilled workers - 1,40,000. Operation and maintenance - 1,25,000. कुल 2,65,000 की आवश्यकता होती। Unskilled workers - 1,48,000, Operation and maintenance - 75,000, कुल - 2,23,000 की आवश्यकता होती। Non-Technical - 84,000, Operation and maintenance - 1,20,000, कुल - 2,04,000 की आवश्यकता होती। यदि हम इन सबका टोटल देखते हैं, तो 8,60,000 manpower, जिसमें Technicians, Engineers, आदि की पूर्ति कर सकते थे। हम जितने कम पीछे जा रहे हैं, यहां इतना unemployment है। हमारे यहां बच्चे महंगी शिक्षा ले करके technical education में जा रहे हैं, नए engineering college में जा रहे हैं, वे इस उम्मीद में जा रहे हैं कि हमें chances मिलेंगे। लेकिन आप यह देख लीजिए कि यह shortfall है। कहां से employment मिलेगा। यह तो सिर्फ इतना हुआ, लेकिन इसके कारण जो industries चलती, इसके कारण जो बाकी का production होता, जो इसके कारण लघु उद्योग गांव-गांव में चलते, इन सबसे आप सोच सकते हैं कि हमको कितना production मिलता, कितना employment मिलता। इसलिए मेरा कहना है कि इससे केवल एक चीज का नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि बाकी की सारी चीजों का भी नुकसान हुआ है। Transmission line loses 30 परसेंट से ऊपर है, कोल आप दे नहीं रहे

हैं, राज्यों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। आप राज्यों को क्यों नहीं देते हैं? राज्यों के सहयोग के बिना बिजली पैदा कहां से होगी? आप अकेले कहां से करेंगे? आप कोल नहीं देते हैं। मध्य प्रदेश के बारे में आज सुबह पूछा, हमको इतनी डिमाण्ड है। माननीय कोयला मंत्री जी ने एक बार जवाब दिया था कि आपको हमने पिछली बार से, यानी एनडीए के समय से ज्यादा दे दिया है, अब यह भी एक समस्या है। पर, अब हमारे पास पावर प्लांट बढ़ गए हैं।

(3m/MP पर क्रमशः)

MP-KLS/3M/4.55

श्री विक्रम वर्मा (क्रमागत) : यदि वहां बढ़ गए हैं, तो कोल की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, यह तो अपने आप में सत्य है। अब वह बढ़े हुए हैं, इसके लिए हमारा आपसे लिंकेज है, लेकिन आप वह नहीं दे रहे हैं, कटौती कर रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि स्टेट्स हमारे साथ सहयोग नहीं करते हैं, इसलिए नहीं हो पाता है। तो मेरा यह कहना है कि इन सब चीज़ों को सम्मिलित रूप से देखना चाहिए। यह पूरे देश की आवश्यकता है और सामूहिक रूप से आपको पॉलिसी बनाकर, सबको विश्वास में लेकर, राज्यों को ज्यादा विश्वास में लेकर आपको काम करना पड़ेगा, तब जाकर हम इसकी पूर्ति कर पाएंगे, धन्यवाद।

(समाप्त)

श्री रामचन्द्र खूंटिआ (उड़ीसा) : उपसभापति महोदय, माननीय ऊर्जा मंत्री जी द्वारा लाए गए बजट का हम समर्थन करते हैं और उनको धन्यवाद भी देते हैं। महोदय, कुछ सदस्यों ने यहां पर कहा कि इच्छाशक्ति की जरूरत है। हम तो यह मानते हैं कि देश में 2012 तक सारी जनता को, आम आदमी को बिजली देनी है और राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना में, बी.पी.एल. में जो लोग हैं, इन सभी को बिजली देने की जो इच्छाशक्ति है, वह इच्छाशक्ति सिर्फ कांग्रेस और यू.पी.ए. गवर्नमेंट में है और किसी में नहीं हो सकती। सिर्फ यही नहीं, यू.एस. के न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के साथ एग्रीमेंट करके भारतवर्ष में जो आइडियल रिएक्टर हैं, सभी लोगों को जानकारी है कि न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए कितने रिएक्टर

आज आइडियल हैं। अगर यह एग्रीमेंट नहीं होता, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप हमको सप्लाई नहीं देते, तो हम भी न्यूक्लियर एनर्जी के टार्गेट को एचीव नहीं कर सकते। तो यह एग्रीमेंट करना, सभी को बिजली देना और जो बिजली उत्पादन है, उसको बढ़ाना, ऐसी इच्छाशक्ति यू.पी.ए. सरकार की है, कांग्रेस की है, मंत्री जी की है, हमारे प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह जी की है और सोनिया जी की है, इसलिए हम सभी को धन्यवाद देते हैं।

महोदय, आज यह बात कही जाती है कि देश में बिजली का उत्पादन टार्गेट हम एचीव नहीं कर पाए और यह ambitious target है। टार्गेट ambitious हो सकता है। केंद्र सरकार अपने आप बिजली प्रोडक्शन नहीं करती है। केंद्र सरकार का जो plan target है, चाहे दसवीं योजना हो, चाहे ग्यारहवीं योजना हो, जो टार्गेट है, it includes the target of the State Government, it includes the target of the private sector and it includes the target of the Central public sector.

तो उसको इंप्लिमेंट करने के लिए न केवल केंद्र सरकार की इच्छाशक्ति की जरूरत है, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट की इच्छाशक्ति की जरूरत है और प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ की इच्छाशक्ति की जरूरत है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोऑपरेशन चाहिए, क्योंकि कोई भी कारखाना लगाने के लिए land acquisition, forest clearance और सभी प्रकार की जो मदद मिलनी चाहिए, वह मिल रही है और हमारा विश्वास है कि बिजली मंत्री उसको जरूर कर पाएंगे।

Sir, I just want to mention here कि इस सरकार के आने के बाद, जैसा अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि loss बढ़ रहा है और पी.एल.एफ. कम हो रहा है, यह बात सही नहीं है। अगर आप देखेंगे कि जो ऑल इंडिया थर्मल पी.एल.एफ. है, जो 2001-02 में 69.9 था, वह 2002-03 में 72.2 था और 2009-10 में 76.17 है, तो इसमें यह कम नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि all India per capita consumption of electricity, in 2002-03, it was 566.7, in 2003-04, it was 592.0, in 2004-05, it was 612.5 and now it is 704.2 which means per capita electricity consumption बढ़ रहा है, इंडस्ट्रीज़ बढ़

रही हैं और किसी क्षेत्र में भी new technology की वजह से किसी का भी संप्रसार हो रहा है, तो that means more power is required for us.

(3N/SSS-SC पर क्रमशः)

SSS/3N/5.00

SHRI RAMA CHANDRA KHUNTIA (CONTD.): I want to give you the records about transmission loss. In 2002-03, in T & D losses were 32.54 and AT & C losses were 32.54. In 2003-04, the T&D losses were 32.53and AT&C losses were 34.78 and let us see what happened in 2006-07. In 2006-07, T&D losses were 28.61 and AT &T losses were 32.07. That means T&D losses and AT&C losses were being reduced day by day. So, it is not in minus point also. Of course, there is a shortage of electricity in all areas, in Northern area, in Western area, in Southern area, in Eastern areas. Everywhere there is a shortfall of electricity and also if we see the situation, it is not new. If we go back to the situation in 1997-98, 1998-99, 1999-2000 and 2000-01, what was the situation? When NDA Government was there, the situation was: energy requirement was 424505 MU, whereas the availability of energy was 390330. In 1998-99, it was 446584 MU and the availability was 420235 whereas in 2007-08 also the requirement was 737052 MU and the availability was 664660 and in 2008-09 the requirement was 777039 MU and the availability was 691038. Sir, from this record if you go to the Plant Load Factor, if you look at 1998-99 when these people, the NDA, who were in power are criticizing, the Plant Load Factor in 1998-99 for Central was 64.6, State was 64.6, Private was 63.7 and Overall was 68.9. What is wrong? In 2007-08, the Plant Load Factor for Central was 86.7, State was

71.9, Private was 90.8 and Overall was 78.6 and in 2008-09, the Plant Load Factor for Central was 84.3, State was 71.2, Private was 91.0 and Overall was 77.2. So if you go to these three, I believe this is gradually improving, not only in production but also in the losses of energy from various points of view. Rather, we should also give credit that the installed capacity has gone up to around from 74000 MW to around 1,54,000 MW in the last seven years. That is the comment made by some people. Sir, although I do not want to say that we should not do anything, I do agree that there is an obstacle. What are the obstacles to achieve the targets? Obstacle is, the problem of land acquisition. We will do it. Central Government has no power for acquisition for land. Obviously, the State Government has to do it. When there is a question of the State Government's power sector, who will do it? Obviously, the State Government has to do it. When there is a question of State Government's Power Sector, who will do it? The State Government should also take incentives to fulfil their commitment and responsibility because the total plan which has been made, the commitment which has been made by the Government, the target which has been made by the Government, is not only the commitment of the Central Government, it is a combination of the targets of the State Government, the private sector and other sectors. So, now in this situation all have to fulfil their responsibility in their respective sectors. Then only we can achieve the target. We do admit that power is the lifeline of not only our country, but, it is the lifeline of the whole world and we must without any difference of opinion contribute positively and see how best we can do and achieve our targets.

(Contd. By NBR/3O)

-SSS/NBR-MCM/3O/5.05

SHRI RAMA CHANDRA KHUNTIA (CONTD.): Sir, I want to tell this House and to those who are saying that the power PSUs are not performing well a thing. It is not correct. Maybe, the NHPC has not been able to achieve the target. There is some problem. The problem is about acquisition of land, getting forest clearance, inaccessible area, etc. I want to appreciate that NHPC, NTPC, Power Grid and other power PSUs which are doing a commendable job. I must say that a company like NTPC has got appreciation all over the world. It has reached to 4th or 5th position among the power generation companies in the world. We must feel proud of it. Sir, land acquisition, forest clearance, availability of coal are the factors which are standing as obstacles. So, we should try to help our PSUs as to how they get those clearances.

In case of hydro power, rather, I want to say, many projects are given to the private sector. Sir, I want to inform the House that hydro power projects are such that within 7-10 years a person can get back his investment and whatever is earned after 10 years that is profit. So, why such profitable projects are given to private players instead of taken over by the NHPC or State sectors? Sir, I know that in Arunachal, out of the 105 projects, probably, except 3 projects, all projects have been given to private sector. In the North-East, Uttarakhand, Himachal Pradesh, our efforts should be to see that the projects are given to public sector so that after 7 or 10 years, the Government can earn profits without any additional investment. So, in this area, there may be a strategy of the private sector. I know

personally that those persons who are taking up hydro projects in Arunachal have not yet started the work! In J & K, North-East and Uttarakhand they have not started the work.

Same is the case in coal blocks. Now, the Government has allocated coal blocks. Of course, it comes under the Ministry of Coal. But, it is linked to energy. What is happening? Out of the 80 coal blocks allotted, more than 50 per cent have not acquired clearance from the Forest and Environment Ministry for developing coal blocks. The main reason behind it is this. The Government wants to develop these blocks within the prescribed time and hence the blocks have been given to the private business and corporate houses. But, there may a strategy not to develop these blocks and, after 4 or 5 years, to handover the same to other party by taking more money. So, I request the Government to coordinate with the Coal Ministry, Forest and Environment Department, Ministry of Petroleum and Natural Gas to help power PSUs to achieve the target which is the main roadway for the growth and development of the country.

Sir, with regard to NTPC, NHPC and all other public sectors, I must say that initiative should be taken to encourage and help them. In case of hydro power projects, the Central PSUs should be given opportunity.

Sir, something has been said about Rajiv Gandhi Grameen Vidyuthikaran Yojana. I know that that we are lagging behind in achieving the target. But, if one criticizes for the sake of criticism, it does not mean anything. Who is implementing this scheme? In many States, the State Governments are implementing it. But, in some States, the Central PSUs have been given the

responsibility. So, those Central PSUs should be taken to task if they are derelicting in their duty. But, what about the State Governments which have failed in implementing it? In my case, Orissa, it has been said that the Central Government is saying that the State Government is creating obstruction because the State Government first assured us not to take tax in any material which has been used for village electrification under the Rajiv Gandhi Vidyuthikaran Programme. But the agreement was delayed for two years. Ultimately, the State Government did not agree to leave these taxes. After discussions and delay of two years, ultimately, the State Government agreed and the project is delayed for two years. Now, the State Government is saying, 'since this has been given to Central PSU, we are not responsible as they are not implementing the programme.' So, I request the hon. Minister to review this matter, because merely accusing or making the other Government responsible by saying that it is not doing the work is not fair.

(CONTD. BY USY "3P")

-NBR-USY/3P/5.10

SHRI RAMA CHANDRA KHUNTIA (CONTD.): This is a very useful programme for the general public and the poor man. We must be very serious and take a review of it. It should be in three phases. In those areas, where it has already been sanctioned and funds are available, it should be implemented with all seriousness so that we can achieve the target. One thing I must say here and congratulate the hon. Minister. I am talking about the North-Eastern Region. In 1998, in the North-Eastern Region, the Government had decided to give a special allowance

to the NHPC people because they were working in a remote area. I don't blame anybody. But fortunately or unfortunately the NDA Government was there. When this scheme of special allowance was implemented, you will be surprised to know this was applicable only to the officers, which means the officers, who were working in the North-Eastern projects would get 10-12 per cent special allowance, but not the workers. We have been fighting for the rights of the workers. The workers have been fighting for their rights. I must congratulate the hon. Minister that he has taken a decision to extend benefit of special allowance to 1500 NHPC workers who are working in the inaccessible areas of the North-Eastern Region. This costs around rupees eight crores. They have already got around rupees four crores for two years. I request the hon. Minister to give the balance of rupees four crores for the next two years. This is definitely a great achievement because they have been given their due right after a long time.

Sir, I would also like to mention here about the construction works and the projects that are being taken up for electrification of rural areas. I think, these things should repeatedly be reviewed. One thing also I would like to mention here. It is about the renewable energy, about the *gobar* gas plants, about the solar system. Of course, the solar energy is a little costly. But we must try to use the alternative sources of energy.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Khuntia, you will have to conclude because there is one more Member from your party and you will not be leaving any time for him.

SHRI RAMA CHANDRA KHUNTIA: Okay, Sir, I am just concluding within two minutes. This is a very important thing. We should also use alternative systems

of energy, like, nuclear energy and solar energy. We should spend more money on research so that the cost of solar energy could be brought down and make it cheap for the consumers to make them more interesting in it. Since this is a natural process and we can get as much solar energy as we want, we should concentrate more on research. We can seek advice from other countries also as to how best the cost of solar energy could be brought down.

With these words, I thank you, Sir, for having given me this opportunity to speak on the working of the Ministry of Power.

(Ends)

(Followed by 3q -- ASC)

ASC-PK/5.15/3Q

श्री राजनीति प्रसाद (बिहार): सर, पूरे देश में पावर बहुत जरूरी चीज़ है। इसको हम लोग बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं। पावर से ही हमारा एम्पलायमेंट बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी, कारखानों में उत्पादन होगा और अगर बिजली नहीं है, तो हम टारगेट तक नहीं पहुंच पायेंगे। आप दिल्ली की बात छोड़ दीजिए, पार्लियामेंट की बात छोड़ दीजिए, आप बिहार के शहरों में जाइए, तो पाएंगे कि वहां पर बिजली नहीं है। वहां पर कारखाना इसलिए नहीं लगता है कि वहां पर बिजली की सप्लाई नहीं होगी। ऐसी स्थिति में लोग साइलेंट जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले शोर करने वाला जनरेटर का इस्तेमाल होता था। इस जनरेटर का प्रोडक्शन अब ज्यादा हो गया है और पावर का प्रोडक्शन कम हो गया है। हमारे यहां पर बरौनी थर्मल पावर स्टेशन है। हमारे यहां कांटी थर्मल पावर स्टेशन है। हमारे यहां कहलगांव का पावर स्टेशन है। कभी-कभी न्यूज़ आती है कि इसमें पावर की सप्लाई कम हो रही है। हमने यह पता लगाया कि पावर की सप्लाई कम क्यों हो रही है, तो पता चला कि पावर की सप्लाई इसलिए कम हो रही है क्योंकि उसको कोयला उचित समय पर नहीं मिलता है। जब कोयला

ही उचित समय पर नहीं मिल पाएगा, जो कि उसका रॉ-मटीरियल है, तो फिर पावर जनरेशन कैसे बढ़ेगी? महोदय, मैं माननीय विद्युत मंत्री जी से यह दरख्वास्त करना चाहूंगा कि आप यह नारा जरूर लगाइए कि *हम होंगे कामयाब एक दिन* । अगर आप यह नारा लगाएंगे, तो निश्चित तौर पर आप एक दिन जरूर कामयाब होंगे। महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर बिजली नहीं है, तो पटवन भी नहीं होगा। अगर बिजली नहीं है, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर जब ऑपरेशन करेगा, तो बिजली गायब होगी। उस टाइम पेशंट के मरने के चांसेज़ ज्यादा होते हैं। मैं देख रहा हूं कि समय ज्यादा हो रहा है और मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि आप एक नारा जरूर लगाइए तथा हम सब लोग भी मिलकर नारा लगाएंगे कि *हम होंगे कामयाब एक दिन।*

(समाप्त)

श्री श्रीगोपाल व्यास (**छत्तीसगढ़**) : उपसभापति महोदय, मैं वैसे तो इलैक्ट्रिकल इंजीजिनयर हूं और मैं माननीय मंत्री जी से बहुत सी बातें कह सकता हूं, किंतु मुझे मालूम है कि समय कम है, तो मुझे अपने राज्य के साथ ही न्याय करना पड़ेगा, As इलैक्ट्रिकल इंजीनियर फिर कभी बात करेंगे। मुझे यहां पर मेरे राज्य ने चुनकर भेजा है। मुझे आज ही छत्तीसगढ़ के लोगों से जो जानकारी मिली है, उसके आधार पर मैं माननीय मंत्री जी को स्मरण दिला रहा हूं कि मध्य प्रदेश के बाहर जो जल विद्युत परियोजनाएं थीं, उनमें से तीन सौ मेगावाट का आवंटन होना था, केवल पांच ही हो रहा है। इस ओर जो कुछ उनका समाधान हो सकता है, आप वह अवश्य कीजिए। उनका यह भी कहना है कि केन्द्र के द्वारा उनके कोटे में कई प्रकार की कटौतियां की गई हैं। आप इसको बेहतर तरीके से जानते हैं। मैं जानता हूं कि आप सभी लोगों के साथ बैठते हैं, बातचीत करते रहते हैं। इसलिए आप उनके जरिए न्याय दीजिए, इतना ही मेरा कहना है।

आप अकेले हैं और मुझे आपके साथ संवेदना है। आपके साथ कम से कम कोयला मंत्री और पर्यावरण मंत्री जी को जरूर बैठना चाहिए था। यह तो आप भी जानते हैं कि सारी

समस्याएं वहां पर जाकर अटक जाती हैं। मैं अपने क्षेत्र के बारे में जानता हूं कि हमारे यहां दो प्रोजेक्ट्स हैं, एक हसदेव अंकोला क्षेत्र का 1320 मेगावाट का और वहीं का एक 1000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, वे इसलिए अटके हैं, जो उनको कोयला क्षेत्र से कोयला मिलना चाहिए, उसकी अनुमति नहीं मिल रही है तथा पर्यावरण के अटकाव भी हैं। इसलिए मैं यह सोचता हूं कि जैसा कि किसी ने पहले भी कहा था और मैं भी उसको आवश्यक समझता हूं कि कुल मिलाकर विचार होना चाहिए। कुल मिलाकर प्रोडक्शन के कितने सोर्सेज हैं और कुल मिलकाकर कहां से अड़चनें आ रही हैं। इसमें बहुत बड़ा वजन है। यह ठीक है कि आपका मंत्रालय केवल पावर का है और आप केवल हाईडल स्टेशन्स या थर्मल स्टेशन्स की बातों पर ही विचार करेंगे। कुल मिलाकर जब देश की आवश्यकता पर विचार करते हैं, तो इस बात में बहुत बड़ा बल है कि इसका कुल विचार कहीं न कहीं होना चाहिए। हमने सोलर मिश◌ान बनाया है, यद्यपि सोलर का मंत्रालय दूसरा है।

(क्रमशः 3R/LP पर)

LP-PB/3r/5.20

श्री श्रीगोपाल व्यास (क्रमागत) : ..किन्तु देश की आवश्यकता को पूरा ध्यान में रखकर, कहां-कहां क्या करना है, इसके बारे में विचार करने की भी मैं बहुत आवश्यकता अनुभव करता हूं। महोदय, ग्राम विद्युतीकरण की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना देश में चल रही है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि हमारे यहां के जो जिले हैं, लगभग सोलह जिले हैं, उसमें से दो जिलों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जसपुर और कोरबा की, छत्तीसगढ़ की, आपके मंत्रालय में पेंडिंग है, कृपा करके उसे क्लियर करा दीजिए, उसके कारण हम 283 ग्रामों तक बिजली नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जिसका परिणाम यह भी हुआ है कि लगभग 90 हजार बीपीएल परिवारों तक जो बिजली पहुंचाई जानी चाहिए थी, वह भी हम अभी तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इन दो जिलों का, जो काम कहीं अटका होगा, आप कृपा करके उसे ठीक करा दीजिए। हमारे यहां पर, छत्तीसगढ़ में लगभग 4550 एम.ओ.यू. साइन किए गए हैं। माननीय

मंत्री जी, मुझे याद है, आपने ही पिछली बार कहा था कि आने वाले कुछ वर्षों में छत्तीसगढ़ सचमुच बहुत अधिक पावर जनरेट करेगा और मुझे यह कहने में खुशी है कि छत्तीसगढ़ के बारे में नक्सलवाद और अन्य वाद तथा आपने बहुत कुछ सुना है, मगर मुझे जो जानकारी है, उसके आधार पर, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि इस देश में छत्तीसगढ़ वह राज्य है, जहां पर 365 दिन और 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। यह स्थिति बनी रहे, उसमें माननीय मंत्री जी हमारी मदद करेंगे, ऐसी हमारी आपसे आशा है। मंत्री जी, सार्वजनिक कंपनियों को जो काम दिया गया है, सारे सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, उनके काम का जो एफिशिएंसी सूचकांक मुझे मिला है, वह बहुत चिंताजनक है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सारे जिलों के जो प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं, ...शायद खेल मंत्री जी को पावर चाहिए, जो सार्वजनिक उद्यम हैं, जैसे एन.एच.पी.सी. है, एन.टी.पी.सी. है, पावर ग्रिड वगैरह हैं, इन सब की एफिशिएंसी का जो सूत्र मुझे प्राप्त हुआ है, मुझे उससे बहुत चिंता हो रही है, यह 2.46 से लेकर 21.93 है। यदि इतने प्रतिशत इनकी एफिशिएंसी है, तो हमारे यहां इन जिलों में कब विद्युत मिलेगी, मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। मेरी आपसे प्रार्थना है, आपका जो कुछ भी माध्यम है, आप इन सारे सार्वजनिक उपक्रमों के साथ बैठकर, हमारे छत्तीसगढ़ प्रांत में जो स्थिति है, उसको बनाए रखें। इतना ही नहीं, मुझे खुशी होगी, अगर हम अपने आस-पास के प्रांतों में भी बिजली सप्लाई करने में समर्थ होंगे। आपने पिछली बार अपना जो आशीर्वाद दिया था, उन कुछ कठिनाइयों का आपके सामने अनुरोध करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं। उपसभापति जी, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं और अपना स्थान लेता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समाप्त)

SHRI TIRUCHI SIVA (TAMIL NADU): Thank your, Mr. Deputy Chairman, Sir, for having given me this opportunity.

Sir, the when the fact cannot be concealed that there is a continuing power shortage in the country, the fact that the Government is taking some initiatives cannot also be ignored.

Sir, the National Electricity Policy announced in the year 2005 had the following objectives:

- Demands for power to be fully met by 2012.
- Supply of reliable and quality power of specified standards in an efficient manner and at reasonable rate.
- Each household to get a minimum of one unit per day by 2012.
- Electricity sector to be made financially viable; and
- Protection of consumers' interests.

Sir, coming to the first point, when the demand for power has been planned to be fully met by 2012, the capacity addition charges in the Eleventh Five Year Plan had envisaged a capacity of addition of 78,000 MW, of which 19.9 per cent was hydro power and 76 per cent was thermal and the rest nuclear. Thermal and hydro both constitute about 96 per cent and only 4 per cent is nuclear. But after the initiation taken by the UPA Government, I think, the nuclear power generation will increase in the due course. Sir, the year-wise target set under the Plan was subsequently revised downward.

Sir, while appreciating the Government's initiatives and the interest, I would like to know from the Minister the reasons for this downward revision. For example, the original target in the year 2007-08 was 16335, the achievement was 9263.

(Contd. by 2s/SKC)

3s/5.25/skc

SHRI TIRUCHI SIVA (Contd.): The percentage achieved was 56.7. In the year 2008-09, only 31.2 per cent was achieved, while in 2009-10, it is 43.9 per cent. All put together, it was 45.6 per cent. The Government has envisaged that by 2012 the need would be fully met, but we have achieved a target of only 45.6 per cent. According to the Economic Survey, 2009-10, the major reasons for not achieving targets were delayed supplies of material and shortage of skilled manpower for construction and commissioning of projects. Sir, this is very odd. A country with so much potential of manpower gives shortage of skilled manpower as a reason for delayed construction and commissioning of projects. How could this be addressed? Why has this not been addressed? The other reasons are contractual disputes between project authorities, contractors, sub-vendors and shortage of fuel.

Sir, the Economic Advisory Council to the Prime Minister has suggested that sources of fuel should be diversified, particularly with respect to natural gas, using both domestic and imported natural gas and liquefied natural gas. I would like to know the Ministry's position in this regard. The Ministry has some policy measures.

Sir, the norm for transmission and distribution losses is 10-15 per cent whereas in actuality, it is 25 per cent. What plans does the Ministry have to reduce this loss and bring it to the actual norm that we need to adopt? Then, there are

policy measures allowing entry of private players into all aspects of the power sector, generation, transmission and distribution and unbundling, that is, separation of generation, transmission and distribution into different entities, allowing for entry of more than one player in each respect and setting up independent, autonomous regulatory commissions. What is the status in this regard? Have these policy measures been initiated by the Government? If so, what is the status and what is the achievement after implementation of these policy measures?

Sir, the Electricity Act also talks something about formulation of a national electricity policy and tariff policy -- each State to establish a regulatory commission to determine tariffs and arbitrate disputes. Also, the Act includes various norms for the benefit of consumers. There are other policy measures, especially, increasing the manufacturing capacity of BHEL, Bharat Heavy Electricals Limited, and liberalization of mega power policy. If BHEL, a profit-earning PSU of the country, is not able to meet the supply of machineries to power projects, which is most essential, the Ministry could coordinate with the Ministry of Heavy Industries and others to see if the problem could be rectified. Everyone talks about how power is a major necessity in the country, now as well as in the future, to compete with the world, but the reasons stated here for not achieving the targets are very simple. I think the Ministry's coordination and its initiatives could rectify all these problems. Then, sixty-one per cent of the villages were to be covered under the RGGY scheme for rural electrification by 15th February, 2010. The Government gave the following reasons for delays in progress

under RGGY: Delays in forest clearance, delays in issuance of road permit and way bills in some States, very poor rural electricity infrastructure in some States, delay in finalization of BPL by some States, delay in taking decisions on various State and local taxes, and so on. As my friend, Mr. Khuntia has pointed out, the States' responsibility increases in certain aspects. As far as my State, Tamil Nadu, is concerned, Sir, we have done very well. I hope, the hon. Minister would appreciate the progress achieved in Tamil Nadu. By 2011, we would increase power generation by more than 7000 megawatts. The wind power generation now in Tamil Nadu equals the total nuclear power generated across the country. Thus, by 2011, Tamil Nadu would not only be self-sufficient, it would also be able to spare something for the nearby States. So, as far as our State is concerned, we comply with the requirements expected of a State Government and Tamil Nadu would do the best. The present situation that is being faced across the country is not so pronounced in Tamil Nadu. I would like to tell this august House that in this federal structure of ours, States have equal responsibility. While moving forward with the UPA government, not only as a partner but also as a responsible State, Tamil Nadu is doing very well in power generation and other aspects as well. In future, the country's demands would be met satisfactorily and the Minister's initiatives would do very well.

(Ends)

(Followed 3t/sch)

Sch/5.30/3t

श्री मंगल किसन (उड़ीसा): डिप्टी चेयरमैन सर, पावर डिपार्टमैंट के द्वारा 60,751.42 करोड़ रुपये की मांग की गई है। हर स्टेट में मैगा पावर प्लांट के लिए कुछ न कुछ कार्य हो रहा है या होने वाला है। इसमें बहुत बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। जिस स्टेट में पावर प्लांट लगते हैं और पावर प्रोड्यूस हाती है, उस स्टेट के बारे में भी भारत सरकार को कुछ सोचना चाहिए। भारत सरकार का पावर प्लांट जिस स्टेट में होता है, वहां से पूरी पावर किसी दूसरी स्टेट में चली जाती है। इन पावर प्लांट्स के कारण जिस स्टेट को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे एनवायरनमैंट या टैम्परेचर बढ़ने की समस्या, उस स्टेट को इसका कोई फायदा नहीं दिया जाता है। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि कम से कम 1%, 1.5% या 2% पावर उसी पावर प्रोड्यूसिंग स्टेट को अवश्य देनी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि जितने भी पावर प्लांट होते हैं, उनके चलते वहां का टेम्परेचर 4°C - 5°C बढ़ जाता है। हम लोगों के उड़ीसा में झारसुगुड़ा में तरह-तरह के प्लांट लगने के बाद, हर प्लांट में एक कैप्टिव पावर प्लांट बनाने की व्यवस्था की गई है, चाहे वह प्राइवेट सेक्टर में हो या पब्लिक सैक्टर में, जिसके कारण झारसुगुड़ा जैसे छोटे शहर का टैम्परेचर भी आज 46°C है। इसके कारण आज आम जनता का जीवन-यापन वहां बहुत कठिन हो गया है। इसलिए मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि जहां भी पावर प्लांट लगें, सरकार उनको बाध्य करे कि उस पावर प्लांट के चारों तरफ, कम से कम पांच या दस किलो मीटर के रैडियस में प्लांटेशन या पेड़ लगाने की व्यवस्था की जाए। इसके लिए सरकार के द्वारा उन्हें बाध्य किया जाना चाहिए, नहीं तो फ्यूचर में इन पावर प्लांट्स के चलते दुनिया का टेम्परेचर कम से कम 4°C -5°C अधिक होगा। मुझे उम्मीद है मंत्री महोदय और सरकार इस तरफ अवश्य ध्यान देंगे।

Rajiv Gandhi Rural Electrification Scheme के बारे में बहुत चर्चा की गई है। सरकार ने उस योजना के लिए पैसे का भी प्रावधान किया है और आज तक इस योजना के तहत 19,140.43 करोड़ रुपये बांटे गए हैं। मगर मैं समझता हूं कि खाली पैसा दे देने से ही

काम पूरा नहीं हो जाता। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए भारत सरकार के जितने भी नैशनल थर्मल पावर प्लांट हैं, इम्प्लिमेंटेशन के लिए इन्हें पब्लिक सैक्टर की एजेंसियों को दिया गया है, लेकिन पब्लिक सेक्टर एजेंसियों ने उसे सब-लीज़ करके प्राइवेट सेक्टर की एजेंसियों को दे दिया है। वे प्राइवेट सेक्टर की एजेंसियां न भारत सरकार के कंट्रोल में हैं, न स्टेट गवर्नमैंट के कंट्रोल में हैं और न ही वे किसी मॉनिटरिंग ऑफिसर की बात सुनती हैं, जिसके चलते आज हालत ऐसी है कि राजीव गांधी इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम के तहत त्रिपुरा, सिक्किम, मीज़ोरम, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश इत्यादि राज्यों में प्रोग्रेस अभी तक ज़ीरो है। मेघालय में अभी तक 6.90%, छत्तीसगढ़ में 7.95%, अरुणाचल प्रदेश में 10.66%, मध्य प्रदेश में 11.04%, मणिपुर में 13.27%, नागालैंड में 13.27%, असम में 18.51%, जम्मू-कश्मीर में 21.55%, उड़ीसा में 28.92%, कर्णाटक में 43.94% काम हुआ है।

(3u-psv पर जारी)

sch - PSV-KSK/3U/5.35

श्री मंगल किसन(क्रमागत): सर, इसका मतलब यह है कि जैसे उड़ीसा में 18 महीनों में Rajeev Gandhi Rural Electrification योजना complete होनी थी मगर उसे implementation के लिए sub-lease पर जिस प्राइवेट पार्टी ने लिया था वह 17 महीनों तक उड़ीसा नहीं आयी। कुछ काम शुरु नहीं किया। जब छान-बीन हुई तो 18 महीनों बाद उसने काम शुरू किया है। जब 18 महीनों में वह प्रोजेक्ट complete होना है, उसको 17 महीनों तक touch भी नहीं किया है। 18वें महीने में उसको start किया है। इस प्रकार Rajeev Gandhi Rural Electrification योजना में काम हो रहा है। सरकार का उद्देश्य महान है। उसने सारे पैसे भी दिए हैं, मगर implementation part में सरकार को ध्यान से उसकी monitoring करने के लिए कोई mechanism develop करनी चाहिए जिससे सरकार ने जो महान उद्देश्य रखा है वह सफल हो।

सर, दूसरी बात लोगों के displacement की है। कम-से-कम 4 हजार या 5 हजार एकड़ से कम में mega projects नहीं बन पाते हैं। इसके कारण जो families displaced हुई हैं उनके लिए RR package ठीक होना चाहिए। इसके साथ ही उनको compensation ठीक मिलनी चाहिए। जो displaced families हैं उनके कम-से-कम 2 generations को, not only one generation को, facility देनी चाहिए। उस क्षेत्र में जो कारखाना बनता है, वहाँ एक mechanism develop करके उन displaced families को उस कारखाने के कुछ shares उनके नाम पर मिलने चाहिए ताकि उस कारखाने का लाभ हर साल कुछ-न-कुछ हर displaced family को मिल सके। Displacement के कारण जो नियुक्ति पाते हैं, employment पाते हैं उन लोगों के बारे में सरकार का नियम है कि quarter से कारखाना जाने के दौरान यदि उनकी कोई casualty हुई तो उसको rehabilitation package में appointment देगी या कारखाने के अन्दर कुछ हो गया तो उनको appointment देगी ...(समय की घंटी)... या कारखाना आने के समय उन्हें कुछ हो गया तो appointment देगी, मगर छुट्टी के समय में वह market गया या कहीं कोई सामान लाने गया और वहाँ उसे कुछ हो गया तो within service में भी public sector में नियुक्ति नहीं मिलती है। इसीलिए सरकार को विचार करना चाहिए जिससे देश में हर displaced family में हर स्टेट में इसके लिए सबसे बड़ी discontentment होती है। इसके बारे में सरकार को विचार करना चाहिए। आपने मुझे इस पर बोलने के लिए जो समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

(समाप्त)

SHRI KUMAR DEEPAK DAS (ASSAM): Sir, sustainable economic growth is possible if the country is abound with natural resources like gas, crude oil, uranium, coal, or, even water. The most States of the North-Eastern Region can well be prime destinations for industrial growth in the country simply because this region is full of these resources.

For setting up of a hydro-electric power project, the State of Arunachal Pradesh is the best place, as it is richest in water resources. It has the potential of generating energy to the extent of staggering 50,328 MW. So far as exploration of hydro-electric power is concerned, nowadays, any promoter can generate power and can sell the same at a commercial price with a statutory minimum return on equity. The demand of power is also increasing rapidly in national and in the South East Asian market.

Power sector reforms in the country indicated a clear policy shift transforming the status of electricity service from an essential one to commercial. Both public and private sectors managed to get enough fund for investment in power sector. Till the other day, due to fund crunch, hydropower projects in the region were of the size of 50 MW and 100 MW. But, now, in the new situation, it is targeted to some 50,000 MW, together by the public and private sectors.

(continued by 3w - gsp)

GSP-DS/5.40/3W

SHRI KUMAR DEEPAK DAS (CONTD.): Sir, the main problem is arising now. Now, the problem in Assam, specifically with regard to the construction of big dam for hydel power generation, has led to statewide protests since long, and, has caused havoc in the downstream of the rivers. The projects are constructed without any holistic and transparent policy on the ecological, or, earthquake and flood control aspects.

After having acerbic experience of unprecedented floods caused by Ranganadi river in Assam, apprehension of the people against any hydel project

has been mounting. If the discharge from a mere 200 MW capacity plant on Ranganadi river during summer could create such a deluge, then, what would be the future plight of the people living in downstream when discharge commensurating with 50,000 MW hydropower is left through the gates of the concerned dam.

This is not a single issue. There are several issues which are lying without solution in our country like the issue of Tipaimukh dam. Thus, viewing the dam issue from a neutral, humane and global viewpoint, it is natural for Bangladesh to fear that the Tipaimukh Dam would wreak havoc on life and economy in that country, as we in India fear that a dam on Tsangpo and diversion of water towards North China could virtually transform Assam into a desert and at the same time, the same fear should also hold good for the people of Bangladesh in the event of Brahmaputra drying out.

Mr. Deputy Chairman, Sir, on the other hand, the entire North Eastern Region has fallen in seismically sensitive zone-V. Under these circumstances, before taking a decision with regard to proposing any venturous job in the form of any mega hydroelectric project in the upper reaches of Brahmaputra in Arunachal Pradesh, all we ought to do is to undertake comprehensive study with regard to its likely impacts on such factors.

The Centre does not seem to be committed to assiduously and meticulously conducting scientific and thorough studies and survey with regard to the downstream impacts of those dams. The Central Government should come forward with a policy paper on it to soothe people's ire against such development.

With these words, I thank you very much for giving me the opportunity to raise some issues concerning my region. Thank you once again.

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The discussion on the Working of the Ministry of Power is concluded. Now, the hon. Minister of Power to reply.

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिन्दे): उपसभापति महोदय, मैं आपका तो आभारी हूँ ही, इसके साथ ही सभी सदस्यों का भी आभारी हूँ। मैं नहीं समझता था कि 6 महीने के अंदर दूसरी बार इसी सदन में यह विषय चर्चा के लिए आएगा, लेकिन जब विषय चर्चा के लिए आ गया तो मुझे भी खुशी हुई।

इस सभा में जब भी चर्चा होती है तो मैं एक प्रेरणा लेकर अपने डिपार्टमेंट में जाता हूँ। मुझ पर टीका-टिप्पणी भी होती है तो उसका मैं आत्मचिन्तन करता हूँ और मेरे अधिकारी भी आत्मचिन्तन करते हैं। ऐसा हम कभी नहीं कहते कि अगर हमारे ऊपर टीका-टिप्पणी हो गयी तो उसको टोको। यह बात हम कभी नहीं कहते हैं, क्योंकि यह देश की चिन्ता का एक विषय है। जिस तरह से हमारी यूपीए-। सरकार आ गयी और दूसरी भी सरकार आ गयी, जिसने इस देश को 2012 तक सबको बिजली देने का एक आश्वासन दिया है, उसके लिए आप भी बड़े चिन्तित हैं कि यह काम कैसे हो सकता है? क्योंकि अभी तक तो इस देश में बिजली निर्माण का कोई काम ही नहीं हुआ था। आप थोड़ा आठवां, नौवां और दसवां प्लान देखिए। दसवें प्लान में तो हम थे, लेकिन आप Eighth-Ninth Plan में या Seventh Plan में भी देखिए कि हमने इस देश को कितनी बिजली दे दी। अभी एन.के. सिंह जी कह रहे थे कि हम देश में per capita 700 KW per hour बिजली का इस्तेमाल करते हैं जबकि अमरीका और चीन में इतनी है। मेरे पास सारे figurers हैं। मैंने इस हाउस में बहुत बार figures दी हैं, इसलिए मैं figures के झंझट में नहीं पड़ना चाहता हूँ।

(3x/AKA पर क्रमशः)

Aka-sk/3x/5:45

श्री सुशील कुमार शिन्दे (क्रमागत) : मैं यही बताना चाहता हूं कि शुरूआत में ही, 2004 में हमने इस देश को बताया था कि 2012 में हम इस देश के सभी घरों में बिजली देना चाहते हैं और देंगे और तब देश में एक हजार प्रति किलोवाट आवर्स बिजली देश के हर आदमी को मिल जाएगी, इस प्रकार का आश्वासन हमने देश में दिया था। उपसभापति जी, मैंने इसी सदन में बताया था कि 8वें, 9वें और 10वें प्लान में, तीनों प्लान्स को मिलाकर 56,000 मैगावाट बिजली इस देश में तैयार हुई। यह टारगेट प्लानिंग कमीशन देता है कि 56,000 मैगावाट बिजली तैयार होगी, 10वीं पंचवर्षीय योजना में 21,000 मैगावाट बिजली तैयार होगी, वह बात अलग है कि हम टारगेट 21,000 की बजाए 25,000 का ले लें, 30,000 का ले लें, 40,000 का ले लें। हमने जब चर्चा की तो हमने कहा कि यह एक चैलेंज था देश के लिए और हमारे डिपार्टमेंट के लिए भी एक चैलेंज था, 78,000 मैगावाट का चैलेंज हमने स्वीकार किया। लेकिन, जब हमने इस चैलेंज को स्वीकार किया था तो देश में पानी की स्थिति अच्छी थी। श्री शिवा जी ने बहुत अच्छा कहा कि difficulty जैसे आती है कि हमने 8वीं और 9वीं योजना में जब प्लान किया तो इस देश में पानी कम गिरा, जिसकी वजह से हाइड्रो का हमारा प्रोडक्शन कम हो गया। कोयले के बारे में भी उन्होंने कहा, मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस सारी स्थिति को जानते हुए कि देश में कोयले की भी शार्टेज है, तो परदेस से भी हमें कोयला मंगाना पड़ा, 12 मिलियन टन कोयला हमें परदेस से पिछले साल मंगाना पड़ा। तो ये सब difficulties आती रहीं। उपसभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा और फिगर्स बताने में मेरे से कहीं गलती न हो जाए, इसलिए मैं जरा ऑन दि रिकार्ड आना चाहता हूं । 9,585 megawatt of the capacity has been added during 2009-10. This is the highest capacity addition achieved in a single year during the last six decades. The second highest being 9,263 megawatt in 2007-08. Moreover, the projects with capacity of 1,082

megawatt have also been synchronized during 2009-10. However, this could not be included in the capacity addition achievement in accordance with new definition of commissioning of projects as this could not achieve full load by March 31st.

उपसभापति महोदय, पहली बात तो यह है कि हम जब फुल लोड पर आते हैं और बिजली जब ग्रिड में जाती है, तब से हम काउंट नहीं करते थे। यदि वह काउंट करते तो आज 30,000 मैगावाट से ऊपर बिजली जाती। हम पहले जो काउंट करते थे, कॉयल पर जब लोड आ गया तो हमारा काउंट होता था कि बिजली आ गई है, हमने यह definition बदल दी है। जब तक ग्रिड में बिजली नहीं आती, तब तक हम उसे मानते नहीं है और यह definition बदलने से भी उसमें टारगेट में थोड़ी कमी आई, यह भी मैं इस सभागृह को बताना चाहता हूं। The capacity addition of 22,302 megawatt has been achieved during the first three years of the Eleventh Plan. इन तीन सालों में हमने 22,000 मैगावाट बिजली का निर्माण किया है और 10वें प्लान में पांच साल में 21,000 मैगावाट का निर्माण हुआ था, अभी हमारे पास इस प्लान के दो साल बाकी हैं और जो टारगेट दिया है, वह भी मैं बताना चाहता हूं। यह बात सही है कि चर्चा होने पर एक मार्गदर्शन भी मिलता है, इसलिए मैं सभी बातें बताना चाहता हूं। The Eleventh Plan is higher than total capacity addition of 21,180 megawatt achieved during the Tenth Plan. A capacity addition target of 20,359 megawatt has been fixed for 2010-11 with the proposed capacity addition of 19,713 megawatts in 2011-12. That means 6,374 megawatt of capacity in the Eleventh Plan would be added which is nearly three times of the capacity added in the Tenth Plan.

(Contd. by ysr-3y)

NB/3Y/5.50

श्री सुशील कुमार शिन्दे (क्रमागत) : दसवें प्लान से तीन गुना कैपेसिटी बढ़ जाएगी और मैं इस सदन को assure करता हूं कि यह मैं confidence से कह रहा हूं कि हमने जो measurements ले लिए हैं, वह मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि दसवें प्लान में हमें जो भी दिक्कतें आईं, जैसे तिरुची शिवा जी ने कहा कि हमारी BHEL की एक ही फैक्टरी है और हम इतनी बड़ी कैपेसिटी का निर्माण कर रहे हैं। BHEL की कैपेसिटी केवल 5 से 6 हजार तक थी, अभी वह 10,000 हो गई है और 15,000 तक पहुंचेगी। हम देश में 78,000 मैगावाट बिजली का निर्माण करना चाहते हैं, तो उसके लिए कहां से इतनी manufacturing capacity आएगी? इस बारे में हमने सरकार से विचार-विमर्श किया। BHEL तो हमारी फैक्टरी है, उसको प्राथमिकता देते हुए, अभी देश में 4 private factories आ रही हैं, एक है - L&T के साथ MHI,जो जापान की कंपनी है, दूसरी - Bharat Forge के साथ ALSTOM आ रही है, तीसरी - Toshiba के साथ JSW आ रही है और चौथी - ANSALDO के साथ GB Engineering आ रही है तथा NTPC और Bharat Forge, पाइपलाइन का काम कर रहे हैं। जो इस सैक्टर में काम करते हैं, उनको मालूम है कि balance of plant सबसे ज्यादा दिक्कत का काम है। कई प्लांट खड़े हो जाते हैं, लेकिन उनको balance of plant नहीं मिलता था, कभी ash plant नहीं मिलता था। जनरेटर और बॉयलर तो उनको मिल जाता था, लेकिन यह काम नहीं होता था। इसलिए हमने इस पर ध्यान दिया और आप देखेंगे कि दसवीं पंचवर्षीय योजना में सबसे बड़ी गलती यह हुई थी कि हमने 42,000 मैगावाट का प्रोजेक्शन किया, लेकिन ऑर्डर्स केवल 21,000 मैगावाट के गए थे। इस वक्त हमने 11वें प्लान में सभी ऑर्डर्स पहले ही place कर दिए हैं और काम शुरू हो गया है। मुझे इस सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी हमारे 12वें प्लान का काम चालू है और आज तक 50,000 मैगावाट का काम चालू है। हमने यह measurement ले लिया है और देश को इसकी जरूरत है। देश में बिजली की बहुत जरूरत है। इसके लिए हमने मॉनीटरिंग यूनिट्स लगाई हैं। जैसा अभी कोश्यारी जी ने कहा, मैं उनको

बहुत धन्यवाद देता हूं कि BJP के होते हुए भी उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया, हमें सपोर्ट किया, इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। यह बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि वे जिस क्षेत्र से आते हैं, गंगोत्री पर काम रोका गया है, उनको पता है। मैं उनको इसलिए धन्यवाद दे रहा हूं, क्योंकि टिहरी में जो काम हो रहा था, उसमें उन्होंने हमारा साथ दिया है।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : वहां BJP की सरकार है।

श्री सुशील कुमार शिन्दे : अहलुवालिया जी, आप बुरा मत मानिए, आप साथ बैठे हैं।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : आपने कहा कि "BJP के होते हुए", वहां BJP की सरकार है और वह अपना कार्यक्रम चला रही है, लेकिन कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। यहां कोश्यारी जी ने सरकारी पक्ष रखा है।

श्री सुशील कुमार शिन्दे : अहलुवालिया जी, मुझे बताना पड़ेगा कि इनका absence वहां feel हो रहा है।

उपसभापति जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी जो सबसे बड़ी समस्या है, वह यह है कि पावर सैक्टर, Concurrent List में है। पावर जनरेशन की जिम्मेदारी स्टेट की है, लेकिन हम दसवें प्लान तक यह समझ रहे थे कि यह काम सेंटर का है। सेंटर का काम तो खाली power supplementation का है। हमने देश के सभी पावर मिनिस्टर्स की बैठकें बुलाई, चीफ मिनिस्टर्स की बैठकें बुलाईं और उनको टारगेट दे दिया कि आपको यह करना ही होगा। इस वजह से यह काम शुरू हो गया है। केवल इतना करके ही हमने नहीं छोड़ा है, हमने इसकी मॉनीटरिंग भी शुरू की है।

(3Z/VNK पर क्रमशः)

श्री सुशील कुमार शिन्दे (क्रमागत): हम यह मोनिटरिंग केवल पीएसयू पर ही नहीं करते हैं, बल्कि स्टेट लेवल के भी जो projects हैं, उनको भी मोनिटर करते हैं और प्राइवेट को भी मोनिटर करते हैं। आजकल, पन्द्रह दिन पहले हमने एनटीपीसी में सेन्ट्रल रूम बनाया है कि वहां हमारे हर यूनिट पर कैमरे लगे हुए हैं। वहां बैठ कर हम सब कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी एनटीपीसी ने हमारा जो हाइड्रो का प्रोजेक्ट ले लिया है, उस पर भी कैमरे लगाए हुए हैं और जो टनल बोरिंग मशीन अंदर जाता है ..(व्यवधान)..

श्री भगत सिंह कोश्यारी : मंत्री जी, कैमरे लगाए हैं या काम लगा रखा है।

श्री सुशील कुमार शिन्दे: नहीं, नहीं, काम भी लगा रखा है। यहां से रोज मानिटर करते हैं कि कितना टनल बोरिंग मशीन अंदर घुस गया है और कौन लोग काम करते हैं। हर रोज इसकी रिपोर्ट आती है। अब पहले वाली बात नहीं रह गई है। अभी यहां आपके आशीर्वाद से सुशील कुमार शिन्दे बैठा है और हमारे प्रधान मंत्री जी ने और सोनिया गांधी जी ने बिठाया है, मैं कहां गवर्नर था, वहां से खींच कर यहां लाया है, तो इसलिए मुझे देश की नौकरी करनी है। उसके लिए मुझे अच्छा रिजल्ट देना है और मैं देता रहूंगा। जिस confidence से मुझे लाया है, वह रिजल्ट मैं देते रहूंगा। ठीक है, कभी-कभी नेचर से, इधर-उधर से गलती होती है। मैं मोनिटरिंग की बात कर रहा था। अभी हर प्रोजेक्ट पर मोनिटरिंग हो रहा है। फिर Central Electricity Authority है, वहां एक मोनिटरिंग होता है। हमने monitoring panel लगाया है, उनमें हाइड्रो की दो हैं और थर्मल के दो हैं। ऐसे चार-पांच monitoring panel लगाए हैं, वे भी मोनिटर करते हैं।

तीसरा जो मोनिटरिंग यूनिट है, वह मेरे लेवल पर है। जहां देश के अभी तक के जितने सेक्रेटरीज, पावर मिनिस्ट्री थे, वे रिटायर हो गए हैं, कपूर से लेकर, पंडित से लेकर इन सभी को मैंने विनती की कि मैं गलती कर सकता हूँ, आप आइए और हमें सहयोग दीजिए। हर महीने इसकी मीटिंग होती है और मानिटरिंग होती है। इतनी रिजिड मोनिटरिंग अभी तक

कभी नहीं हुई थी। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से अभी हमारे एन.के.सिंह साहब ten point programme लेकर आए, यह बहुत ही अच्छा है, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने प्लानिंग कमीशन में काम किया है और भारत सरकार में सचिव रहे हैं, लेकिन जिस तरह से एपीडीआरपी का काम किया है, उन्होंने कहा है कि restructure एपीडीआरपी करना चाहिए। हमने restructure एपीडीआरपी किया है। इसमें हमने दो पार्ट किया है- पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में हमने डेटा बेस लाइन किया है, हम पूरे देश में इसके लिए पैसा दे रहे हैं। एक बार डेटा बेस आ जाएगा तो हमें पता चलेगा। पार्ट बी में maintenance वगैरह को करने का काम करेंगे, चेंज करने का काम करेंगे। हमने already इस तरह का restructure plan किया ही है। एपीडीआरपी जो स्कीम है, उससे जो T&D losses हैं, वे भी कम हो जाएंगे, क्योंकि एक बार पता चल जाएगा कि कहां से चोरी होती है। वह बेस लाइन से पता चल जाएगा और यही हमें अभी तक पता नहीं चल रहा था।

उपसभापति महोदय, मैं आपका थोड़ा सा समय ले लिया हूँ। मैं दूसरी बात यह बताना चाहता हूँ कि अभी तक प्राइवेट सेक्टर कभी भी इतनी जोर से नहीं आई थी। अभी इस देश में प्राइवेट सेक्टर इतनी जोर से आ गई है कि capacity addition of over 19,000 megawatt is likely to be added in the private sector during the current Plan which is nearly ten times the capacity added in the private sector in the Tenth Plan and 1.7 times of the aggregate capacity addition in the private sector during the last 15 years. In terms of the contribution to the total installed capacity, the share of the private sector has grown from four per cent in 1999 to 18 per cent as on today. The projects for 5,000 megawatt capacity are presently under construction by private developers. Further, private sector is likely to add about 60 per cent of the total capacity addition.

(Contd. By MP/4a)

श्री सुशील कुमार शिन्दे (क्रमागत) : उपसभापति जी, अभी-अभी उड़ीसा के हमारे सम्मानित सदस्य यहां अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के बारे में कह रहे थे। जब मैं 2006 में वहां गया था, उस वक्त हमारे पास अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की केवल संकल्पना थी और केवल पांच अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट हम करना चाहते थे। चार प्रोजेक्ट अभी तक हम competitive bidding में दे चुके हैं और सरगुजा का पांचवां प्रोजेक्ट online है। सात प्रोजेक्ट हम और कर रहे हैं और एक-एक प्रोजेक्ट 16,000 करोड़ का है और इससे 4000 मेगावॉट बिजली का निर्माण होने वाला है। मैं उड़ीसा को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अभी एक काम शुरू कर दिया है और दूसरा करने जा रहे हैं। कीमतों के बारे में मैं कहता हूं कि एक प्रोजेक्ट में, कृष्णापटनम में competition हो गया, जो turbine की कीमतें हैं, उसमें ज़रूर competition हो गया और 400 करोड़ मैंने बचा भी दिए। तो यह competition नहीं है, आखिर यह पैसा हमारा पैसा है, जनता का पैसा है, यह कौन बचाएगा? तो competition के लिए यह बहुत ज़रूरी है और यह अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, सब तैयारी करके ही हम bidding process में देते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अटका हुआ हो। एकाध का शुरुआत में हो गया था कि उसका थोड़ा सा environmental clearance होना था, लेकिन मुंड्रा का जो पहला प्रोजेक्ट था और फिर ससान का प्रोजेक्ट आ गया, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था, वह भी अब क्लीयर हो गया है और मैं इस सदन में बताना चाहता हूं कि जो अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स से 12वें प्लान में हमें बिजली आनी तय थी, मुझे इस सदन में बोलने में यह खुशी है कि जिस तरह से हम monitoring कर रहे हैं, दो अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट जो हैं, उनमें से एक टाटा का जो प्रोजेक्ट है, उसके दो युनिट्स अभी 11वें प्लान में आ रहे हैं और ससान का, जो रिलायंस का प्रोजेक्ट है, उसका एक युनिट अगले प्लान में आ रहा है और इसमें अभी तक हम best effort करके एचीव नहीं कर पाए हैं। जो 62,000 मेगावॉट में नहीं कर पाए हैं, वह best efforts करके हम करेंगे , क्योंकि हम यह भी नहीं कहना चाहते हैं कि हम केवल 62,000 मेगावॉट इस देश को देंगे, इसलिए

हम कह रहे हैं कि जिस तरह से हम monitoring कर रहे हैं, best efforts से हम वह काम करने का प्रयास करेंगे।

उपसभापति महोदय, जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर में लोग आ रहे हैं, उसके बारे में भी मैं आपको थोड़े से मालूमात देना चाहता हूं। Incremental flow of bank credit to power sector has increased by merely 300 per cent from Rs. 13,000 crore in April-November 2008 to Rs. 38,000 crore in April-November 2009. What is more encouraging is the fact that the total incremental bank credit to the power sector accounts for over 50 per cent in 2009.

The comprehensive monitoring mechanism, वह तो मैंने कहा कि यह इतना encouraging है कि हमारे प्राइवेट सेक्टर में जब ये आएंगे, आज तो मेरे पास इतनी पी.डी. आ रही हैं और मैं सोलर के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारे एन.टी.पी.सी. की एक सब-कमेटी सोलर का काम कर रही है, तो इतने applications आ रहे हैं, मुझे भी अचरज हो रहा है कि देश में जैसे एक तरह का तूफान आ गया है कि किसको दें और किसको न दें? यह खुशी की बात है कि एक confidence बना हुआ है। आपने कभी देखा था कि एक साल में किसी कॉरपोरेट बॉडी के 5 IPO or FPO कभी निकले थे? तो इसका मतलब यह है अहलुवालिया जी कि जो credibility department को आ रही है, इसकी भी थोड़ी सी कभी चर्चा करनी चाहिए, appreciate करना चाहिए। आप businessman हो, तो आपको तो इसकी जानकारी .... (व्यवधान)...

श्री उपसभापति : क्या वे businessman हैं?

श्री एस.एस.अहलुवालिया : आप मुझे ज़बर्दस्ती businessman बना रहे हैं। क्या ख्वाब में देख लिया?

श्री सुशील कुमार शिन्दे : क्या करें सर, ये हमारे साथ यहां बैठते थे, अब वहां चले गए।

श्री एस.एस.अहलुवालिया : आप गलती से कह गए। संतोष बागड़ोदिया जी businessman हैं, जिन्होंने यह debate initiate की है। वे businessman हैं, हमें आपने businessman कहां से बना दिया?

श्री सुशील कुमार शिन्दे : ठीक है, मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे दोस्त जहां भी जाएं, बहुत active रहते हैं, इसलिए हमें खुशी है।

उपसभापति जी, मैं शॉर्ट में कहना चाहता हूं कि मैं बात तो बहुत कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास मालूमात बहुत हैं।

(4B/SC पर क्रमशः)

-MP/SC/6.05/4B

श्री सुशील कुमार शिन्दे (क्रमागत) : यहां पर पॉवर कंज़रवेशन के बारे में हमारे साथी श्री सैयद अज़ीज़ पाशा ने बहुत अच्छी बात की - पाशा जी चले गए हैं। पॉवर कंज़रवेशन के संबंध में हम जो अवॉयडेड कैपेसिटी की बात कहते हैं, 4,600 अवॉयडेड कैपेसिटी हमने अभी बचाई है और यह बचाकर हम यह इस देश को बता रहे हैं। हर तरफ से हम बिल्डिंग कोड लाए और बचत लैम्प का काम किया है। ये जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, वे पूरे देश में ऐसे कंपीटिशन में भाग लेते हैं। उसमें हम उन्हें एक लाख का, पचास हजार का प्राइज़ देते हैं। इस प्रकार से बिजली बचाने के लिए हम एक कंपीटिशन करते हैं और हमारे एम्बेसेडर वह काम करते हैं। कंज़रवेशन के लिए यह बहुत बढ़िया चीज़ है। आज सुबह ही एक प्रश्न के संबंध में हम सोलर सिस्टम में जो कॉस्ट बनती है, उसके संबंध में बात कर रहे थे। अभी प्रारम्भिक तौर पर एनटीपीसी की तरफ से हम जो सोलर सिस्टम कर रहे हैं, उसकी एक यूनिट की कॉस्ट 16 रुपए आती है। लेकिन अनऐलोकेटिड कोटा जो है, उसमें से हम मिक्सअप करके देना चाहते हैं। सोलर और अनऐलोकेटिड कोटा जो हमारी गवर्नमेंट के पास है, उसको मिक्स करके अगर हम दे देंगे तो बिजली की कीमत पांच या छः रुपए हो सकती है। रिलायबल बिजली के

संबंध में हमारे एन.के.सिंह साहब ने कहा। सस्ती और रिलायबल बिजली देने के संबंध में भारत सरकार की, डा0 मनमोहन सिंह जी की और यूपीए सरकार की पहली इंटेंशन है - चीपर बिजली, सस्ती बिजली और स्मूथ बिजली देना।

श्री एस.एस.अहलुवालिया : 16 रुपए बार-बार बोल रहे हैं।..(व्यवधान

श्री सुशील कुमार शिन्दे : बार-बार नहीं, एक ही बार बोला है।

श्री एस.एस.अहलुवालिया : सर, जैसे यूरोप में अभी शुरू हुआ है कि डोमेस्टिक यूज़ के लिए सोलर प्लांट अपने घर पर लगाइए। जितना यूज़ आप करते हैं, वह आप करिए और जो ज्यादा पैदा करते हैं, उसे आप ग्रिड में डाल दीजिए। उस ग्रिड से पॉवर कारपोरेशन उसको खरीदेगा और आपको पैसे देगा। जब आप सोलर फॉर्मिंग के लिए अलाऊ कर रहे हैं, सोलर फॉर्मिंग के लिए आपका नॉन कनवेंश्नल सोर्स ऑफ एनर्जी अलाऊ कर रहा है और वहां पर जो बिजली पैदा होगी, जैसे विंड फार्म में होती है, टाइडल फार्म में होती है, और यहां पर होती है, वह ग्रिड में जाएगी और ग्रिड से बिकेगी। इसी तरह से अगर कोई सोलर पॉवर अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए जेनरेट करता है, उसके अलावा जो बिजली पैदा हो रही है, उसको ग्रिड में लेकर उसको राहत दें तो शायद यह प्रचलन ज्यादा होगा और आपका थर्मल पॉवर का डोमेस्टिक यूज़ कम जाएगा और आप पॉल्यूशन से भी बचेंगे। इसलिए आप उसको सब्सिडी भी दीजिए। आप उसको ग्रिड में खरीदिए, हरेक आदमी माल बेचेगा।

श्री सुशील कुमार शिन्दे : ऐसे जो भी सजेशंस आ रहे हैं, उनको हम एग्ज़ामिन करेंगे और इन्हें हम जरूर लेंगे। ऐसे जो भी सजेशंस आ रहे हैं, उन्हें हम देख लेंगे। महोदय, कोश्यारी साहब रीहेब्लीटेशन के प्रोग्राम के बारे में कह रहे थे। हमने थोड़ी सी पॉलिसी हाइड्रो की बदल दी है। मैं बताना चाहता हूं कि जो प्रोजेक्ट अफेक्टिड फैमिलीज़ हैं, उनको हम दस साल के लिए महीने में 100 यूनिट फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली दे रहे हैं। उस बेचारे के 10,15,20 यूनिट लगते हैं। बाकी जो बिजली बचेगी, उसको वह बेच सकता है, ताकि उसको भी पैसा मिले, उसकी भी

कुछ कमाई हो जाए। इस प्रकार की स्कीम हमने निकाली है। इस प्रकार जो सजेशंस आपने दिए हैं, उनका हम जरूर ख्याल रखेंगे।

श्री भगत सिंह कोश्यारी : यहां पर यूनिट देना अलग विषय है। आदमी को तुरंत रहने के लिए जगह चाहिए, मकान चाहिए, बहुत ही ऐक्यूट प्रॉब्लम होती है। ..(व्यवधान)..

श्री सुशील कुमार शिन्दे: टिहरी में भी मैंने दो-तीन मीटिंग्स की हैं, आपको भी पता है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी : पूरे देश के बारे में बोलिए।

श्री सुशील कुमार शिन्दे : सर, मैं डिटेल में फिगर्स नहीं दूंगा..(व्यवधान)..

श्री एस.एस.अहलुवालिया : ओवरऑल पॉलिसी बता दीजिए।

श्री सुशील कुमार शिन्दे : हाइड्रो की पॉलिसी के बारे में तो मैंने बता दिया है। एक बात सही है कि यह जो पॉवर जेनरेशन का काम होता है, यह कमर्शियल बिज़िनेस है।

(4सी-एमसीएम पर क्रमश:)

SC-MCM/VK/4C/6-10

श्री सुशील कुमार शिन्दे (क्रमागत) : तो इसके बारे में मैं सहमत हूं कि यह हॉस्पिटल जैसे या दूसरे सार्वजनिक रूप से जो जगह लेते हैं, तो उसी तरह इसका काम नहीं होना चाहिए, भले ही शोलापुर में और नागपुर में अभी एन0टी0पी0सी0 की जो जमीन हमने ली है, जिस जगह की कीमत 50 हजार रुपए एकड़ थी, हमने कंसेंट टर्म से किसानों से बात करके जमीन ले ली और 5 लाख रुपए एकड़ उनको दे दिया। इससे वहां के लोग नाच रहे थे। इतना ही नहीं मैं यहां बताना चाहता हूं जिससे आप सब को खुशी होगी कि वह मजदूर जो किसान की उस जमीन पर काम करता है उसको भी 50 हजार रुपए का चैक हमने देना तय किया है और वहां चैक बांटे जा रहे हैं। जमीन के मालिक किसान को तो उसका पैसा मिल जाता है लेकिन उसके खेत में काम करने वाला जो गरीब आदमी है उसको कौन देखेगा? इसीलिए उसको 50 हजार का चैक हम दे रहे हैं। वह बैंक में जाकर उसको डिपोजिट करेगा तो उसको उस पर लोन मिलेगा और वहां वह टपरी लगाकर बैठेगा। इस तरह की भी हमने स्कीम बनाई है।

महोदय, हमने यह एक नई योजना ले ली है। यह अच्छी स्कीम हमने शुरू कर दी है। अभी व्यास जी मैन पॉवर की बात कर रहे थे। मैं बतलाना चाहूंगा कि हमने यह कम्पलसरी किया है, जो प्राइवेट हो या कोई भी हमारे स्टेट का हो या हमारी यूटीलिटी का हो, जो कोई भी प्रोजेक्ट लगाता होगा तो वहां उसको पहले ट्रेनिंग स्कूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि जहां नई जगह प्रोजेक्ट आता है, जगह लेने के बाद 5 साल लगते हैं प्रोजेक्ट आने के लिए और उस जगह जब यदि पहले महीने में ही जगह का फाउंडेशन होता है तो उसी वक्त टेक्नीकल स्कूल का फाउंडेशन हो जाए तो 6 महीने में उसका कंस्ट्रक्शन हो जाता है, अगले 6 महीने में बच्चा पढ़ना लगता है, तो दो बैचेज तैयार होते हैं 5 साल में। तो उस एरिया में रहने वाले जो लोग हैं उनको वहां पढ़ाना होगा, यह कम्पलसरी किया है और उन लोगों को ही वहां सर्विस में लेना होगा, यह भी हमने कम्पलसरी किया है और इसके लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी ऑथोरिटी ने सर्क्यूलर निकाला है और रेग्यूलेटरी ऑथोरिटी ने भी प्रोजेक्ट में इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट इनबिल्ट की है। तो हर किसी को यह काम करना पड़ेगा। अभी जो 8 लाख की मैन पॉवर की बात यहां कह रहे थे, तो इसी से ही मैन पॉवर खड़ा हो जाएगा, इसके लिए एक अच्छा प्रयास हमने इस देश में शुरू किया है। हम बहुत बार कहते हैं कि हमारे पास इतनी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की केपेसिटी है, जो आपने भी कहा कि एक लाख 50 हजार मेगावाट की है लेकिन अभी 36 हजार की हो गई है। लेकिन कितनी दिक्कतें हैं यह आप भी देख रहे हैं, उत्तराखंड छोटा सा राज्य है लेकिन इन सब डिफिकल्टियों को खत्म करके ही अभी हमने अरुणाचल में काफी प्रोजेक्ट दे दिए हैं और वहां काम शुरू हो गया है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, तवांग से लेकर काम शुरू कर दिया है, इस पर हम ज्यादा बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि फिर गड़बड़ी शुरू हो सकती है। हमारे डी0पी0आर0 तैयार थे और इससे अधिक काम शुरू कर दिए। वहां भी रि-हेबिलिटेशन पौलिसी लगाई है कि हमारी कॉमर्शियल कम्पनी है, क्योंकि वह बेचारा किसान वहां इतनी पीढ़ियों से खेती करता है और थोड़े से पैसे देकर हम उसकी जमीन मार्केट रेट नहीं देकर सरकारी रेट देकर लेंगे तो उसको नुकसान होता है।

इससे उसके दिल में क्या लगता होगा, यह भी हमें पता है। इसलिए हमने अपने सभी कारपोरेशंस से कहा है कि नेगोशिएटिंग बेसिस पर जमीन की खरीदारी करो, जिससे विरोध भी नहीं होगा और खुशी से लोग अपनी जमीन दे देंगे। इस प्रकार की भूमिका हम इस देश में चालू करना चाहते हैं। यह बात आपने बहुत अच्छी की कि यहां उत्तराखंड में टिहरी में जो काम आपने किया है, सहयोग दिया है, मैंने अभी मालूमात कर ली है कि फर्स्ट यूनिट दिसम्बर, 2010 में आ रही है।

(4d/GS पर क्रमशः)

श्री सुशील कुमार शिन्दे (क्रमागत): और बाकी 2011 में सभी हो जाएगा। टिहरी में पम्प स्टोरेज भी है, उसके बारे में भी अभी सुप्रीम कोर्ट के आर्डर हो गए हैं, उस पर भी चर्चा चल रही है और वह भी जल्दी हो जाएगा। लोहारी नागपाला के लिए जैसा आपके दिल में दर्द है, वैसा ही मेरे दिल में दर्द है, महोदय जी, क्या करें, उस पर 400 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, 500 मेगावाट बिजली वहां पैदा करनी है। कई निवेदन आ चुके हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, वहां पर थोड़ा आंदोलन हो गया, तो उन्होंने कहा कि हमें यहां तक पानी चाहिए, तो हमने कहा कि यहां तक क्यों मैं यहां तक देता हूं, मैं गले तक पानी देता हूं, सरल धारा की तरह पानी देता हूं। वे एक बार तैयार हो गए, उनके सिग्नेचर हो गए, मैं परदेश जा रहा था, तो फिर उसके बीच में आंदोलन शुरू हो गया और फिर से काम रुक गया । अभी हमारे सामने दिक्कत यह है कि यदि पूरा काम रोकना है, तो जो टनल पांच-छह किलोमीटर अंदर गए हैं, उनको बंद किया, तो क्या होगा ? हिल की लाइन बहुत सेंसेटिव होती है। हमारे सामने यह दिक्कत की बात है, इसलिए हमने आईआईटी के दो प्रोफेसर्स लगाए हैं - एक दिल्ली के हैं और एक वेस्ट बंगाल के हैं। वे इसको देख रहे हैं कि इन टनल को बंद किया तो क्या हो सकता है और बंद नहीं किया, तो क्या करना चाहिए? हमारी एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमेटी है, वह भी इसको देख रही है। यदि आप सहयोग दें, जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके बारे में मदद करें, तो अच्छा रहेगा। हम लोगों के मन में भी गंगा के लिए बहुत श्रद्धा है, सरलता से पानी आने के लिए हम लोग भी सहयोग देने के लिए तैयार हैं। लेकिन गंगोत्री से पानी नीचे आने के लिए हमारा कंस्ट्रक्शन का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, इसके बाद हम वहां पर करना नहीं चाहते हैं। जब भावना का सवाल आता है, तब भावना से यह सरकार खेलना नहीं चाहती है। यह हमारी नीति है, प्रधान मंत्री जी की नीति है, हमारी यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी की नीति है कि भावना से खेलने का काम नहीं करना है। जिस तरह से हम आत्म-चिंतन कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जैसे लोग जिस तरह आंतरिक इच्छा से बोल रहे हैं कि क्या

तकलीफें होती हैं, हमारी नदियां तो सुविधा देने के लिए होती है, यह ठीक है कभी भावना से संबंध होता है, अगर आप इसमें सहयोग देते हैं, तो यह अच्छी तरह से हो जाएगा।

श्री विक्रम वर्मा जी मध्य प्रदेश के बारे में बहुत चिंतित हैं, मैं जब भी उनका भाषण सुनता हूं, तो मैं भी चिंतत हो जाता हूं। वह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बारे में कहते हैं। मैं हमेशा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मदद देने के लिए तैयार रहता हूं। हमें बिजली सब तरफ से चाहिए। बिजली निर्माण के लिए जहां-जहां भी जरूरत होगी, मैं मदद देने के लिए, सहयोग देने के लिए हमेशा तैयार हूं और इसके लिए आपके दिल में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। चक्रवर्ती जी, आप अभी नहीं थे, अभी हमारे खूंटिआ जी कह रहे थे कि करीब दस-पन्द्रह साल से कामगारों का, मजदूरों का प्रश्न निलम्बित था, वह कैसे छोड़ दिया, उसके बारे में उन्होंने बताया था। आप नहीं थे, मुझे तो मालूम नहीं है, आप वह प्रश्न मेरे सामने नहीं लाए, नहीं तो मैं उनको हल करवा देता। अगली बार कभी हो, तो जरूर लाना, मैं आपके साथ हूं। ठीक है, कभी ऐसा हो जाता है, इन्सान को मालूम नहीं होता है कि कौन किस तरह का है ?। remained as Labour Minister, and I was also a part of the Labour Movement...

SHRI S.S. AHLUWALIA: I am still a labourer.

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: I am also still a labourer, and I am producing. You do not have to ask me what!

उपसभापति महोदय, पार्ट बी में जो APDRP की हमारी स्कीम है, फर्स्ट मैंने बेस लाइन के बारे में बोला है, कम्प्युटराइज बेस लाइन कहा है और पार्ट टू में MNO का जो काम हम कर रहे हैं, उसमें हमने यह निर्णय ले लिया है कि जो हिल स्टेशन हैं, जो रिलीजियस प्लेसिस हैं, ऐसी जगहों पर जहां ऊपर से वायरिंग जाती है, हमने सोचा कि यह स्कीम अभी आई है, तो यह ट्रांसमिशन लाइन जमीन के नीचे से क्यों न दी जाए। इस तरह की स्कीम हमने बनाई है और आज मैं अनाउंस करने जा रहा हूं कि हर जगह पर APDRP Part-2 में हमने इस स्कीम को

लागू करना तय किया है और इसके लिए पैसा दिया जाएगा। यह अंडर ग्राउंड वायरिंग के लिए है।(4ई/एएससी पर जारी)

ASC-TDB/4E/6.20

श्री सुशील कुमार शिन्दे (क्रमागत) : हमने यह प्रयोग गोवा में किया है और अब हम यह प्रयोग वहां पर करना चाहेंगे,जहां पर Religious places हैं और tourist places हैं, क्योंकि देखने में अच्छा नहीं लगता है। मैं आज एक दूसरी स्कीम और एनाउंस करना चाहता हूं क्योंकि आप लोग आज दिनभर यहां बैठे हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम तो शहर में बैठे हैं और बार-बार बिजली जा रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो हमारा अपना सब-स्टेशन है, उसमें खराबी आ गई थी और उसकी वायर जल गई थी। इसी वजह से यहां पर बिजली में प्रॉब्लम हो रही थी। डिस्ट्रीब्यूशन का वर्क तो भारत सरकार नहीं करती है, बल्कि हर स्टेट करती है, लेकिन अभी यह करेक्ट किया है। सब डीज़ल पर ही चला रहे थे । अब आपको यह सुविधा देना तय किया है। हमने कहा है कि पार्लियामेंट के एरिया में तो यह दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम इसके लिए भी प्रिकॉशन लेंगे।

महोदय, हमारे बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट एक जगह है और हम उससे बाहर निकलते हैं, तो उससे आधार किलोमीटर या उससे कम किलोमीटर की दूरी पर जाने के बाद अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ता है। जहां पर हमारा प्रोजेक्ट है, वहां पर काफी रोशनी होती है, उजाला ही उजाला होता है और वहां से निकलने के बाद अंधेरा ही अंधेरा होता है। इसलिए हमने यह निर्णय भी ले लिया है कि पांच किलोमीटर के periphery में पूरी बिजली दी जाएगी और BPL को फ्री कनेक्शन दिया जाएगा। हम स्टेटों को यह बिजली दे देंगे और उसकी देखभाल उन्हीं को करनी होगी। अभी हमने पांच किलोमीटर की शुरुआत की है। हमें राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण का टार्गेट भी दिया गया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि BPLमें और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण में इस साल के लिए जो हमें टार्गेट दिया

गया था, हमने वह क्रॉस कर दिया है। हमने उस टार्गेट से भी ज्यादा पांच परसेंट किया है और मुझे आपको यह बताने में खुशी होती है। अभी तक हमने 78 हजार किया है। यह टोटल 118 है और जो हमारे पास काम बचा है, उस काम को डबल करने के लिए हमने कहा है। उड़ीसा में हमारे कॉरपोरेशन को यह काम दिया था, उन्होंने दूसरे लोगों को दे दिया और वह काम कैंसिल करने के लिए कहा है तथा दूसरों को तुरंत देने के लिए कहा है। उसका जो 18 महीने का पीरियड है, उसे कम करने को कहा है। आप चिंतित न हों, इसलिए मैं आपको यह बता रहा हूं। महोदय, मैंने अपने एक दोस्त से कहा था कि मैं 15 मिनट में खत्म करुंगा, लेकिन यह विषय ऐसा है कि मुझे बोलना पड़ता है। इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन एक transmission के बारे में बोलूंगा। जो हमारा Power Grid है, आज इस देश में उसका एक अलग नाम हो गया है। अभी तो हमने उस Power Grid की चारों तरफ से connectivity की है। हमने उसको साउथ से वैसे तो किया है। Synchronised power connectivity जिसको बोलते हैं, वह अभी साल डेढ़ साल में साउथ से कर देंगे। यदि उसको एक बार किया तो फिर उसकी power capacity उधर से, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर आज भी जाती है, लेकिन उस वक्त फ्लो और जोर से चालू हो जाएगा। हमने इस तरह का एक प्रावधान करने का काम किया है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि जब अमेरिका के पावर ग्रिड में प्राब्लम आ गई, तो हमारे पावर ग्रिड के चेयरमैन को वहां पर एडवाइज़ देने के लिए बुलाया था। अभी यह भारत की कैपेसिटी बढ़ी है, इसलिए मैं इस सदन में यह बता रहा हूं।

एक आखिर बात कह कर मैं समाप्त करता हूं। हमारे माननीय प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह जी ने civil nuclear power के बारे में सरकार की परवाह न करते हुए, जिस तरह का निर्णय लिया तथा इस देश को clean power देने का जो प्रयास किया है, उसका तो अभी एग्रीमेंट होता आ रहा है, मेरे ख्याल में उस पर साल-डेढ़ साल में काम शुरू होने में दिक्कत नहीं होगी। देश में हम जो climate change की बात कर रहे हैं, जो Civilian

Nuclear Deal हो गई है, उससे भी हमें जल्द से जल्द अच्छी तरह की बिजली मिल जाएगी। आप सब लोग बड़ी इच्छा शक्ति के साथ साथ दे रहे हैं। ...(व्यवधान)..

(4F/LP पर आगे)

-ASC/LP-KGG/6.25/4F

श्री विक्रम वर्मा : उसे एजुकेटिड करने के लिए जो इंजीनियर्स, टेक्नीशियन्स चाहिए, की तैयारी भी अभी से कीजिए, अन्यथा, वह भी अमरीका से बुलाना पड़ेगा, विदेश से लेना पड़ेगा। आप उसके साथ यह भी कार्य करें।

श्री सुशील कुमार शिन्दे : उसकी जरूरत नहीं है। मेरे साथी, चव्हाण जी डिपार्टमेंट देखते हैं, मैंने भी कई प्रोजेक्ट्स पर जाकर देखा है, जब काकोदकर जी थे, अभी नहीं हैं, काकोदकर जी के साथ, जो सवाल आपने किया है, वह मेरे भी दिल में आया था, मैंने भी पूछा था, लेकिन हमारे पास इतने एक्सपर्टाइज लोग हैं, इसलिए चिंता की बात नहीं है। शुरूआत में हमें थोड़ी दिक्कत लगेगी। जैसे बिहार की बात है, बाड का प्रोजेक्ट है, पटना में, बाड का प्रोजेक्ट करीब चार-पांच साल से बंद था, क्योंकि वहां पर एक रशियन मशीनरी Texpro के साथ और एन.डी.पी. के साथ डिस्प्यूट का निर्माण हो गया था। हमने उसका भी समझौता कर दिया है, वहां अभी रशियन टीम गई है और वहां पर टर्बाइन का काम अभी शुरू हो रहा है। चक्रवर्ती जी, मैं कल सुबह वहां साढ़े पांच बजे जाकर विजिट कर रहा हूं। मैं बाड़ जा रहा हूं और यहां मैं पक्का साढ़े ग्यारह बजे आऊंगा। मैं इतनी जल्दी जाकर आऊंगा, क्योंकि उनके साथ यह मसला चार साल से रुका हुआ है। हम जो स्लिप्पेज जैसा बोलते हैं, That project was on Eleventh Plan. But, because of some dispute, we have to undergo such a delay. और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं जब भी इस सभाग्रह में आता हूं, अपने डिपार्टमेंट के लिए

एक शक्ति लेकर जाता हूं। आप सभी लोगों ने मेरा जो साथ दिया है, मैं उसका आभारी हूं। चक्रवर्ती जी, मैं शुरूआत में भाषण कर रहा था, I hope you understand Hindi.

SHRI SHYAMAL CHAKRABORTY: Yes, I do. But, please say something about Damodar Valley Corporation.

SHRI SUSHIL KUMAR SHINDE: Yes, I will tell you about it. It is good that you have reminded me. I personally went three times to Damodar Valley. I have visited and I have laid the foundation stone.

SHRI SHYAMAL CHAKRABORTY: Please meet the affected people.

SHRI SUSHIL KUMAR SHINDE: You see, there are disputes. I have been asking a second office in Jharkhand. I have laid the foundation stone. But, the land is not being given there. So, you have to help me to speed up the work.

SHRI SHYAMAL CHAKRABORTY: We are ready to help you, Sir. With regard to West Bengal, I would request the Chief Minister.

SHRI SUSHIL KUMAR SHINDE: When you talk of Damodar Valley, it comes under West Bangal and Jharkhand.

श्री एस.एस.अहलुवालिया : वह वैली झारखंड में है।

श्री सुशील कुमार शिन्दे : वे बोल रहे हैं कि नहीं है।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : बराकर और मैथान के बॉर्डर पर वह है।

श्री सुशील कुमार शिन्दे : आप दोनों तय कीजिए, अपना तो कुछ नहीं है।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : सर, वह झारखंड के किनारे पर है, उसका हिस्सा है। हम लोग दामोदर के किनारे पले-बढ़े हैं।

SHRI SUSHIL KUMAR SHINDE: Tamil Nadu is doing good और मुझे तमिलनाडु का भी अभिनन्दन करना होगा। उपसभापति जी, बहुत दिनों से यू.एम.पी.पी. अल्ट्रा मेगा पावर

प्रोजेक्ट रुका हुआ था, अभी आपने चैन्नोर (?) में जगह दे दी है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वह भी दूर हो जाएगी। उपसभाति जी, कितने काम हैं, मैं आपको बताऊं कि हम लोग भारत में तो काम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ परदेस में भी पावर ग्रिड काम कर रहा है, एन.टी.पी.सी. काम कर रहा है। कहीं श्रीलंका में काम कर रहे हैं, तो कहीं साउथ अफ्रीका में काम कर रहे हैं। भारत के विंग बहुत दूर-दूर जा रहे हैं, आपको इसका भी अभिनन्दन करना होगा। अभी हमारे साथ बहुत अच्छा बोल रहे थे कि हम एक दिन कामयाब होंगे, इसी पांच साल में हम कामयाब होंगे। हम सभी मिलकर बोलेंगे कि भारत एक बहुत ताकतवर देश है और उसके साथ हम पावर लेकर चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिन्द।

(समाप्त)

श्री राजनीति प्रसाद : उपसभापति जी..(व्यवधान)..

श्री उपसभापति : अभी छोड़िए, आज इतना ही, इतने विस्तार से इतना अच्छा रिप्लाई दिया है। The House is adjourned to meet at 11 a.m. tomorrow.

The House then adjourned at thirty minutes past six of the clock till eleven of the clock on Tuesday, 20th April, 2010.